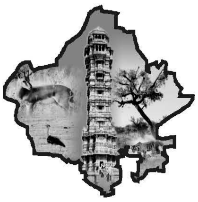


राजस्थान अध्ययन

भाग–1

कक्षा–9

संयोजक एवं लेखक

डॉ. हरि मोहन सक्सेना
से. नि. संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
बी–1, एम.बी.एस.नगर, कोटा जंक्शन, **कोटा**

लेखक गण

डॉ. हुकम चन्द जैन
विभागाध्यक्ष, इतिहास
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कोटा

डॉ. ओम प्रकाश शर्मा
वरिष्ठ व्याख्याता
आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, **सवाई माधोपुर**

बद्री नारायण मिश्रा
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
कोठियां (भीलवाड़ा)

प्रेम स्वरूप शर्मा
व्याख्याता
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
रामगढ़ (अजमेर)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्रकाशक
राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय – 1

राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एक परिचय

राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है, जिसमें विविधता के साथ निरन्तरता है। परम्पराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओत–प्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ की मिट्टी का कण–कण यहाँ के रणबांकुरों की विजयगाथा बयान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राणों की आहूति दी। कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पुरा सम्पदा का अटूट खजाना है। कहीं पर प्रागैतिहासिक शैलचित्रों की छटा है, तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण हैं। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान, तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास। कहीं समय का ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के, तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक। उपासना स्थल, भव्य प्रासाद, अभेद्य दुर्ग एवं जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों एवं उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रणक्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यहाँ लोकपरक सांस्कृतिक चेतना अत्यन्त गहरी है। मेले एवं त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रचे –बसे हैं। लोकनृत्य एवं लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक हैं। राजस्थानी चित्रशैलियों में श्रृंगार सौन्दर्य के साथ लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है।

राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्म स्थली रही है। यहाँ कालीबंगा, आहड़, बैराठ, बागौर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिन्धुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ, जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती है। इन सभ्यता–स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ बागौर जैसे स्थल मध्यपाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा जैसे विकसित सिन्धुकालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ। वहीं आहड़, गणेश्वर जैसी प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यताएँ भी पनपीं।

आर्य और राजस्थान

मरुधरा की सरस्वती और दृषद्वती जैसी नदियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरणस्थली रही है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियाँ कालान्तर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। इन्द्र और सोम की अर्चना में मन्त्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन–मुक्ति का ज्ञान आर्यों को सम्भवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल (बीकानेर), मरुकान्तार (मारवाड़) आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे, जो आर्यों की यादव शाखा से सम्बन्धित थे।

जनपदों का युग

आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है, जहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएँ अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती हैं। सिकन्दर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, शिवि तथा अर्जुनायन जातियाँ, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आयीं और सुविधा के अनुसार यहाँ बस गयीं। इनमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का शिवि जनपद, अलवर का शाल्व जनपद प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त 300 ई. पू. से 300 ई. के मध्य तक मालव, अर्जुनायन तथा यौधेयों की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। मालवों की शक्ति का केन्द्र जयपुर के निकट था, कालान्तर में यह अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गये। भरतपुर–अलवर प्रान्त के

अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के यौधेय भी एक शक्तिशाली गणतन्त्रीय कबीला था। यौधेय संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुये थे, जो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट है।

लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी के काल में राजस्थान के केन्द्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार था, परन्तु यौधेय तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के ह्रास के चिह्न दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतन्त्रों को समाप्त नहीं किया, परन्तु इन्हें अर्द्ध–आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतन्त्र हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाये और अन्ततः छठी शताब्दी आते–आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतन्त्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त हो गई।

मौर्य और राजस्थान

राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बैराठ का शिलालेख तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र सम्प्रति द्वारा बनवाये गये मन्दिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबन्ध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद का बनवाया हुआ है। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राज मान का, जो मौर्यवंशी माना जाता है, वि. सं. 770 का शिलालेख कर्नल टॉड को मिला, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये चार नाम क्रमशः दिये हैं। कोटा के निकट कणसवा (कसुंआ) के शिवालय से 795 वि. सं. का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है।

हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नये जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने–अपने राज्य स्थापित कर लिये थे, इसमें मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के गुहिल, सांभर के चौहान, आमेर के कछवाहा, जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख हैं।

शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि छठी शताब्दी में मण्डोर के आस–पास प्रतिहारों का राज्य था और फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांभर में चौहान राज्य की स्थापना हुई और धीरे–धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। पांचवीं या छठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भू–भाग में गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। दसवीं शताब्दी में अर्थूणा तथा आबू में परमार शक्तिशाली बन गये। बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दी के आस–पास तक जालौर, रणथम्भौर और हाड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया परन्तु उसका कहीं–कहीं विघटन भी होता रहा।

नामकरण

वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। इसके भिन्न–भिन्न क्षेत्र अलग–अलग नामों से जाने जाते थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में 'जांगल देश' कहलाता था। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को 'जंगलधर बादशाह' कहते थे। जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपादलक्ष (वर्तमान अजमेर और नागौर का मध्य भाग) कहलाता था, जिस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग शूरसेन देश के अन्तर्गत था। भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग शूरसेन देश के अन्तर्गत थे। शूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा, मत्स्य राज्य की विराटनगर और कुरु राज्य की इन्द्रप्रस्थ थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम 'शिव' था, जिसकी राजधानी 'मध्यमिका' थी। आजकल 'मध्यमिका' (मज्झमिका) को नगरी कहते हैं। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिस कारण इसे मेदपाट अथवा प्राग्वाट भी कहा जाने लगा। डूँगरपुर, बाँसवाड़ा के प्रदेश को वॉगड़ कहते थे। जोधपुर के राज्य को मरु अथवा मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरत्रा कहते थे

और सिरोही के हिस्से को अर्बुद (आबू) देश कहा जाता था। जैसलमेर को माड तथा कोटा और बूँदी को हाड़ौती पुकारा जाता था। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालव देश के अन्तर्गत गिना जाता था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भू–भाग को आजकल हम राजस्थान कहते है, वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1800 ई. में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रान्त के लिए 'राजपूताना' नाम का प्रयोग किया था। प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ई. में अपनी पुस्तक 'एनल्स एण्ड एण्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान' में इस राज्य का नाम 'रायथान' अथवा 'राजस्थान' रखा। जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो इस राज्य का नाम 'राजस्थान' स्वीकार कर लिया गया।

प्राचीन सभ्यताएँ

राजस्थान और प्रस्तर युग

राजस्थान में आदिमानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ अथवा उसके क्या क्रिया–कलाप थे, इससे संबंधित समसामयिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, परन्तु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों अथवा उनकी सहायक नदियों के किनारों से प्राप्त हुये हैं। चित्तौड़ और इसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह क्षेत्र इस काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केन्द्र रहा हो। लूनी नदी के तटों में भी प्रारम्भिक कालीन उपकरण प्राप्त हुये हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी सीढ़ी मध्य पाषाण एवं नवीन पाषाण युग है। आज से हजारों वर्षों से पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही। इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूनी तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों व दक्षिणी–पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेड़च और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्रचुर मात्रा में हुई है। बागौर और तिलवाड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। इनके अतिरिक्त अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनूं, कोटा, बूँदी, टोंक आदि स्थानों से भी नवीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुये हैं।

नवीन पाषाण युग में कई हजार वर्ष गुजारने के पश्चात् मनुष्य को धीरे–धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को स्थापित किया जाता है, परन्तु समयान्तर में जब ताँबा और पीतल, लोहा आदि का उसे ज्ञान हुआ तो उनका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का सम्पादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया और धातु से बने उपकरणों से वह अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगा।

कालीबंगा

यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती–दृषद्वती नदियों के तट पर बसा हुआ था, जो 2400–2250 ई. पू. की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के दो टीले प्राप्त हुये हैं। इनमें पूर्वी टीला नगर टीला है, जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टीला दुर्ग टीले के रूप में है। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। कालीबंगा से पूर्व–हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले है। पूर्व–हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो संसार में प्राचीनतम हैं। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियाँ तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में यहाँ घग्घर नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले है। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मुहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है, वह सैन्धव लिपि से मिलती–जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी

व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली हैं। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिन्धु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली तीन समाधियाँ मिली हैं। दुर्भाग्यवश, ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया, जिसका कारण संभवतः सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं।

आहड़

वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिण–पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केन्द्र था। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद थी। यह ताम्रवती नगरी अथवा धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बसी थी। विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्ती बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आस–पास ताँबे की अनेक खानों के होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहें और उसे एक ताम्रयुगीय कौशल केन्द्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 500 मीटर लम्बे धूलकोट के टीले से ताँबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियाँ आदि सामग्री प्राप्त हुई हैं।

अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में वृहत् परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तनों तथा उनके खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता है। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएँ मिली हैं। इनसे इतना तो स्पष्ट है कि उस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। इस बनास सभ्यता की व्यापकता एवं विस्तार गिलूंड, बागौर तथा अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित है। इसका संपर्क नवदाटोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि भागों की प्राचीन सभ्यता से भी था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन व कौशल की समानता से निर्दिष्ट होता है।

बैराठ

वर्तमान जयपुर जिले में स्थित बैराठ का महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से समीकरण किया जाता है। यहाँ की पुरातात्त्विक पहाड़ियों के रूप में बीजक डूँगरी, भीम डूँगरी, मोती डूँगरी इत्यादि विख्यात हैं। यहाँ की बीजक डूँगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का 'भाब्रू शिलालेख' खोजा था। इनके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर (गोल मंदिर) और अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी अवशेष मौर्ययुगीन हैं। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रान्ता मिहिरकुल ने बैराठ का विध्वंस कर दिया था। चीनी यात्री युवानच्वांग ने भी अपने यात्रा वृत्तान्त में बैराठ का उल्लेख किया है।

सभ्यता के अन्य प्रमुख केन्द्र

पाषाणकालीन सभ्यता के केन्द्र बागौर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के दो वृहद् समूह सरस्वती तथा बनास नदी के कांठे में पनपे थे, जिनका वर्णन ऊपर के पृष्ठों में किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान में अन्य कई महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहे हैं, जो इस युग के वैभव की दुहाई दे रहे हैं। गणेश्वर, खेतड़ी, दरीबा, ओझियाना, कुराड़ा आदि से प्राप्त ताम्र और ताम्र उपकरणों का उपयोग अधिकांश राजस्थान के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि में भी होता था। सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा, रेढ़ इत्यादि स्थलों से लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले है।

अतः सरस्वती–दृषद्वती, बनास, बेड़च, आहड़, लूनी इत्यादि नदियों की उपत्यकाओं में दबी पड़ी कालीबंगा, आहड़, बागोर, गिलूंड, गणेश्वर आदि बस्तियों से मिली प्राचीन वस्तुओं से एक विकसित और व्यापक संस्कृति का पता लगा है। ये सभ्यताएँ न केवल स्थानीय सभ्यता का

प्रतिनिधित्व करती थी, अपितु चित्रकला, भाण्ड–शिल्प तथा धातु संबंधी तकनीकी कौशल में पश्चिमी एशिया, ईराक, अफ्रीका आदि देशों की प्राचीन सभ्यताओं से सम्पर्क में थी।

पूर्व मध्यकालीन राजस्थान

इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना युद्धप्रिय राजपूत जाति का उदय एवं राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना है। गुप्तों के पतन के बाद केन्द्रीय शक्ति का अभाव उत्तरी भारत में एक प्रकार से अव्यवस्था का कारण बना। राजस्थान की गणतन्त्र जातियों ने उत्तर गुप्तों की कमजोरियों का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतन्त्र कर लिया। यह वह समय था, जब भारत पर हूण आक्रमण हो रहे थे। हूण नेता मिहिरकुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुँचायी और बिखरी हुई गणतन्त्रीय व्यवस्था को जर्जरित कर दिया। परन्तु मालवा के यशोवर्मन ने हूणों को लगभग 532 ई. में परास्त करने में सफलता प्राप्त की। इध ार राजस्थान में यशोवर्मन के अधिकारी जो राजस्थानी कहलाते थे, अपने–अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होने की चेष्टा कर रहे थे। किसी भी केन्द्रीय शक्ति का न होना इनकी प्रवृत्ति के लिए सहायक बन गया। लगभग इसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय हुआ। उसके तत्त्वावधान में राजस्थान में व्यवस्था एवं शांति की लहर आयी, परंतु जो बिखरी हुई अवस्था यहाँ पैदा हो गयी थी, वह सुधर नहीं सकी।

इन राजनीतिक उथल–पुथल के सन्दर्भ में यहाँ के समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है। राजस्थान में दूसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी तक विदेशी जातियाँ आती रहीं और यहाँ के स्थानीय समूह उनका मुकाबला करते रहे। परन्तु कालान्तर में इन विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई, इनमें कई मारे गये और कई यहाँ बस गये। जो शक या हूण यहाँ बचे रहे उनका यहाँ की शस्त्रोपजीवी जातियों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित होता गया और अन्ततोगत्वा छठी शताब्दी तक स्थानीय और विदेशी योद्धाओं का भेद जाता रहा।

राजपूतों की उत्पत्ति

राजपूताना के इतिहास के सन्दर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तों का अध्ययन बड़ा महत्त्व का है। राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया है। इस मत का प्रथम सूत्रपात **चन्दबरदाई** के प्रसिद्ध ग्रंथ **'पृथ्वीराजरासो'** से होता है। उसके अनुसार राजपूतों के चार वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुण्ड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किये गये। इस कथानक का प्रचार 16वीं से 18वीं सदी तक भाटों द्वारा खूब होता रहा। मुँहणोत नैणसी और सूर्यमल्ल मिसण ने इस आधार को लेकर उसको और बढ़ावे के साथ लिखा। परन्तु वास्तव में 'अग्निवंशीय सिद्धान्त' पर विश्वास करना उचित नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण कथानक बनावटी व अव्यावहारिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि चन्दबरदाई ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन चार वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबला हेतु स्वंय को सजग कर लिया। गौरीशकंर हीराचन्द ओझा, सी.वी.वैद्य, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया है।

गौरीशंकर हीराचन्द ओझा राजपूतों को सूर्यवंशीय और चन्द्रवंशीय बताते हैं। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिये हैं, जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से सम्बन्धि ात यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है।

राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार **कर्नल जेम्स टॉड** ने राजपूतों को शक और सीथियन बताया है। इसके प्रमाण में उनके बहुत से प्रचलित रीति–रिवाजों का, जो शक जाति के रिवाजों से समानता रखते थे, उल्लेख किया है। ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा इत्यादि हैं। टॉड की पुस्तक के सम्पादक विलियम क्रुक ने भी इसी मत का समर्थन किया है परन्तु इस विदेशी वंशीय मत का गौरीशंकर

हीराचन्द ओझा ने खण्डन किया है। ओझा का कहना है कि राजपूतों तथा विदेशियों के रस्मों–रिवाजों में जो समानता कर्नल टॉड ने बतायी है, वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की है, वरन् उनकी सात्यता वैदिक तथा पौराणिक समाज और संस्कृति से की जा सकती है। अतएव उनका कहना है कि शक, कुषाण या हूणों के जिन–जिन रस्मो–रिवाजों व परम्पराओं का उल्लेख समानता बताने के लिए जेम्स टॉड ने किया है, वे भारतवर्ष में अतीत काल से ही प्रचलित थीं। उनका सम्बन्ध इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है।

डॉ. डी. आर. भण्डारकर राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेत–हूणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पति को और बल देते हैं। इसकी पुष्टि में वे बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर और हूणों का वर्णन विदेशियों के सन्दर्भ में मिलता है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे, क्योंकि राजोर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। इनके अतिरिक्त भण्डारकर ने बिजौलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। वे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं और गुहिल राजपूतों की उत्पति नागर ब्राह्मणों से मानते हैं।

डॉ. ओझा एवं वैद्य ने भण्डराकर की मान्यता को अस्वीकृत करते हुए लिखा है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं है वरन् उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण है। जहाँ तक राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का प्रश्न है, वह भी निराधार है क्योंकि इस मत के समर्थन में उनके साक्ष्य कतिपय शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने मात्र से है।

इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपर्युक्त मतों में मतैक्य नहीं है। फिर भी डॉ. ओझा के मत को सामान्यतः मान्यता मिली हुई है। निःसन्देह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है।

पूर्व मध्यकाल में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय

प्रारम्भिक राजपूत कुलों में जिन्होंने राजस्थान में अपने–अपने राज्य स्थापित किये थे, उनमें मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार और राठौड़, सांभर के चौहान, तथा आबू के परमार, आम्बेर के कछवाहा, जैसलमेर के भाटी आदि प्रमुख थे।

I मेवाड़ के गुहिल – इस वंश का आदिपुरुष **गुहिल** था। इस कारण इस वंश के राजपूत जहाँ–जहाँ जाकर बसे उन्होंने स्वयं को गुहिलवंशीय कहा। गौरीशंकर हीराचन्द ओझा गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशीय मानते हैं, जबकि डी. आर. भण्डारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा ब्राह्मण थे।

गुहिल के बाद मान्य प्राप्त शासकों में **बापा** का नाम उल्लेखनीय है, जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉ. ओझा के अनुसार बापा इसका नाम न होकर कालभोज की उपाधि थी। बापा का एक सोने का सिक्का भी मिला है, जो 115 ग्रेन का था। अल्लट, जिसे ख्यातों में आलुरावल कहा गया है, 10वीं सदी के लगभग मेवाड़ का शासक बना। उसने हूण राजकुमारी हरियादेवी से विवाह किया था तथा उसके समय में आहड़ में वराह मन्दिर का निर्माण कराया गया था। आहड़ से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र नागदा था। गुहिलों ने तेरहवीं सदी के प्रारम्भिक काल तक मेवाड़ में कई उथल–पुथल के बावजूद भी अपने कुल परम्परागत राज्य को बनाये रखा।

II मारवाड़ के गुर्जर–प्रतिहार – प्रतिहारों द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग छठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। चूँकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुर्जरत्रा कहलाता था, इसलिए चीनी यात्री युवानच्वांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलो मोलो (भीनमाल) या बाड़मेर बताया है।

मुँहणोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें मण्डौर के प्रतिहार प्रमुख थे। इस

शाखा के प्रतिहारों का हरिश्चन्द बड़ा प्रतापी शासक था, जिसका समय छठी शताब्दी के आसपास माना जाता है। लगभग 600 वर्षों के अपने काल में मण्डौर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परम्परा को निभाकर अपने उदात्त स्वातन्त्र्य प्रेम और शौर्य से उज्ज्वल कीर्ति को अर्जित किया। जालौर–उज्जैन–कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से आरंभ होती है, जो इस वंश का प्रवर्तक था। उसे ग्वालियर प्रशस्ति में 'म्लेच्छों का नाशक' कहा गया है। इस वंश में भोज और महेन्द्रपाल को प्रतापी शासकों में गिना जाता है।

III आबू के परमार – 'परमार' शब्द का अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमार आबू के आस–पास के प्रदेशों में रहते थे। परन्तु प्रतिहारों की शक्ति के ह्रास के साथ ही परमारों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता चला गया। धीरे–धीरे इन्होंने मारवाड़, सिन्ध, गुजरात, वागड़, मालवा आदि स्थानों में अपने राज्य स्थापित कर लिये। आबू के परमारों का कुल पुरुष धूमराज था परन्तु परमारों की वंशावली उत्पलराज से आरंभ होती है। परमार शासक धंधुक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर वहाँ **विमलशाह** को दण्डपति नियुक्त किया। विमलशाह ने आबू में 1031 में आदिनाथ का भव्य मन्दिर बनवाया था। **धारावर्ष** आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। धारावर्ष का काल विद्या की उन्नति और अन्य जनोपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसका छोटा भाई प्रह्लादन देव वीर और विद्वान था। उसने 'पार्थ–पराक्रम–व्यायोग' नामक नाटक लिखकर तथा अपने नाम से प्रहलादनपुर (पालनपुर) नामक नगर बसाकर परमारों के साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाया। धारावर्ष के पुत्र सोमसिंह के समय में, जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामन्त था, वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गाँव में लूणवसही नामक नेमिनाथ मन्दिर का निर्माण करवाया था। मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मन्दिर बनवाकर अपनी कला के प्रति रुचि को व्यक्त किया। वागड़ के परमारों ने बाँसवाड़ा के पास अर्थूणा नगर बसा कर और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी शिल्पकला के प्रति निष्ठा का परिचय किया।

IV सांभर के चौहान – चौहानों के मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सपादलक्ष एवं जांगल प्रदेश के आस–पास रहते थे। उनकी राजधानी अहिच्छत्रपुर (नागौर) थी। सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष **वासुदेव** था, जिसका समय 551 ई. के लगभग अनुमानित है। बिजौलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांभर झील का निर्माता माना गया है। इस प्रशस्ति में चौहानों को वत्सगौत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामन्त थे परन्तु गुवक प्रथम, जिसने हर्षनाथ मन्दिर का निर्माण कराया, स्वतन्त्र शासक के रूप में उभरा। इसी वंश के चन्दराज की पत्नी रुद्राणी यौगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन एक हजार दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी।

1113 ई. में **अजयराज चौहान** ने अजमेर नगर की स्थापना की। उसके पुत्र अर्णोराज (आनाजी) ने अजमेर में आनासागर झील का निर्माण करवाकर जनोपयोगी कार्यों में भूमिका अदा की। चौहान शासक **विग्रहराज चतुर्थ** का काल सपादलक्ष का स्वर्णयुग कहलाता है। उसे वीसलदेव और कवि बान्धव भी कहा जाता था। उसने 'हरकेलि' नाटक और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने 'ललित विग्रहराज' नामक नाटक की रचना करके साहित्य स्तर को ऊँचा उठाया। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। जिस पर आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 'ढाई दिन का झोंपड़ा' बनवाया। विग्रहराज चतुर्थ एक विजेता था। उसने तोमरों को पराजित कर ढिल्लिका (दिल्ली) को जीता। इसी वंशक्रम में **पृथ्वीराज चौहान तृतीय** ने राजस्थान और उत्तरी भारत की राजनीति में अपनी विजयों से एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। 1191 ई. में उसने तराइन के प्रथम युद्ध में मुहम्मद गौरी को परास्त कर वीरता का समुचित परिचय दिया। परन्तु 1192 ई. में तराइन के दूसरे युद्ध में जब उसकी गौरी से हार हो

गई, तो उसने आत्म–सम्मान को ध्यान में रखते हुए आश्रित शासक बनने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवनपर्यन्त युद्धों के वातावरण में रहते हुए भी चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्ट किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात् भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं था कि इस युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई। लगभग आगामी एक शताब्दी तक चौहानों की शाखाएँ रणथम्भौर, जालौर, हाड़ौती, नाड़ौल तथा चन्द्रावती और आबू में शासन करती रहीं और राजपूत शक्ति की धुरी बनी रहीं। इन्होंने दिल्ली सुल्तानों की सत्ता का समय–समय पर मुकाबला कर शौर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया।

पूर्व मध्यकाल में पराभवों के बावजूद राजस्थान बौद्धिक उन्नति में नहीं पिछड़ा। चौहान व गुहिल शासक विद्वानों के प्रश्रयदाता बने रहे, जिससे जनता में शिक्षा एवं साहित्यिक प्रगति बिना अवरोध के होती रही। इसी तरह निरन्तर संघर्ष के वातावरण में वास्तुशिल्प पनपता रहा। इस समूचे काल की सौन्दर्य तथा आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजनाओं को जीवित रखा। चित्तौड़, बाड़ौली, आबू के मन्दिर इस कथन के प्रमाण हैं।

मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्ज्वल एवं गौरवशाली पक्ष

मध्यकाल में राजपूत शासकों और सामन्तों ने मुस्लिम शक्ति को रोकने की समय–समय पर भरपूर कोशिश की। राजपूतों द्वारा अनवरत तीव्र प्रतिरोध का सिलसिला मध्यकाल में चलता रहा। सत्ता संघर्ष में राजपूत निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सके। इसका मुख्य कारण राजपूतों में साधारणतः आपसी सहयोग का अभाव, युद्ध लड़ने की कमजोर रणनीति तथा सामन्तवाद था। यह सोचना उचित नहीं है कि राजपूतों के प्रतिरोध का कोई अर्थ नहीं निकला। राणा कुम्भा एवं राणा सांगा के नेतृत्व में सर्वोच्चता की स्थापना राजपूताने में ही सम्भव हो सकती थी। यह स्मरण रहे कि आगे चलकर राणा प्रताप, चन्द्रसेन और राजसिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। यद्यपि अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूताना के अधिकांश शासक उसके हितों की रक्षा करने वाले बन गये।

मध्यकालीन राजस्थान को बौद्धिक अधिसृष्टि से पिछड़ा मानना इतिहास के तथ्यों एवं अनुभवों के विपरीत होगा। जिस वीर प्रसूता वसुन्धरा पर माघ, हरिभद्रसूरी, चन्दबरदाई, सूर्यमल्ल मीसण, कवि करणीदास, दुरसा आढ़ा, नैणसी जैसे विद्वान लेखक तथा महाराणा कुम्भा, राजा रायसिंह, राजा सवाई जयसिंह जैसे प्रबुद्ध शासक अवतरित हुए हों, वह ज्ञान के आलोक से कभी वंचित रही हो, स्वीकार्य नहीं। जिस प्रदेश के रणबाँकुरों में राणा प्रताप, राव चन्द्रसेन, दुर्गादास जैसे व्यक्तित्व रहे हों, वह धरती यश से वंचित रहे; सोचा भी नहीं जा सकता।

'धरती धोरां री' का इतिहास अपने–आप में राजस्थान का ही नहीं अपितु भारतीय इतिहास का उज्ज्वल एवं गौरवशाली पहलू है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में गुहिल–सिसोदिया (मेवाड़), कछवाहा (आमेर–जयपुर), चौहान (अजमेर, दिल्ली, जालौर, सिरोही, हाड़ौती इत्यादि के चौहान), राठौड़ (जोधपुर और बीकानेर के राठौड़) इत्यादि राजवंश नक्षत्र भांति चमकते हुये दिखाई देते हैं।

गुहिल–सिसोदिया वंश

I मेवाड़ के इतिहास में तेरहवीं शताब्दी के आरंभ से एक नया मोड़ आता है, जिसमें चौहानों की केन्द्रीय शक्ति का ह्रास होना और गुहिल जैत्रसिंह जैसे व्यक्ति का शासक होना बड़े महत्त्व की घटनाएं हैं। मेवाड़ के गुहिल शासक **रत्नसिंह** (1302–03) के समय चित्तौड़ पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के इस आक्रमण के राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारणों के साथ रत्नसिंह की सुन्दर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने लालसा भी बताया जाता है। पद्मिनी की कथा का उल्लेख मलिक मुहम्मद जायसी के 'पद्मावत' नामक ग्रंथ में मिलता है। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रत्नसिंह और गोरा–बादल वीर गति प्राप्त हुये तथा पद्मिनी

ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर आत्मोत्सर्ग किया। इसी समय अलाउद्दीन ने 30,000 हिन्दुओं का चित्तौड़गढ़ में कत्ल करवा दिया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम खिज्राबाद कर दिया था। राजपूतों का यह बलिदान चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें गोरा–बादल की वीरता एक अमर कहानी बन गयी। आज भी चित्तौड़ के खण्डहरों में गोरा–बादल के महल उनके साहस और सूझ–बूझ की कहानी सुना रहे हैं। पद्मिनी का त्याग और जौहर व्रत महिलाओं को एक नयी प्रेरणा देता है। गोरा–बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आये तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्योछावर कर देश–रक्षा में लग जाना चाहिए।

रत्नसिंह के पश्चात् सिसोदिया के सरदार **हम्मीर** ने मेवाड़ को दयनीय स्थिति से उभारा। वह राणा शाखा का राजपूत था। **राणा लाखा** (1382–1421) के समय उदयपुर की पिछोला झील का बांध बनवाया गया था। लाखा के निर्माण कार्य मेवाड़ की आर्थिक स्थिति तथा सम्पन्नता को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए। लाखा के पुत्र मोकल ने मेवाड़ को बौद्धिक तथा कलात्मक प्रवृत्तियों का केन्द्र बनाया। उसने चित्तौड़ के समिधेश्वर (त्रिभुवननारायण मंदिर) मंदिर के जीर्णोद्धार द्वारा पूर्व मध्यकालीन तक्षण कला के नमूने को जीवित रखा। उसने एकलिंगजी के मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाकर, उस मंदिर की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की।

II मोकल के पुत्र **राणा कुंभा** (1433 –1468) का काल मेवाड़ में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए जाना जाता है। कुंभा को अभिनवभरताचार्य, हिन्दू सुरताण, चापगुरु, दानगुरु आदि विरुदों से संबोधित किया जाता था। राणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा (मांडू) के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने अपने आराध्यदेव विष्णु के निमित्त चित्तौड़गढ में नौ मंजिला प्रसिद्ध कीर्तिस्तंभ (विजयस्तंभ) का निर्माण करवाया। कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के उद्देश्य से 32 किलों का निर्माण करवाया था, जिनमें बसन्ती दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग प्रमुख हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊँचा भाग कटारगढ़ कहलाता है। कुंभाकालीन स्थापत्य में मंदिरों का बड़ा महत्त्व है। ऐसे मन्दिरों में कुंभस्वामी तथा श्रृंगारचौरी का मंदिर (चित्तौड़), मीरां मंदिर (एकलिंगजी), रणकपुर का मंदिर अनूठे हैं। कुंभा वीर, युद्धकुशल, कलाप्रेमी के साथ–साथ विद्वान एवं विद्यानुरागी भी था। एकलिंगमहात्म्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद्, व्याकरण, साहित्य, राजनीति में बड़ा निपुण था। संगीतराज, संगीत मीमांसा एवं सूड़ प्रबन्ध कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ थे। कुंभा ने चण्डीशतक की व्याख्या, गीतगोविन्द की रसिकप्रिया टीका और संगीत रत्नाकर की टीका लिखी थी। कुंभा का दरबार विद्वानों की शरणस्थली था। उसके दरबार में मण्डन (प्रख्यात शिल्पी), कवि अत्रि और महेश, कान्ह व्यास इत्यादि थे। अत्रि और महेश ने कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की रचना की तथा कान्ह व्यास ने एकलिंगमहात्य नामक ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार कुंभा के काल में मेवाड़ सर्वतोन्मुखी उन्नति पर पहुँच गया था।

III मेवाड़ के वीरों में **राणा सांगा** (1509–1528) का अद्वितीय स्थान है। सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहीम लोदी को पराजित कर अपनी सैनिक योग्यता का परिचय दिया। सांगा भारतीय इतिहास में हिन्दूपत के नाम से विख्यात है। राणा सांगा खानवा के मैदान में राजपूतों का एक संघ बनाकर बाबर के विरुद्ध लड़ने आया था परन्तु पराजित हुआ। बाबर के श्रेष्ठ नेतृत्व एवं तोपखानें के कारण सांगा की पराजय हुई। खानवा का युद्ध (17 मार्च, 1527) परिणामों की दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण रहा। इससे राजसत्ता राजपूतों के हाथों से निकलकर, मुगलों के हाथों में आ गई। यहीं से उत्तरी भारत का राजनीतिक संबंध मध्य एशियाई देशों से पुनः स्थापित हो गया। राणा सांगा अन्तिम हिन्दू राजा था, जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियाँ विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई। सांगा ने अपने देश के गौरव रक्षा में एक आँख, एक हाथ और टांग गँवा दी थी। इसके अतिरिक्त उसके शरीर के भिन्न–भिन्न भागों पर 80 तलवार

के घाव लगे हुये थे। सांगा ने अपने चरित्र और आत्मबल से उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने की क्षमता का अधिक महत्त्व है।

सांगा के पुत्र **विक्रमादित्य** (1531 –1536) के राजत्व काल में गुजरात के बहादुरशाह ने चित्तौड़ पर दो आक्रमण किये, जिसमें मेवाड़ को जन और धन की हानि उठानी पड़ी। इस आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य की माँ और सांगा की पत्नी हाड़ी कर्मावती ने हुमायूँ के पास राखी भेजकर सहायता मांगी परन्तु समय पर सहायता न मिलने पर कर्मावती (कर्णावती) ने जौहर व्रत का पालन किया। कुँवर पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र वणवीर ने अवसर पाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वह विक्रमादित्य के दूसरे भाई उदयसिंह को भी मारकर निश्चिन्त होकर राज्य भोगना चाहता था परन्तु **पन्नाधाय** ने अपने पुत्र चन्दन को मृत्यु शैया पर लिटाकर उदयसिंह को बचा लिया और चित्तौड़गढ़ से निकालकर कुंभलगढ़ पहुँचा दिया। इस प्रकार पन्नाधाय ने देश प्रेम हेतु त्याग का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका गान भारतीय इतिहास में सदियों तक होता रहेगा।

IV महाराणा **उदयसिंह** (1537 –1572) ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की थी। उसके समय 1567–68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था परन्तु कहा जाता है कि अपने मन्त्रियों की सलाह पर उदयसिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। इतिहास लेखकों ने इसे उदयसिंह की कायरता बताया है। कर्नल टॉड ने तो यहाँ तक लिखा है कि यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदयसिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्ज्वल होते। परन्तु डॉ. गोपीनाथ शर्मा की राय में उदयसिंह को कायर या देशद्रोही कभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने बणवीर, मालदेव, हाजी खाँ पठान आदि के विरुद्ध युद्ध लड़कर अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। अकबर से लड़ते हुये जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुये। अकबर ने चित्तौड़ में तीन दिनों के कठिन संघर्ष के बाद 25 फरवरी, 1568 को किला फतह कर लिया। अकबर द्वारा यहाँ कराये गये नरसंहार से आज भी उसका नाम कलंकित है। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि उसने आगरा किले के द्वार पर उन दोनों वीरों की पाषाण मूर्तियाँ बनवाकर लगवा दी।

V उदयसिंह के पुत्र **महाराणा प्रताप** का जन्म 9 मई, 1540 को कटारगढ़ (कुंभलगढ़) में हुआ था। प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर केवल पच्चीस वर्षो तक शासन किया लेकिन इतने समय में ही उन्होंने ऐसी कीर्ति अर्जित की जो देश–काल की सीमा को पार कर अमर हो गई। वह और उनका मेवाड़ राज्य वीरता, बलिदान और देशाभिमान के पर्याय बन गए। प्रताप को पहाड़ी भाग में 'कीका' कहा जाता था, जो स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है। अकबर ने प्रताप को अधीनता में लाने के अनेक प्रयास किये परन्तु निष्फल रहे। जहाँ भारत के तथा राजस्थान के अधिकांश नरेशों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, प्रताप ने वैभव के प्रलोभन को ठुकरा कर राजनीतिक मंच पर अपनी कर्त्तव्य परायणता के उत्तरदायित्व को बड़े साहस से निभाया। उसने अपनी निष्ठा और दृढ़ता से अपने सैनिकों को कर्तव्यबोध, प्रजा को आशावादी और शत्रु को भयभीत रखा।

अकबर मेवाड़ की स्वतन्त्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था और प्रताप उसकी रक्षा के लिए। दोनों की मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल न होना ही हल्दीघाटी के युद्ध (18 जून, 1576) का कारण बन गया। अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य ऐतिहासिक हल्दीघाटी (जिला राजसमंद) का युद्ध लड़ा गया। परन्तु इसमें मानसिंह प्रताप को मारने अथवा बन्दी बनाने में असफल रहा, वहीं प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक की पीठ पर बैठकर मुगलों को ऐसा छकाया कि वे अपना पिण्ड छुड़ाकर मेवाड़ से भाग निकले। यदि हम इस युद्ध के परिणामों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि पार्थिव विजय तो मुगलों को मिली, परन्तु वह विजय पराजय से

कोई कम नहीं थी। इतिहासकार डॉ. के. एस. गुप्ता की इस सन्दर्भ में टिप्पणी है कि "परिस्थितियों एवं परिणामों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हल्दीघाटी युद्ध में अकबर विजयश्री प्राप्त न कर सका।" महाराणा प्रताप को विपत्ति काल में उसके मन्त्री भामाशाह ने सुरक्षित सम्पत्ति लाकर समर्पित कर दी थी। इस कारण भामाशाह को दानवीर तथा मेवाड़ का उद्धारक कहकर पुकारा जाता है।

राणा प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खाँ को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया। प्रताप ने अपने जीवनकाल में चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप ने विभिन्न समय में कुंभलगढ़ और चावण्ड को अपनी राजधानियाँ बनायी थीं। प्रताप के सम्बन्ध में कर्नल जेम्स टॉड का कथन है कि "अकबर की उच्च महत्त्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन ये सब बातें दृढ़–चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्ज्वल रखने वाले दृढ़ साहस और कर्मठता को दबाने में पर्याप्त न थी। अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं, जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मेराथन है।" अतएव स्वतन्त्रता का महान् स्तंभ, सद्कार्यों का समर्थक और नैतिक आचरण का पुजारी होने के कारण आज भी प्रताप का नाम भारतीयों के लिए आशा का बादल है और ज्योति का स्तंभ है। स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान महाराणा प्रताप असंख्य भारतीय देशभक्तों के लिए स्वतन्त्रता के पुंज बने रहे।

प्रताप की मृत्यु (19 जनवरी, 1597) के पश्चात् उसके पुत्र **अमर सिंह** ने मेवाड़ की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए मुगलों से संधि करना श्रेयस्कर माना। अमरसिंह ने 1615 को जहाँगीर के प्रतिनिधि पुत्र खुर्रम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे जहाँगीर ने स्वीकार कर लिया। अमरसिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। संधि में कहा गया था कि राणा अमरसिंह को अन्य राजाओं की भांति मुगल दरबार की सेवा श्रेणी में प्रवेश करना होगा, परन्तु राणा को दरबार में जाकर उपस्थित होना आवश्यक न होगा।

VI महाराणा राजसिंह (1652–1680) ने मेवाड़ की जनता को दुष्काल से सहायता पहुँचाने के लिए तथा कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसिंह ने युद्ध नीति और राज्य हित के लिए संस्कृति के तत्त्वों के पोषण की नीति को प्राथमिकता दी। वह रणकुशल, साहसी, वीर तथा निर्भीक शासक था। उसमें कला के प्रति रुचि और साहित्य के प्रति निष्ठा थी। मेवाड़ के इतिहास में निर्माण कार्य एवं साहित्य को इसके समय में जितना प्रश्रय मिला, कुंभा को छोड़कर किसी अन्य शासक के समय में न मिला। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक से मैत्री सम्बन्ध बनाये रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर शत्रुता बढ़ा लेना राजसिंह की समयोचित नीति का परिणाम था।

कछवाहा वंश

I कछवाहा वंश राजस्थान के इतिहास मंच पर बारहवीं सदी से दिखाई देता है। उनको प्रारम्भ में मीणों और बड़गुर्जरों का सामना करना पड़ा था। इस वंश के प्रारम्भिक शासकों में **दुल्हैराय** व पृथ्वीराज बड़े प्रभावशाली थे जिन्होंने दौसा, रामगढ़, खोह, झोटवाड़ा, गेटोर तथा आमेर को अपने राज्य में सम्मिलित किया था। **पृथ्वीराज,** राणा सांगा का सामन्त होने के नाते खानवा के युद्ध (1527) में बाबर के विरुद्ध लड़ा था। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कछवाहों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। गृह कलह तथा अयोग्य शासकों से राज्य निर्बल हो रहा था। 1547 में भारमल ने आमेर की बागडोर हाथ में ली। **भारमल** ने उदयीमान अकबर की शक्ति का महत्त्व समझा और 1562 में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अकबर की यह बेगम मरियम–उज्जमानी के नाम से विख्यात हुई। भारमल पहला राजपूत था जिसने मुसलमानों (मुगल) से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये थे।

II भारमल के पश्चात् कछवाहा शासक **मानसिंह** अकबर के दरबार का योग्य सेनानायक था। रणथम्भौर के 1569 के आक्रमण के समय मानसिंह और उसके पिता भगवन्तदास अकबर के साथ थे। मानसिंह को अकबर ने काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में शामिल था तथा उसे अकबर ने 7000 मनसब प्रदान किया था। मानसिंह ने आमेर में शिलादेवी मन्दिर, जगतशिरोमणि मन्दिर इत्यादि का निर्माण करवाया। इसके समय में दादूदयाल ने 'वाणी' की रचना की थी।

मानसिंह के पश्चात् के शासकों में **मिर्जा राजा जयसिंह** (1621–1667) महत्त्वपूर्ण था, जिसने 46 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान उसे जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उसे शाहजहाँ ने 'मिर्जा राजा' का खिताब प्रदान किया। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को मराठों के विरुद्ध दक्षिण भारत में नियुक्त किया था। जयसिंह ने पुरन्दर में शिवाजी को पराजित कर मुगलों से संधि के लिए बाध्य किया। 11 जून, 1665 को शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरन्दर की संधि हुई थी, जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने मुगलों की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया। इस प्रकार पुरन्दर की संधि जयसिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता का एक सफल परिणाम थी। जयसिंह के बनवाये आमेर के महल तथा जयगढ़ और औरंगाबाद में जयसिंहपुरा उसकी वास्तुकला के प्रति रुचि को प्रदर्शित करते हैं। इसके दरबार में हिन्दी का प्रसिद्ध कवि बिहारीमल था।

III कछवाहा शासकों में **सवाई जयसिंह द्वितीय** (1700–1743) का अद्वितीय स्थान है। वह राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, खगोलविद्, विद्वान एवं साहित्यकार तथा कला का पारखी था। वह मालवा का मुगल सूबेदार रहा था। जयसिंह ने मुगल प्रतिनिधि के रूप में बदनसिंह के सहयोग से जाटों का दमन किया। सवाई जयसिंह ने राजपूताना में अपनी स्थिति मजबूत करने तथा मराठों का मुकाबला करने के उद्देश्य से 17 जुलाई, 1734 को हुरड़ा (भीलवाड़ा) में राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया। इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर आदि के शासकों ने भाग लिया था परन्तु इस सम्मेलन का जो परिणाम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान के शासकों के स्वार्थ भिन्न–भिन्न थे। सवाई जयसिंह अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से बूँदी के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर स्वयं वहाँ का सर्वेसर्वा बन बैठा, परन्तु बूँदी के बुद्धसिंह की पत्नी अमर कुँवरि ने, जो जयसिंह की बहिन थी, मराठा मल्हारराव होल्कर को अपना राखीबन्द भाई बनाकर और धन का लालच देकर बूँदी आमंत्रित किया जिससे होल्कर और सिन्धिया ने बूँदी पर आक्रमण कर दिया।

सवाई जयसिंह संस्कृत और फारसी का विद्वान होने के साथ गणित और खगोलशास्त्र का असाधारण पण्डित था। उसने 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर 'जीजमुहम्मदशाही' नाम रखा। उसने 'जयसिंह कारिका' नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। सवाई जयसिंह की महान् देन जयपुर है, जिसकी उसने 1727 में स्थापना की थी। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। नगर निर्माण के विचार से यह नगर भारत तथा यूरोप में अपने ढंग का अनूठा है, जिसकी समकालीन और वर्तमानकालीन विदेशी यात्रियों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। जयपुर में जयसिंह ने सुदर्शनगढ़ (नाहरगढ़) किले का निर्माण करवाया तथा जयगढ़ किले में जयबाण नामक तोप बनवाई। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में पाँच वेधशालाओं (जन्तर–मन्तर) का निर्माण करवाया, जो ग्रह–नक्षत्रादि की गति को सही तौर से जानने के लिए बनवाई गई थी। जयपुर के जन्तर–मन्तर में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 'सूर्य घड़ी' है, जिसे 'सम्राट यंत्र' के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। धर्मरक्षक होने के नाते उसने वाजपेय, राजसूय आदि यज्ञों का आयोजन किया। वह अन्तिम हिन्दू नरेश था, जिसने भारतीय परम्परा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ किया। इस प्रकार सवाई जयसिंह अपने शौर्य, बल, कूटनीति और विद्वता के कारण अपने समय

का ख्याति प्राप्त व्यक्ति बन गया था, परन्तु वह युग के प्रचलित दोषों से ऊपर न उठ सका।

राठौड़ वंश

I राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थापित थे। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ राजपूत प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर राज्य का मूल पुरुष **राव सीहा** था, जिसने मारवाड़ के एक छोटे भाग पर शासन किया। परन्तु लम्बे समय तक गुहिलों, परमारों, चौहानों आदि राजपूत राजवंशों की तुलना में राठौड़ों की शक्ति प्रभावशाली न हो पाई थी।

II राठौड़ शासक **राव जोधा** ने 1459 में जोधपुर बसाकर वहाँ मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। **राव गांगा** (1515–1532) ने खानवा के युद्ध में 4000 सैनिक भेजकर सांगा की मदद की थी। इस प्रकार सांगा जैसे शक्ति सम्पन्न शासक के साथ रहकर राव गांगा ने अपने राज्य का राजनीतिक स्तर ऊपर उठा दिया। **राव मालदेव** गांगा का ज्येष्ठ पुत्र था। वह अपने समय का एक वीर, प्रतापी, शक्ति सम्पन्न शासक था। उसके समय में मारवाड़ की सीमा हिण्डौन, बयाना, फतेहपुर–सीकरी और मेवाड़ की सीमा तक प्रसारित हो चुकी थी। मालदेव की पत्नी उमादे (जैसलमेर की राजकुमारी) इतिहास में 'रूठी रानी' के नाम से विख्यात है। मालदेव ने साहेबा के मैदान में बीकानेर के राव जैतसी को मारकर अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा को पूरी किया परन्तु मालदेव ने अपनी विजयों से जैसलमेर, मेवाड़ और बीकानेर से शत्रुता बढ़ाकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूँ मालदेव से सहायता प्राप्त करना चाहता था परन्तु वह मालदेव पर सन्देह करके अमरकोट की ओर प्रस्थान कर गया। मालदेव की सेना को 1544 में गिरि–सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध के पूर्व शेरशाह ने चालाकी का सहारा लेते हुये मालदेव के दो सेनापति जेता और कूंपा को जाली पत्र लिखकर अपनी ओर मिलाने का ढोंग रचा था। इस युद्ध में स्वामिभक्त जेता और कूंपा मारे गये तथा शेरशाह की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के पश्चात् शेरशाह ने कहा था ''एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए वह हिन्दुस्तान की बादशाहत खो देता।''

III मालदेव के पुत्र **चन्द्रसेन** ने जो एक स्वतन्त्र प्रकृति का वीर था, अपना अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया परन्तु अकबर की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की। वंश गौरव और स्वाभिमान, जो राजस्थान की संस्कृति के मूल तत्व हैं, वह हम चन्द्रसेन के व्यक्तित्व में पाते हैं। महाराणा प्रताप ने जैसे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार चन्द्रसेन भी आजन्म अकबर से टक्कर लेता रहा। चन्द्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने चन्द्रसेन के बड़े भाई **मोटा राजा उदयसिंह** को 1583 में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। इस प्रकार उदयसिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था। उदयसिंह ने 1587 में अपनी पुत्री मानबाई (जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण यह जोधाबाई भी कहलाती है) का विवाह जहाँगीर के साथ कर दिया। यह इतिहास में 'जगतगुसाई' के नाम से प्रसिद्ध थी। इसी वंश के गजसिंह का पुत्र अमरसिंह राठौड़ राजकुमारों में अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। आज भी इसके नाम के 'ख्याल' राजस्थान के गाँवों में गाये जाते हैं।

IV **जसवन्त सिंह** ने धर्मत के युद्ध (1658) में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से भाग लिया था परन्तु शाही सेना की पराजय ने जसवन्तसिंह को युद्ध मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। जसवन्तसिंह खजुआ के युद्ध (1659) में शुजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से लड़ने गया था परन्तु वह मैदान में शुजा से गुप्त संवाद कर, शुजा की ओर शामिल हो गया, जो उसके लिए अशोभनीय था। हालांकि वह जैसा वीर, साहसी और कूटनीतिज्ञ था, वैसा ही वह विद्या तथा कला प्रेमी भी था। उसने 'भाषा–भूषण' नामक ग्रंथ लिखा। मुँहणोत नैणसी उसका मंत्री था। नैणसी द्वारा लिखी गई **'नैणसी री ख्यात'** तथा **'मारवाड़ रा परगना री विगत'** राजस्थान की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के अनुपम ग्रंथ हैं।

जसवन्तसिंह मारवाड़ का शासक था जिसने अपने बल और प्रभाव से अपने राज्य का सम्मान बनाये रखा। मुगल दरबार का सदस्य होते हुए भी उसने अपनी स्वतन्त्र प्रकृति का परिचय देकर राठौड़ वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा बनाये रखी। राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवन्तसिंह के पुत्र **अजीतसिंह** को मारवाड़ का शासक बनाया। परन्तु अजीतसिंह ने अपने सच्चे सहायक और मारवाड़ के रक्षक, अदम्य साहसी वीर दुर्गादास को, जिसने उसके जन्म से ही उसका साथ दिया था, बुरे लोगों के बहकाने में आकर बिना किसी अपराध के मारवाड़ से निर्वासित कर दिया। उसकी यह कृतघ्नता उसके चरित्र पर कलंक की कालिमा के रूप में सदैव अंकित रहेगी।

दुर्गादास ने अपनी कूटनीति से औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लिया था। उसने शहजादा अकबर के पुत्र बुलन्द अख्तर तथा पुत्री सफीयतुनिस्सा को शरण देकर तथा उनके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके साम्प्रदायिक एकता का परिचय दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ एक चमकता हुआ सितारा है, जिससे इतिहासकार जेम्स टॉड भी प्रभावित हुये बिना नहीं रह सका। जेम्स टॉड ने उसे 'राठौड़ों का यूलीसैस' कहा है।

V जोधपुर के रावजोधा के पुत्र **राव बीका** ने 1488 में बीकानेर बसाकर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केन्द्र बनाया। बीका के पुत्र राव लूणकर्ण को इतिहास में 'कलयुग का कर्ण' कहा गया है। बीकानेर के जैतसी का बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष हुआ, जिसमें कामरान की पराजय हुई। 1570 में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में **राव कल्याणमल** ने अपने पुत्र रायसिंह के साथ भाग लिया। तभी से मुगल सम्राट और बीकानेर राज्य का मैत्री संबंध स्थापित हो गया। बीकानेर के नरेशों में **कल्याणमल** प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी।

VI महाराजा रायसिंह ने मुगलों की लिए गुजरात, काबुल और कंधार अभियान किये। वह अपने वीरोचित तथा स्वामिभक्ति के गुणों के कारण अकबर तथा जहाँगीर का विश्वास पात्र बना रहा। रायसिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण करवाया, जिस पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। रायसिंह स्वभाव से उदार तथा दानवीर शासक था। इसी आधार पर मुंशी देवीप्रसाद ने उसे 'राजपूताने का कर्ण' कहा है। बीकानेर महाराजा **दलपतसिंह** का आचरण जहाँगीर के अनुकूल न होने के कारण जहाँगीर ने उसे कैद कर मृत्यु दण्ड दिया था। महाराजा **कर्णसिंह** को 'जंगलधर बादशाह' कहा जाता था। इस उपाधि का उपयोग बीकानेर के सभी शासक करते हैं।

VII महाराजा **अनूपसिंह** वीर, कूटनीतिज्ञ और विद्यानुरागी शासक था। उसने अनूपविवेक, कामप्रबोध, श्राद्धप्रयोग चिन्तामणि और गीतगोविन्द पर 'अनूपोदय' टीका लिखी थी। उसे संगीत से प्रेम था। उसने दक्षिण में रहते हुए अनेक ग्रंथों को नष्ट होने से बचाया और उन्हें खरीदकर अपने पुस्तकालय के लिए ले आया। कुंभा के संगीत ग्रंथों का पूरा संग्रह भी उसने एकत्र करवाया था। आज अनूप पुस्तकालय (बीकानेर) हमारे लिए अलभ्य पुस्तकों का भण्डार है, जिसका श्रेय अनूपसिंह के विद्यानुराग को है। दक्षिण में रहते हुये उसने अनेक मूर्तियों का संग्रह किया और उन्हें नष्ट होने से बचाया। यह मूर्तियों का संग्रह बीकानेर के ''तैंतीस करोड़ देवताओं के मंदिर'' में सुरक्षित है।

VIII किशनगढ़ में भी राठौड़ सत्ता का पृथक् केन्द्र था। यहाँ का प्रसिद्ध शासक **सावन्त सिंह** था, जो कृष्ण भक्त होने के कारण 'नागरीदास' के नाम से प्रसिद्ध था। इसके समय किशनगढ़ में चित्रकला का अद्भुत विकास हुआ। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार 'निहालचन्द था, जिसने विश्व प्रसिद्ध 'बनी–ठणी' चित्र चित्रित किया।

चौहान वंश

I हम चौहानों के अधिवासन और प्रारम्भिक विस्तार के बारे में विगत पृष्ठों में अध्ययन कर चुके हैं। बारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में शाकम्भरी के चौहान शासक **पृथ्वीराज चौहान तृतीय** ने अपनी विजयों से उत्तरी

भारत की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। उसने चन्देल शासक परमार्दीदेव के देशभक्त सेनानी आल्हा और ऊदल को मारकर 1182 को महोबा को जीत लिया। कन्नौज के गाहड़वाल शासक जयचन्द का दिल्ली को लेकर चौहानों से वैमनस्य था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी अपनी दिग्विजय में कन्नौज को शामिल करना चाहता था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचन्द की महत्त्वाकांक्षा दोनों के वैमनस्य का कारण बन गयी। पृथ्वीराजरासो दोनों के मध्य शत्रुता का कारण जयचन्द की पुत्री संयोगिता को बताता है। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मुहम्मद गौरी को पराजित कर भारत में तुर्क आक्रमण को धक्का पहुँचाया। तुर्कों के विरुद्ध लड़े गये युद्धों में तराइन का प्रथम युद्ध हिन्दू विजय का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। परन्तु पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित तुर्की सेना का पीछा न किया जाना इस युद्ध में की गयी भूल के रूप में भारतीय भ्रम का एक कलंकित पृष्ठ है। इस भूल के परिणामस्वरूप 1192 में मुहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया। इस हार का कारण राजपूतों का परम्परागत सैन्य संगठन माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान अपने राज्यकाल के आरंभ से लेकर अन्त तक युद्ध लड़ता रहा, जो उसके एक अच्छे सैनिक और सेनाध्यक्ष होने को प्रमाणित करता है। सिवाय तराइन के द्वितीय युद्ध के, वह सभी युद्धों में विजेता रहा। वह स्वयं अच्छा गुणी होने के साथ–साथ गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन तथा विश्वरूप उसके दरबारी लेखक और कवि थे, जिनकी कृतियाँ उसके समय को अमर बनाये हुए हैं। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराजरासो का लेखक चन्दबरदाई भी पृथ्वीराज चौहान का आश्रित कवि था।

II रणथम्भौर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र **गोविन्द राज** ने की थी। यहाँ के प्रतिभा सम्पन्न शासकों में **हम्मीर** का नाम सर्वोपरि है। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर के समय रणथम्भौर पर असफल आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथम्भौर पर आक्रमण कर दिया। इसका मुख्य कारण हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थियों को आश्रय देना था। किला न जीत पाने के कारण अलाउद्दीन ने हम्मीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। हम्मीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया पर वह वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। हम्मीर की रानी रंगादेवी और पुत्री ने जौहर व्रत द्वारा अपने धर्म की रक्षा की। यह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। हम्मीर के साथ ही रणथम्भौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। हम्मीर के बारे में प्रसिद्ध है ''तिरिया–तेल, हम्मीर हठ, चढ़े न दूजी बार।''

III जालौर की चौहान शाखा का संस्थापक **कीर्तिपाल** था। प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जाबालिपुर और किले का सुवर्णगिरि मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की यह शाखा 'सोनगरा' कहलायी। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक **कान्हड़दे चौहान** था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतने से पूर्व 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया। उस समय चौहानों के एक सरदार, जिसका नाम सातलदेव था, दुर्ग का रक्षक था। उसने अनेक स्थानों पर तुर्कों को छकाया था। इसलिए उसके शौर्य की धाक राजस्थान में जम चुकी थी। परन्तु एक राजद्रोही भावले नामक सैनिक द्वारा विश्वासघात करने के कारण सिवाना का पतन हो गया और अलाउद्दीन ने सिवाना जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया। इस विजय के पश्चात् 1311 में जालौर का भी पतन हो गया और वहाँ का शासक कान्हड़देव वीर गति को प्राप्त हुआ। वह शूरवीर योद्धा, देशाभिमानी तथा चरित्रवान व्यक्ति था। उसने अपने अदम्य साहस तथा सूझबूझ से किले निवासियों, सामन्तों तथा राजपूत जाति का नेतृत्व कर एक अपूर्व ख्याति अर्जित की थी।

IV वर्तमान हाड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंशीय हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। प्राचीनकाल में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था। ऐसा माना जाता है कि बून्दा

मीणा के नाम पर ही बूँदी का नामकरण हुआ। कुंभाकालीन राणपुर के लेख में बूँदी का नाम 'वृन्दावती' मिलता है। **राव देवा** ने मीणाओं को पराजित कर 1241 में बूँदी राज्य की स्थापना की थी। बूँदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण **बरसिंह हाड़ा** ने करवाया था। तारागढ़ ऐतिहासिक काल में भित्तिचित्रों के लिए विख्यात रहा है। बूँदी के **सुर्जनसिंह** ने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बूँदी की प्रसिद्ध चौरासी खंभों की छतरी शत्रुसाल हाड़ा का स्मारक है, जो 1658 में शामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। **बुद्धसिंह** के शासनकाल में मराठों ने बूँदी रियासत पर आक्रमण किया था। प्रारम्भ में कोटा बूँदी राज्य का ही भाग था, जिसे शाहजहाँ ने बूँदी से अलग कर **माधोसिंह** को सौंपकर 1631 ई. में नये राज्य के रूप में मान्यता दी थी। कोटा राज्य का दीवान झाला जालिमसिंह इतिहास चर्चित व्यक्ति रहा है। कोटा रियासत पर उसका पूर्ण नियन्त्रण था। कोटा में ऐतिहासिक काल से आज तक कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा है। इसलिए कोटा का नाम 'नन्दग्राम' भी मिलता हैं। बूँदी–कोटा में सांस्कृतिक उपागम के रूप में यहाँ की चित्रशैलियाँ विख्यात रही हैं। बूँदी में पशु–पक्षियों का श्रेष्ठ अंकन हुआ है, वहीं कोटा शैली शिकार के चित्रों के लिए विख्यात रही है।

मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म–संस्कृतियाँ

राजस्थान में धार्मिक परम्परा और लोक विश्वास की धारा प्राचीन काल से ही लगातार जारी है। वैदिक धर्म और उससे संबंधी विश्वासों के प्रतीक राजस्थान में आज भी देखे जाते हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुण्डी शिलालेख में अवश्मेध यज्ञ का उल्लेख है। तीसरी सदी में नान्दसा यूप स्तम्भ तथा कोटा, जयपुर के कुछ यूप स्तंभों से यज्ञों के प्रचलन का बोध होता है। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध तथा अन्य यज्ञों के सम्पादन द्वारा अपने समय तक यज्ञों की वैदिक परम्परा को जीवित रखा। राजस्थान में 12वीं शताब्दी तक मुख्य देव के रूप में ब्रह्मा एवं सूर्य का अर्चन प्रचलित था।

अनेक स्त्रोतों से विदित होता है कि राजस्थान में **शैव धर्म** का अनेक राजवंशों पर प्रभाव था, जिनमें मेवाड़ और मारवाड़ रियासत प्रमुख हैं। लकुलीश और नाथ सम्प्रदाय के आचार्यों ने अपने चमत्कार के प्रभाव से मेवाड़ और मारवाड़ राजपरिवार पर क्रमशः प्रभाव स्थपित करने में सफलता प्राप्त की, जिसके परिणामस्वरूप मेवाड़ के महाराणा श्रीएकलिंगजी को ही अपने राज्य का स्वामी और स्वयं को उनका दीवान मानते थे। वहीं मारवाड़ के मानसिंह के समय नाथों का शासन कार्य में बड़ा हाथ रहा। मानसिंह ने जोधपुर में नाथों की प्रसिद्ध पीठ 'महामंदिर' का निर्माण करवाया था।

मध्यकालीन राजस्थान में अनेक रूपों में **शक्ति** की उपासना प्रचलित थी, जिसके प्रमाण ओसियाँ का सच्चियाय माता मंदिर, चित्तौड़ का कालिका मंदिर के रूप में देखे जा सकते हैं। राजस्थान के अनेक राजवंशों ने तो शक्ति पर विश्वास कर उसे कुलदेवी के रूप में स्वीकार कर लिया था। बीकानेर राजपरिवार करणीमाता, जोधपुर नागणेची माता, सिसोदिया नरेश बाणमाता, कछवाहा राजवंश अन्नपूर्णा माता के आज भी परम भक्त हैं।

राजस्थान में **वैष्णव धर्म** का सर्वप्रथम उल्लेख द्वितीय शताब्दी ई. पू. के घोसुण्डी के लेख में मिलता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रमाण के रूप में महाराणा कुंभा के समय में खड़िया गाँव में कृष्ण मन्दिर, चित्तौड़ तथा कुंभलगढ़ में कुंभश्याम मन्दिर, उदयपुर में जगदीश मन्दिर, नाथद्वारा का श्रीनाथजी मन्दिर, जोधपुर का घनश्यामजी मंदिर उल्लेखनीय है। नारी संत के रूप में मीरां अपने समय की कृष्ण भक्ति की अनुपम उदाहरण है। बीकानेर के पृथ्वीराज तथा जोधपुर के विजयसिंह और किशनगढ़ के नागरीदास अपने समय के कृष्ण भक्तों में प्रमुख स्थान रखते हैं। कृष्णभक्ति के साथ राम भक्ति भी राजस्थान में सम्मानित पद प्राप्त किये हुये थी। कछवाहा शासक स्वयं को 'रघुवंशतिलक' कहते थे।

राजस्थान में **जैन धर्म** वैश्यों में अधिक प्रचलित

रहा है। हालांकि यहाँ के शासक जैन अनुयायी नहीं रहें, परन्तु उन्होंने इस धर्म को सहिष्णुता दृष्टि से देखा। जैसलमेर, नाडौल, आमेर, धुलेव, रणकपुर, आबू, सिरोही आदि स्थानों पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ एवं जैन धर्म की प्रभावना से सम्बन्धित अनेक शिलालेख उपलब्ध हैं, जो जैन धर्म की राजस्थान में होने वाली प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान को जैन धर्म की सबसे बड़ी देन यह है कि इस धर्म के अनेक विद्वानों ने सहस्त्रों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथों को लिखा, जिनमें निहित ज्ञान हमारे लिए आज भी एक बड़ी निधि है।

इस्लाम धर्म राजस्थान में बारहवीं शताब्दी में अधिक प्रगतिशील बना। प्रसिद्ध सूफी सन्त ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती, मुहम्मद गौरी के आक्रमणों के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आये थे। इन्होंने अजमेर को अपना केन्द्र बनाया था, जहाँ से इसका जालौर, नागौर, माण्डल, चित्तौड़ आदि स्थानों पर प्रसार हुआ। नागौर में प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जो अजमेर के बाद राजस्थान में इस्लाम के प्रमुख केन्द्र के रूप में विख्यात है। सूफी संतों ने अपने चारित्रिक बल से मध्ययुगीन धार्मिक आक्रोश को कम करने में सफलता पायी। इतना ही नहीं राजस्थान के अनेक शासकों द्वारा मस्जिदों को अनुदान दिये जाने के उल्लेख मिलते हैं। अजमेर की दरगाह शरीफ को अजीतसिंह और जगतसिंह द्वारा गाँवों को भेंट के रूप में दिये जाने के वर्णन मिलते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान में 18वीं शताब्दी तक हिन्दू–मुस्लिम वैमनस्य का विशेष रूप नजर नहीं आया।

राजस्थान के लोकमानस में लोक देवों के रूप में एक नयी प्रवृत्ति दिखाई देती है। यहाँ जिन लोगों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपने देश की सेवा की अथवा नैतिक जीवन बिताया, उनको देवत्व (लोकदेवता) का स्थान देकर पूजा जाने लगा। ऐसे लोकप्रिय देवों में **गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी, देवजी, मल्लिनाथजी** प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने अपने आत्मोत्सर्ग के द्वारा तथा सादा और सदाचारी जीवन बिताने के कारण अमरत्व प्राप्त किया। लाखों की संख्या में ग्रामीण आज भी तेजाजी का चिह्न गले में पहनते हैं। इन विविध लोक देवों की उपासना प्रायः अति–विश्वास पर आधारित रही है और बुद्धिजीवियों की इन पर कोई विशेष श्रद्धा नहीं रही, फिर भी इनके प्रति दृढ़–निष्ठा ने लोक मानस को सद्मार्ग पर चलने के लिए निश्चय ही प्रेरित किया है।

राजस्थान के जाट परिवार में जन्में **धन्ना** के विचारों में रहस्यवाद और रूढ़िवाद का समन्वय देखा जा सकता है। ये बनारस में जाकर रामानन्द के शिष्य बन गये। इनका मानना था कि प्रेम और मनन से ईश्वर की प्राप्ति सुलभ है। पीपासर में जन्मे **जाम्भोजी** पँवारवंशीय राजपूत थे। ये साम्प्रदायिक संकीर्णता, कुप्रथाओं एवं कुरीतियों के विरोधी थे। इन्होंने समाज सुधारक की भाँति विधवा विवाह पर बल दिया। इनके सभी सिद्धान्त '29 शिक्षा' के नाम से जाने जाते हैं और इनका पालन करने वाले 'विश्नोई' (20+9) नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। इनमें अधिकांश जाट हैं। विश्नोई सम्प्रदाय के कई अनुयायियों ने जीव कल्याण और पर्यावरण रक्षार्थ अपने प्राण–न्योछावर किये। बनारस में पैदा हुये **रैदास** चित्तौड़ आये थे तथा इनकी एक छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। रैदास और कबीर के सिद्धान्तों में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। रैदास की वाणियों को 'रैदास की परची' कहते हैं।

मीरां नारी सन्तों में ईश्वर प्राप्ति में लगी रहने वाली भक्तों में प्रमुख है। यह रत्नसिंह की इकलौती पुत्री थी तथा इसका जन्म कुड़की में लगभग 1498–1499 में हुआ था। मीरां का विवाह मेवाड़ के सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था परन्तु भोजराज की शीघ्र ही मृत्यु हो जाने से मीरां पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा। मीरां के स्वतन्त्र विचार और सन्त संगति मेवाड़ राजपरिवार के लिए असहय थे। मीरां के जीवन से कुछ कथानक जुड़े हुये है जैसे, जहर पीने के लिए विवश करना, सांप से कटवाना, उसके चरित्र पर राजा द्वारा सन्देह करना इत्यादि, परन्तु कृष्णभक्ति में लगी मीरां के लिए शारीरिक यातनाएँ, वैधव्य जीवन इत्यादि कोई महत्त्व नहीं रखते थे। मीरां कहती थी 'मारो तो गिरधिर गोपाल दूजो न कोई।' मीरां की दृष्टि में समृद्धि, वैभव, संसार के सुख, उच्च पद और सम्मान मिथ्या है। यदि कोई

सत्य है तो उसके 'गिरिधर गोपाल।' मीरां की भक्ति की विशेषता यह थी कि उसमें ज्ञान पर जितना बल नहीं था उतना भावना एवं अनुभूति पर था। ऐसा प्रचलित है कि मीरां वृन्दावन में रहते हुए अथवा द्वारिका में रहते हुए 1540 के लगभग नृत्य करने–करते रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन हो गयीं। नवीन शोध से यह स्थापित हुआ कि महात्मा गांधी भक्ति आन्दोलन के संत नरसिंह मेहता के साथ मीरां से काफी प्रभावित थे और वे मीरां को अन्याय के विरूद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला के रूप में देखते थे। निश्चय ही मीरां आज भी लोक मानस पटल पर प्रभावी है।

दादू पंथ के प्रवर्तक **दादू** धर्म संबंधी स्वतन्त्र विचारकों में प्रमुख सन्त हैं। उनकी मृत्यु 1605 में नारायणा (जयपुर) में हुई थी। नारायणा की गद्दी दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। इनके 52 शिष्य बावन स्तंभ कहलाते हैं, जिनमें सुन्दरदास, रज्जबजी प्रमुख हैं। दादू आमेर के कछवाहा शासक मानसिंह के समकालीन थे। कबीर की भाँति दादू रूढ़ियों, विविध पूजा पद्धतियों के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे कि ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिन्दू–मुसलमानों का कोई भेदभाव नहीं है। दादू की उपासना निरंजन और निर्गुण ब्रह्म की प्राधान्यता को लेकर है। दादू की सबसे बड़ी विशेषता है, प्रचार में स्थानीय भाषा का प्रयोग। उन्होंने ढूँढाड़ी भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में गुजराती, पश्चिमी हिन्दी तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। इसी कारण हिन्दी सन्त साहित्य में दादू की 'वाणी' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कबीर और दादू के विचारों में सुधारवादी भावना के रूप में समानता मिलती है। इसके विपरीत कबीर के कहने में उग्रता झलकती है तो दादू में विनम्रता। दादू द्वारा प्रतिपादित पंथ में प्रेम एक ऐसा धागा है, जिसमें गरीब व अमीर बांधे जा सकते हैं तथा जिसकी एकसूत्रता विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

लालदासी सम्प्रदाय के संस्थापक **संत लालदास** का जन्म धोलीदूब गाँव (जिला अलवर) में हुआ था। इन्होंने हिन्दू–मुस्लिम दोनों धर्मो की अच्छाइयों को अपनाकर लोगों को उपदेश दिये तथा साम्प्रदायिक समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेव मुसलमान इनको पीर मानते हैं। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक तथा समाज सुधारक थे। इनका निधन नगला में हुआ।

कामड़िया पंथ के संस्थापक **रामदेवजी** का जन्म उडूकासमेर (बाड़मेर) में हुआ था। इन्होंने समाज में छूआछूत और ऊँच–नीच के भेदभाव का विरोध रख हिन्दू–मुस्लिम समन्वयता के लिए प्रयास किया। इनका समाधि स्थल रामदेवरा (रूणेचा) में है, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। इनकी स्मृतियों में आयोजित रामदेवरा मेले में हजारों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। इस मेले की मुख्य विशेषता साम्प्रदायिक सद्भावना है। इस मेले में कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा तेरहताली नृत्य किया जाता है। रामदेवजी को हिन्दू 'विष्णु का अवतार' और मुस्लिम 'रामशाह पीर' और 'पीरों के पीर' मानते हैं।

जसनाथी सम्प्रदाय के संस्थापक **जसनाथजी** का जन्म कतरियासर (बीकानेर) में हुआ था। इस सम्प्रदाय में रात्रि जागरण, अग्नि नृत्य इत्यादि प्रचलित है। **संत पीपा** खींची राजपूत थे। इनकी छतरी गागरोन (झालावाड़) में है। श्रीकृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित **सन्त मावजी** का जन्म मावला (डूँगरपुर) में हुआ था। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम–माही–जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर की।

वर्तमान टोंक जिले के सोडा ग्राम में विजयवर्गीय वैश्य परिवार में जन्मे **सन्त रामचरण** ने 18वीं सदी के राजनीतिक और धार्मिक ह्रास के काल में जन्म लेकर इस समय की क्षतिपूर्ति की। इन्होंने अपने विचारों को मूर्त्त रूप देने के लिए 'अणभैवाणी' की रचना की तथा 'रामस्नेही सम्प्रदाय' का प्रचलन किया, जिसकी प्रधान पीठ 'शाहपुरा' (भीलवाड़ा) में है। उन्होंने अपने अनुयायियों को 'राम' नाम का मन्त्र देकर मानवता का सन्देश दूर–दूर तक फैलाया। ये निर्गुण उपासक थे। अतः रामस्नेही मत को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते। इस पंथ में नैतिक आचरण, गुरु महिमा, सत्यनिष्ठा, धार्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता है।

इस प्रकार मध्यकालीन धार्मिक आन्दोलन और लोक विश्वासों ने राजस्थानी समाज में न्यूनाधिक नवजागरण की अलख जगाई। इस काल की धार्मिक–सांस्कृतिक गतिविधियों ने सभी हिन्दू और दलित जाति को एक वर्ग मानकर, पंथों की सीमाएँ बनायी, जिससे विधर्मी होने के अवसर कम हो गये और भारतीय जनता एक सूत्र में बंधी रह गई। यहाँ तक कि कई पंथों ने तो हिन्दू–मुसलमानों के भेदभाव को अस्वीकृत कर चेतना के स्वर को नव आयाम प्रदान किया। कुल मिलाकर, यह युग न केवल राजस्थान की संस्कृति का उज्ज्वल युग है अपितु सांझी संस्कृति का परिचायक भी है, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है।

राजस्थान के मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल

अचलगढ़

आबू के निकट अवस्थित अचलगढ़ पूर्व–मध्यकाल में परमारों की राजधानी रहा है। यहाँ अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर है। कुम्भा द्वारा निर्मित कुम्भस्वामी का मन्दिर यहीं अवस्थित है। अचलेश्वर महादेव मन्दिर के सामने चारण कवि दुरसा आढा की बनवाई स्वयं की पीतल की मूर्ति है। अचलेश्वर पहाड़ी पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे राणा कुम्भा ने ही बनवाया था।

अजमेर

आधुनिक राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर नगर की स्थापना 12 वीं शताब्दी में चौहान शासक अजयदेव ने की थी। यहाँ के मुख्य स्मारकों में कुतुबद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित ढ़ाई दिन का झौपड़ा, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह, सोनीजी की नसियाँ (जैन मन्दिर, जिस पर सोने का काम किया हुआ है) , अजयराज द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग, अकबर द्वारा बनवाया गया किला (मैग्जीन) आदि प्रमुख स्मारक हैं। यह मैग्नीज फोर्ट वर्तमान में संग्रहालय के रूप में है। यह स्मरण रहे कि ख्वाजा साहिब की दरगाह साम्प्रदायिक सद्भाव का जीवंत नमूना है। यहाँ चौहान शासक अर्णोराज (आनाजी) द्वारा निर्मित आनासागर झील बनी हुई है। इस झील के किनारे पर जहाँगीर ने दौलतबाग (सुभाष उद्यान) और शाहजहाँ ने बारहदरी का निर्माण करवाया था।

अलवर

18 वीं शताब्दी में रावराजा प्रतापसिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की थी। अलवर का किला, जो बाला किला के नाम से जाना जाता है, 16 वीं शताब्दी में एक अफगान अधिकारी हसन खां मेवाती ने बनवाया था। अलवर में मूसी महारानी की छतरी है, जो राजा बख्तावरसिंह की पत्नी रानी मूसी की स्मृति में निर्मित है। यह छतरी अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। अलवर का राजकीय संग्रहालय दर्शनीय है, जहाँ अलवर शैली के चित्र सुरक्षित है।

आबू

अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित आबू सिरोही के निकट स्थित है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊँचा भाग 'गुरु शिखर' है। महाभारत में आबू की गणना तीर्थ स्थानों में की गई है। आबू अपने देलवाड़ा जैन मन्दिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का विमलशाह द्वारा निर्मित आदिनाथ मन्दिर तथा वास्तुपाल– तेजपाल द्वारा निर्मित नेमिनाथ का मन्दिर उल्लेखनीय है। आबू के देलवाड़ा के जैन मन्दिर अपनी नक्काशी, सुन्दर मीनाकारी एवं पच्चीकारी के लिए भारतभर में प्रसिद्ध है। इन मन्दिरों का निर्माण 11वीं एवं 13वीं शताब्दी में किया गया था। ये मन्दिर श्वेत संगमरमर से निर्मित है। यहाँ श्वेत पत्थर पर इतनी बारीक खुदाई की गई है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। आबू पर्वत को अग्नि कुल के राजपूतों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है।

आमेर

जयपुर से सात मील उत्तर–पूर्व में स्थित आमेर ढूँढाड़ राज्य की जयपुर बसने से पूर्व तक राजधानी था। दिल्ली–अजमेर मार्ग पर स्थित होने के कारण आमेर का मध्यकाल में बहुत महत्त्व रहा है। कछवाहा वंश की राजधानी आमेर के वैभव का युग मुगल काल से प्रारम्भ होता है। आमेर का किला दुर्ग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ के भव्य प्रासाद एवं मन्दिर हिन्दू एवं फारसी

शैली के मिश्रित रूप हैं। इसमें बने दीवान–ए–आम, दीवान–ए–खास (शीशमहल) आदि की कलात्मकता प्रशंसनीय है। इस किले में जगतशिरोमणि मंदिर और शिलादेवी मन्दिर बने हुए है। इनका निर्माण मानसिंह के समय हुआ था। मानसिंह शिलादेवी की मूर्ति को बंगाल से जीतकर लाया था। आमेर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है।

उदयपुर

महाराणा उदयसिंह ने 16 वीं शताब्दी मे इस शहर की स्थापना की थी। यहाँ के महल विशाल परिसर में अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। राजमहलों के पास ही 17 वीं शताब्दी का निर्मित जगदीश मन्दिर है। यहाँ की पिछौला झील एवं फतह सागर झील मध्यकालीन जल प्रबन्धन के प्रशंसनीय प्रमाण है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आधुनिक काल की मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति है, जिसने स्मारक का रूप ग्रहण कर लिया है। महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित सहेलियों की बाड़ी तथा महाराणा सज्जनसिंह द्वारा बनवाया गुलाब बाग शहर की शोभा बढ़ाने के लिए पर्याप्त है।

ऋषभदेव (केसरियाजी)

उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में स्थित यह स्थान ऋषभदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैन एवं आदिवासी भील अनुयायी इसे समान रूप से पूजते हैं। भील इन्हें कालाजी कहते हैं, क्योंकि ऋषभदेव की प्रतिमा काले पत्थर की बनी हुई है। मूर्ति पर श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं और इसका लेप करते हैं, इसलिए इसे केसरियानाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष मेला भरता है।

ओसियाँ

जोधपुर जिले में स्थित ओसियाँ पूर्वमध्यकालीन मन्दिरों के लिए विख्यात है। यहाँ के जैन एवं हिन्दू मन्दिर 9वीं से 12वीं शताब्दियों के मध्य निर्मित है। यहाँ के जैन मन्दिर स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। महावीर स्वामी के मंदिर के तोरण द्वार एवं स्तम्भों पर जैन धर्म से सम्बन्धित शिल्प अंकन दर्शनीय है। यहाँ के सूर्य मंदिर, सच्चियामाता का मंदिर आदि उस युग के कला वैभव का स्मरण कराते हैं।

करौली

यदुवंशी शासक अर्जुनसिंह ने करौली की स्थापना की थी। करौली में महाराजा गोपालपाल द्वारा बनवाए गए रंगमहल एवं दीवान–ए–आम खूबसूरत हैं। यहाँ की सूफी संत कबीरशाह की दरगाह भी स्थापत्य कला का सुन्दर नमूना है। करौली का मदनमोहनजी का मन्दिर प्रसिद्ध है।

किराडू

बाड़मेर से 32 किमी. दूर स्थित किराडू पूर्व–मध्यकालीन मन्दिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का सोमेश्वर मन्दिर शिल्पकला के लिए विख्यात है। यह स्थल राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ कामशास्त्र की भाव भंगिमा युक्त मूर्तियाँ शिल्पकला की दृष्टि से बेजोड़ है।

किशनगढ़

अजमेर जिले में जयपुर मार्ग पर स्थित किशनगढ़ की स्थापना 1609 ई. में जोधपुर के शासक उदयसिंह के पुत्र किशनसिंह ने की थी। किशनगढ़ अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है।

केशवरायपाटन

बूँदी जिले में चम्बल नदी के किनारे स्थित केशवरायपाटन में बूँदी नरेश शत्रुशाल द्वारा 17वीं शताब्दी का निर्मित विशाल केशव (विष्णु) मन्दिर है। यहाँ पर जैनियों का तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर है।

कोटा

कोटा की स्थापना 13 वीं शताब्दी में बूँदी के शासक समरसी के पुत्र जैतसी ने की थी। उसने कोटा के स्थानीय शासक कोटिया भील को परास्त कर उसके नाम से कोटा की स्थापना की। शाहजहाँ के फरमान से सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में बूँदी से अलग होकर कोटा स्वतन्त्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य के क्रांतिकारियों ने बढ़–चढ़कर भाग

लिया। कोटा के क्षार बाग की छतरियाँ राजपूत स्थापत्य कला के सुन्दर नमूने है। यहाँ का महाराव माधोसिंह संग्रहालय एवं राजकीय ब्रज विलास संग्रहालय कोटा चित्र शैली एवं यहाँ के शासकों की कलात्मक अभिरुचि को प्रदर्शित करते है। कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर वैष्णव सम्प्रदाय का प्रमुख तीर्थ है एवं वल्लभ सम्प्रदाय की पीठ है। कोटा का दशहरा मेला भारत प्रसिद्ध है।

कौलवी

झालावाड़ जिले में डग कस्बे के समीप स्थित कौलवी की गुफाएँ बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध है। ये विहार 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य निर्मित माने जाते है। ये गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित हैं, जो चट्टानें काटकर बनायी गई हैं।

खानवा

भरतपुर जिले में स्थित खानवा मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुए युद्ध (1527) के लिए विख्यात है। खानवा के युद्ध में सांगा की हार ने राजपूतों को दिल्ली की गद्दी पर बैठने का स्वप्न नष्ट कर दिया और मुगल वंश की स्थापना को मजबूत कर दिया।

गलियाकोट

डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट वर्तमान में दाऊदी बोहरा सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र है। यहाँ संत सैय्यद फख़रुद्दीन की दरगाह स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी याद में उर्स का मेला भरता है।

गोगामेड़ी

हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में स्थित गोगामेड़ी लोक देवता गोगाजी का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष उनके सम्मान में एक पशु मेले का आयोजन होता है। राजस्थान में गोगाजी सर्पो के लोकदेवता के रूप में प्रसिद्ध है। हिन्दू इन्हें गोगाजी तथा मुसलमान गोगा पीर के नाम से पूजते हैं।

चावण्ड

उदयपुर से ऋषभदेव जाने वाली सड़क पर अरावली पहाड़ियों के मध्य 'चावण्ड' गाँव बसा हुआ है। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात् चावण्ड को अपनी राजधानी बनाया था। प्रताप की मृत्यु भी 1597 में चावण्ड में हुई थी।

चित्तौड़गढ़

यह नगर अपने दुर्ग के नाम से अधिक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। समय–समय पर चित्तौड़ दुर्ग का विस्तार होता रहा है। चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा गया है। इसके बारे में कहावत है –'गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढैया'। चित्तौड़ के शासकों ने तुर्कों एवं मुगलों से इतिहास प्रसिद्ध संघर्ष किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुम्भा द्वारा बनवाये अनेक स्मारक हैं, जिनमें नौ मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति (विजय स्तम्भ), स्तम्भ कुम्भश्याम मन्दिर, श्रृंगार चँवरी, कुम्भा का महल आदि शामिल हैं। दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित सात मंजिला जैन कीर्ति स्तम्भ, जयमल–पत्ता के महल, मीरा मन्दिर, रैदास की छतरी, तुलजा भवानी मन्दिर आदि अपने कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हैं।

जयपुर

भारत का पेरिस एवं गुलाबी नगर नाम से प्रसिद्ध जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। कछवाहा राजाओं की इस राजधानी का महत्व अपने स्थापना काल से ही रहा है। यहाँ के स्थापत्य में राजपूत एवं मुगल स्थापत्य का मिश्रण देखा जा सकता है। यहाँ का सिटी पैलेस जयपुर के राजपरिवार का निवास स्थल रहा है। सिटी पैलेस के पास ही गोविन्ददेवजी का मन्दिर है, जो सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित है। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वैधशाला 'जन्तर–मन्तर' का विशेष महत्व है। यहाँ स्थापित सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है। नाहरगढ़ किला, हवामहल, रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आदि दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थल हैं।

जालौर

ऐसा माना जाता है कि जालौर (जाबालिपुर)

प्राचीनकाल में महर्षि जाबालि की तपोभूमि था। जालौर के प्रसिद्ध शासक कान्हड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी से लम्बे समय तक लोहा लिया था। जालौर के सुवर्णगिरि दुर्ग का निर्माण परमार राजपूतों ने करवाया था। दुर्ग में वैष्णव एवं जैन मंदिर तथा सूफी संत मलिकशाह का मकबरा है।

जैसलमेर

भाटी राजपूतों की राजधानी जैसलमेर की स्थापना 12 वीं शताब्दी में महारावल जैसल ने की थी। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित्त होने के कारण 'सोनार किला' कहलाता है। दुर्ग में अनेक वैष्णव एवं जैन मन्दिर बने हैं, जो अपनी शिल्पकला की उत्कृष्टता के कारण विख्यात है। जैसलमेर का जिनभद्र ज्ञान भण्डार प्राचीन ताड़पत्रों एवं पाण्डुलिपियों तथा कई भाषाओं के ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर की हवेलियों की वजह से विशेष पहचान है। यहाँ की पटवों की हवेलियाँ, सालिमसिंह की हवेली तथा नथमल की हवेली अपने झरोखों, दरवाजों व जालियों की नक्काशीयुक्त शिल्प के लिए पहचानी जाती हैं। जैसलमेर शासकों के निवास बादल निवास व जवाहर विलास शिल्पकला के 'बेजोड़ नमूने है। रावत गढ़सी सिंह द्वारा निर्मित्त मध्यकालीन गढसीसर सरोवर अपने कलात्मक प्रवेश द्वार एवं छतरियों के लिए प्रसिद्ध है।

जोधपुर

इस नगर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने की थी। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने शुरू किया, जिसमें कालान्तर में विस्तार होता रहा है। इस दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में फूल महल, मोती महल, चामुण्डा देवी का मन्दिर दर्शनीय हैं। दुर्ग के पास ही जसवन्त थड़ा है, जो महाराजा जसवन्त सिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया गया था। यहाँ आधुनिक काल का उम्मेद भवन (छीतर पैलेस) अपनी विशालता एवं कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है।

झालरापाटन

झालावाड़ शहर से 4 मील दूर स्थित झालरापाटन कस्बा कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिमसिंह ने बसाया था। यहाँ पहले 108 मन्दिर थे, जिनकी झालरों एवं घण्टियों के कारण कस्बे का नाम झालरापाटन रखा गया। यहाँ का मध्यकालीन सूर्य मन्दिर प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में सात सहेलियों के मन्दिर के नाम से प्रख्यात है। यहाँ का शांतिनाथ का जैन मन्दिर विशाल एवं भव्य है, जो 11वीं शताब्दी का निर्मित है।

टोंक

17 वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 ग्रामों को मिलाकर टोंक की स्थापना की। 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अमीर खां ने टोंक रियासत की स्थापना की। टोंक की सुनहरी कोठी पच्चीकारी एवं मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। टोंक के अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, जो आधुनिक काल का है, में हस्तलिखित उर्दू, अरबी–फारसी ग्रंथों का विशाल संग्रह है।

डूँगरपुर

रावल वीर सिंह ने 14 वीं शताब्दी में डूँगरपुर की स्थापना की थी। डूँगरपुर को वॉगड़ राज्य की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डूँगरपुर अपने मध्यकालीन मन्दिरों, हरे रंग के पत्थर की मूर्तियों आदि के कारण प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का गैप सागर जलाशय अपने स्थापत्य के कारण आकर्षित करता है। यहाँ का उदयविलास पैलेस सफेद संगमरमर एवं नीले पत्थर से बना है, जो नक्काशी तथा झरोखों से सुसज्जित है। आदिवासियों से बाहुल्य डूँगरपुर में परम्परागत जन–जीवन की झांकी देखने को मिलती है।

डीग

भरतपुर जिले में डीग जाट नरेशों के भव्य महलों के लिए विख्यात है। भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में यहाँ सुन्दर राजप्रासाद बनवाये। डीग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना किला है, जिसे गोपालगढ़ कहते है।

नागौर

नागौर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था। यहाँ

समय–समय पर नागवंश, परमारवंश एवं मुगल वंश का शासन रहा। अपने विशालकाय परकोटों व प्रभावशाली द्वारों के कारण नागौर राजपूतों के अद्भुत नगरों में से एक है। ऐतिहासिक नागौर किले में शानदार महल, मन्दिर एवं भव्य इमारतें है। नागौर का दुर्ग दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है। यह किला राव अमरसिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास प्रसिद्ध है। नागौर के ऐतिहासिक झंडा तालाब पर बनी 16 कलात्मक खम्भों से निर्मित अमरसिंह राठौड़ की छतरी एवं कलात्मक बावड़ी दर्शनीय है। यहाँ सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह हिन्दू–मुस्लिम सद्भाव के रूप में पहचानी जाती है। नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है।

नाथद्वारा

राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे बसे नाथद्वारा पूरे देश में श्रीनाथजी के वैष्णव मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है। पुष्टिमार्गीय वैष्णवों का यह प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ कृष्ण की उपासना उसके बालरूप में की जाती है। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण श्रीनाथजी की मूर्ति मथुरा से सिहाड़ ग्राम (वर्तमान नाथद्वारा) लाई गई, जो महाराणा राजसिंह के प्रयासों से नाथद्वारा में प्रतिष्ठापित की गई। चढ़ावे की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे सम्पन्न तीर्थस्थल है। पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है।

पुष्कर

अजमेर के निकट पुष्कर हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पद्म पुराण में भी इसकी महिमा का बखान किया गया है। पुष्करताल के घाटों पर स्नान करना अत्यन्त पुण्य का काम समझा जाता है। तीर्थराज पुष्कर में प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मन्दिर है। यहाँ के अन्य प्रसिद्ध मन्दिरों में रंगनाथ मन्दिर, सावित्री मन्दिर, वराह मन्दिर आदि धार्मिक महत्त्व के हैं। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में मेले का आयोजन होता है। यह मेला न केवल विभिन्न पशुओं की खरीद–फरोख्त का माध्यम है बल्कि विदेशी पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र माना जाता है। वर्तमान में पुष्कर को अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त है।

बूँदी

राव देवा ने 13वीं शताब्दी में बूँदी राज्य की स्थापना की थी। बूँदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव राजा बरसिंह ने 14वीं शताब्दी में शुरू करवाया था। बूँदी के शासक शत्रुसाल हाड़ा मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान धरमत की लड़ाई (1658) में मारा गया। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में नवल सागर, चौरासी खम्भों की छतरी, रानीजी की बावड़ी, जैत सागर , फूल सागर आदि है। बूँदी अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए विख्यात है। बूँदी एक ऐसा शहर है, जिसके पास समृद्ध विरासत है और आज भी मध्यकालीन शहर की झलक देता है।

बयाना

भरतपुर जिले में स्थित बयाना का उल्लेख 13वीं–14वीं शताब्दी के इब्नेबतूता, जियाउद्दीन बरनी जैसे लेखकों ने भी किया है। आगरा के निकट होने के कारण बयाना का सामरिक महत्त्व था। मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना से बड़ी संख्या में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, जो तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। राणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा की लड़ाई (1527ई.) हुई थी, जो बयाना के निकट ही है।

बाड़ोली

चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा के निकट बाड़ोली हिन्दू मन्दिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये मन्दिर गणेश, विष्णु, शिव, महिषासुर मर्दिनी आदि को समर्पित है। इन मन्दिरों से लोगों को सबसे पहले परिचय कर्नल जेम्स टॉड ने कराया था।

बीकानेर

राव बीका द्वारा 15 वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की गई थी। यहाँ के 16 वीं शताब्दी के शासक रायसिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग अपने स्थापत्य कला एवं चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर शहर प्राचीर से घिरा हुआ हैं, जिसमें पाँच

दरवाजे बने हुए है। लाल और सफेद पत्थरों से निर्मित रतन बिहारी जी का मन्दिर, लालगढ़ पैलेस, पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मन्दिर आदि कलात्मक एवं दर्शनीय हैं। बीकानेर का अनूप पुस्तकालय पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है।

भरतपुर

राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जाट शासक बदनसिंह ने की थी। उसके उत्तराधिकारी सूरजमल ने भरतपुर राज्य का विस्तार किया और इसे शानदार महलों से अलंकृत किया। मिट्टी की मोटी दोहरी प्राचीरों से घिरा भरतपुर का किला अपनी अभेद्यता के कारण लोहागढ दुर्ग' के नाम से प्रख्यात है। भरतपुर सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्वी राजस्थान का एक समृद्ध नगर है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में गंगा मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, जामा मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आदि हैं।

भीनमाल

जालौर जिले में स्थित भीनमाल का सम्बन्ध प्राचीन इतिहास से रहा है। संस्कृत के प्रख्यात कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना यहीं की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी।

मण्डावा

झुँझुनूं में मण्डावा शेखावाटी अंचल का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते है। इस कस्बे के चारों ओर रेगिस्तानी टीलें है। यहाँ स्थित सेठों की हवेलियाँ, उनका स्थापत्य तथा उनमें बने भित्ति चित्र पर्यटन एवं कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोयनका की हवेली, लाडियों की हवेली आदि हवेली चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।

मण्डौर

जोधपुर के पास स्थित मण्डौर पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा है। मण्डौर दुर्ग के अन्दर विष्णु और जैन मन्दिरों के खण्डहर हैं। यहाँ स्थित मण्डौर उद्यान में मण्डौर संग्रहालय, जनाना महल तथा राजाओं के देवल (स्मारक) बने हुए हैं। इस उद्यान में राजा अजीतसिंह तथा राजा अभयसिंह ने देवताओं की साल (बरामदा) का निर्माण करवाया था।

महनसर

झुंझुनू में महनसर पोद्दारों की सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है, जो हरचंद पोद्दार ने बनवाई थी। यहाँ के भित्ति चित्रों में मुख्यतः श्रीराम और कृष्ण की लीलाओं का सुन्दर अंकन हुआ है। यह दुकान, जो मूलतः एक इमारत है पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। महनसर में सेठों की अनेक हवेलियाँ है, जो भित्ति चित्रों एवं हवेली स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। महनसर की एक अन्य इमारत उल्लेखनीय है, जिसे तोलाराम जी का कमरा कहा जाता है। इस दो मंजिला इमारत को देखने के लिए लोग दूर–दूर से आते है। शेखावाटी अंचल के लोकगीतों में इस इमारत की सुन्दरता का वर्णन मिलता है।

रणकपुर

पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मन्दिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का मुख्य मन्दिर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ (ऋषभदेव) का है। इनकी चतुर्मुखी प्रतिमा होने के कारण इसे चौमुखा मन्दिर भी कहते हैं। इस मन्दिर का निर्माण महाराणा कुम्भा के शासनकाल में सेठ धरणशाह ने 15 वीं शताब्दी में करवाया था। इस मन्दिर में 1444 स्तम्भ हैं। इस मन्दिर का शिल्पी देपाक था। इस मन्दिर में राजस्थान की जैन कला एवं धार्मिक परम्परा का अपूर्व प्रदर्शन हुआ है। एक कला मर्मज्ञ की टिप्पणी है कि ऐसा जटिल एवं कलापूर्ण मन्दिर मेरे देखने में नहीं आया।

रामदेवरा

जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील में अवस्थित 'रामदेवरा' लोक संत रामदेवजी का समाधि स्थल है। यहाँ रामदेवजी का भव्य मन्दिर बना हुआ है। यहाँ भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक मेला भरता है, जिसमें भारत के कोने–कोने से हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह मेला साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है।

सवाई माधोपुर

इस शहर की स्थापना जयपुर के शासक सवाई माधोसिंह ने की थी। यहाँ का रणथम्भौर का किला हम्मीर चौहान की वीरता का साक्षी रहा है। रणथम्भौर में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों द्वारा किया गया जौहर राजस्थान के पहले साके के रूप में विख्यात है। दुर्ग में त्रिनेत्र गणेशजी का मंदिर स्थित है। रणथम्भौर दुर्ग की प्रमुख विशेषता है कि इस किले में बैठकर दूर–दूर तक देखा जा सकता है परन्तु शत्रु किले को निकट आने पर ही देख सकता है। यहाँ का रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान (बाघ अभयारण्य) पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है।

हल्दीघाटी

राजसमंद जिले में स्थित 'हल्दीघाटी' गांव महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़े युद्ध (18 जून, 1576) के लिए प्रसिद्ध है। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, परन्तु अकबर जैसा साम्राज्यवादी शासक भी प्रताप की संघर्ष एवं स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सका। युद्धस्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है किंतु दुर्भाग्य से इसके मूल स्वरूप को यथावत् रखने में प्रशासन असफल रहा है। इतिहास के जागरूक छात्रों को चाहिये कि वे स्मारकों के संरक्षण में सहयोग प्रदान करें।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. मत्स्य जनपद में कौनसे आधुनिक जिले शामिल किए जा सकते हैं ?
   (अ) अलवर, करौली, जयपुर, भरतपुर
   (ब) अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली
   (स) अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर
   (द) अलवर, जयपुर, भरतपुर, कोटा
2. मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा, वह है –
   (अ) चौहान (ब) कछवाहा
   (स) गुहिल (द) प्रतिहार
3. जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी थी –
   (अ) मण्डोर (ब) भीनमाल
   (स) आमेर (द) ओसियाँ
4. आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग करने वाला था –
   (अ) जार्ज थॉमस
   (ब) गौरीशंकर हीराचन्द ओझा
   (स) कनिंघम
   (द) जेम्स टॉड
5. जुते हुए खेत के प्राचीनतम् साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले है ?
   (अ) कालीबंगा (ब) आहड़
   (स) बैराठ (द) रंगमहल
6. तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा –
   (अ) पृथ्वीराज चौहान की पराजय
   (ब) पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु
   (स) पृथ्वीराज चौहान की विजय
   (द) पृथ्वीराज चौहान का युद्ध मैदान से भाग निकलना
7. कीर्तिस्तम्भ का (जिसे विजय स्तम्भ के नाम से अधिक जाना जाता है) निर्माता था –
   (अ) राणा सांगा (ब) राणा कुम्भा
   (स) राणा लाखा (द) राणा उदयसिंह
8. 18 जून, 1576 को कौनसा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया ?
   (अ) दिवेर (ब) चित्तौड़
   (स) हल्दीघाटी (द) खानवा
9. मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को 'आधुनिक' माना जा सकता है ?
   (अ) मिर्जाराजा जयसिंह
   (ब) राजा मानसिंह
   (स) राजा रामसिंह द्वितीय
   (द) सवाई जयसिंह

10. जेम्स टॉड ने किसे 'राठौड़ों का यूलीसैस' कहा –
    (अ) राव चन्द्रसेन (ब) राव सुरताण
    (स) दुर्गादास (द) राव जोधा
11. राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम् साक्ष्य कौनसा अभिलेख प्रस्तुत करता है –
    (अ) बिजौलिया अभिलेख
    (ब) घोसुण्डी अभिलेख
    (स) हस्तीकुण्डी शिलालेख
    (द) कीर्ति स्तम्भ अभिलेख
12. नागौर का सम्बन्ध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा –
    (अ) ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती
    (ब) हमीदुद्दीन नागौरी
    (स) शेख बख्तियार काकी
    (द) निजामुद्दीन औलिया

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. राजस्थान के नामकरण के बारे में आप क्या जानते है ?
2. आहड़ सभ्यता की दो विशेषताएँ बताइये।
3. देलवाड़ा के जैन मन्दिरों पर प्रकाश डालिये।
4. हल्दीघाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ तथा क्या परिणाम निकले ?
5. राजसमंद झील का निर्माण किसने और क्यों करवाया ?
6. आमेर की चार प्रमुख इमारतें बताइये।
7. अजमेर एवं नागौर में किन सूफी संतों की दरगाह है ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. कालीबंगा सभ्यता का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
2. राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मतों की प्रस्तुति दीजिये।
3. रणथम्भौर एवं जालौर के चौहान शासकों का एक परिचय दीजिये।
4. महाराणा कुम्भा की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिये।
5. जैन धर्म से सम्बन्धित राजस्थान के चार प्रमुख स्थलों के नाम बताइये।
6. पुष्कर के धार्मिक महत्त्व को स्पष्ट कीजिये।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. मध्यकालीन राजस्थान के प्रमुख शासकों की उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये।
2. मध्यकालीन राजस्थान के भक्ति आन्दोलन के संतों की शिक्षाओं एवं उपलब्धियों की विवेचना कीजिये।

❑❑❑❑

10 Commandents of safe driving

- Don't jump traffic lights
- Drive wearing seat belts
- Don't drive without wearing a helmet
- Don't talk on mobile
- Don't drive on wrong side
- Don't break speed barrier
- Don't drive in no-entry zone
- Turn lights to low-beam while driving in city limits
- Avoid use of tinted glasses on your car windows
- Don't drink and drive

अध्याय–2

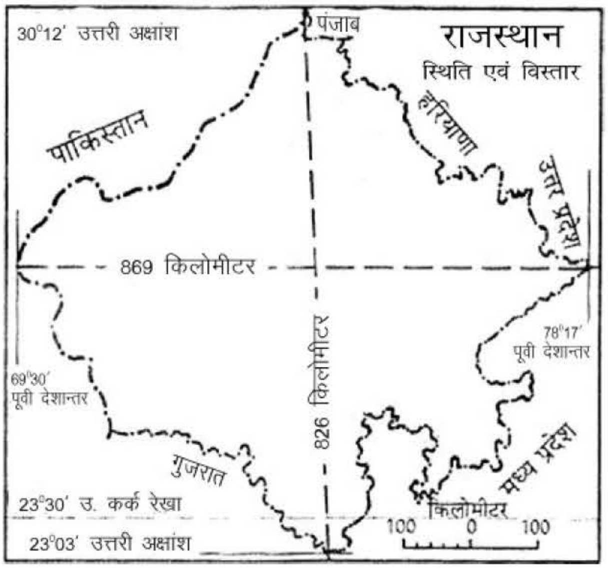
राजस्थान का भौतिक पर्यावरण

राजस्थान राज्य जहाँ एक ओर इसके गौरवशाली इतिहास के लिये पहचाना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसका भौतिक स्वरूप भी विशिष्टता लिये हुए है। राज्य के भौतिक पर्यावरण ने यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक वातावरण को सदैव से प्रभावित किया है और वर्तमान में भी राज्य के विकास में महती भूमिका निभा रहा है।

स्थिति एवं विस्तार

राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी–पश्चिमी भाग में 23°3' से 30°12' उत्तरी अक्षांश से 69°29' से 78°17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा अर्थात् 23½° अक्षांश राज्य के दक्षिण में बाँसवाड़ा–डूँगरपुर जिलों से गुजरती है।

राज्य की पश्चिमी सीमा भारत–पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है, जो 1070 किलोमीटर लम्बी है। राज्य की उत्तरी और उत्तरी–पूर्वी सीमा पंजाब तथा हरियाणा से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से, दक्षिणी–पश्चिमी सीमा क्रमशः मध्य प्रदेश तथा गुजरात से संयुक्त है।



मानचित्र 2.1 राजस्थान : स्थिति एवं विस्तार

राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है जो भारत के कुल क्षेत्र का 10.41 प्रतिशत है। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व के अनेक देशों से बड़ा है, उदाहरण के लिये इजराइल से 17 गुना, श्रीलंका से पांच गुना, इंग्लैण्ड से दुगना तथा नार्वे, पोलैण्ड, इटली से भी अधिक विस्तार रखता है। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राज्य की उत्तर से दक्षिण लम्बाई 826 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है।

प्रशासनिक इकाईयाँ

स्वतत्रंता के पश्चात् 1956 में राजस्थान राज्य के गठन के प्रक्रिया पूर्ण हुई। वर्तमान में राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से सात संभागों, 33 जिलों और 241 तहसीलों में विभक्त किया गया है।



मानचित्र 2.2 राजस्थान की प्रशासनिक इकाईयाँ

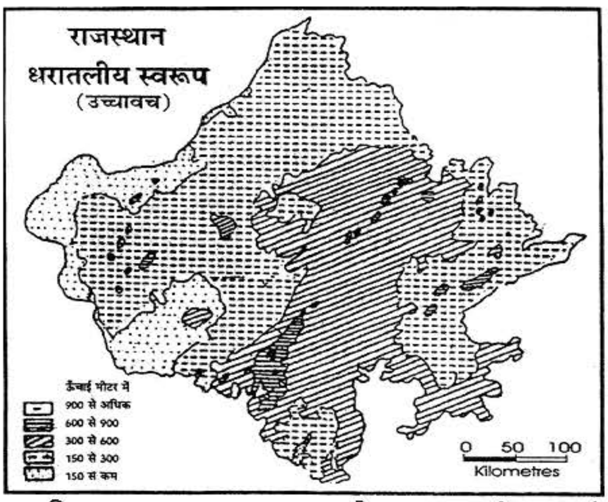
राज्य के संभाग एवं उनमें सम्मलित जिलें निम्न

प्रकार से है–

1. **जयपुर संभाग**– जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर एवं झुन्झुँनू जिले।
2. **जोधपुर संभाग**– जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही एवं जैसलमेर जिले।
3. **भरतपुर संभाग**– भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर जिले।
4. **अजमेर संभाग**– अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक एवं नागौर जिले।
5. **कोटा संभाग**– कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ जिले।
6. **बीकानेर संभाग**– बीकानेर,, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले।
7. **उदयपुर संभाग**– उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले।

उच्चावच अर्थात् धरातल (Relief) एवं धरातलीय प्रदेश

राजस्थान एक विशाल राज्य है अतः यहाँ धरातलीय विविधताओं का होना स्वाभाविक है। राज्य में पर्वतीय क्षेत्र, पठारी प्रदेश एवं मैदानी और मरूस्थली प्रदेशों का विस्तार है अर्थात् यहाँ उच्चावच सम्बन्धी विविधतायें हैं। राज्य के उच्चावच का स्वरूप मानचित्र 2.3 में प्रदर्शित है–



मानचित्र 2.3 राजस्थान धरातलीय स्वरुप (उच्चावच)

मानचित्र 2.3 से राजस्थान के उच्चावच के निम्न स्वरुप स्पष्ट होते है :

1. **उच्च शिखर –** इसके अन्तर्गत वे पर्वतीय शिखर सम्मिलित हैं जो समुद्रतल से 900 मीटर से अधिक ऊँचे हैं। ये राजस्थान के कुल एक प्रतिशत क्षेत्र से भी कम है। इसमें अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरुशिखर है जिसकी ऊँचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। दक्षिणी अरावली के अन्य उच्च शिखर सेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबू, जरगा, कुम्भलगढ़ हैं।

2. **पर्वत श्रृंखला –** इसमें 600 मीटर से 900 मीटर की ऊँचाई वाला क्षेत्र सम्मिलित है जो राज्य के लगभग 6 प्रतिशत भाग में विस्तृत है। सम्पूर्ण अरावली पर्वतमाला इसमें सम्मिलित है जो दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व तक अक्रमिक रूप में राजस्थान के मध्य भाग में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार सिरोही, उदयपुर, राजसमंद से अजमेर जिले तक है। इसके पश्चात् जयपुर और अलवर जिलों इन श्रेणियों का विस्तार अक्रमिक होता जाता है।

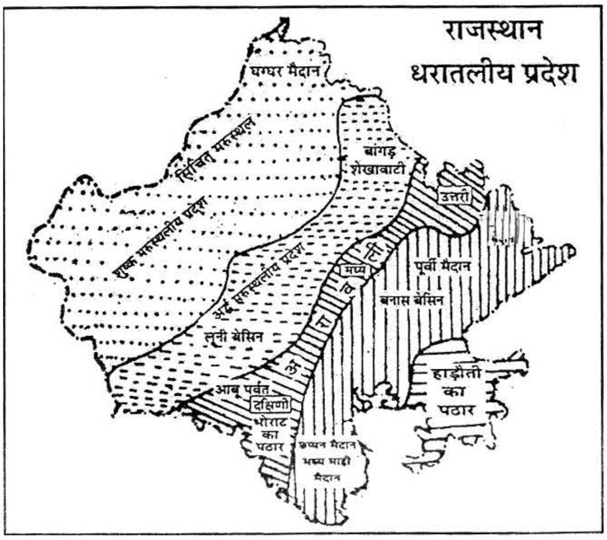
3. **उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र–** इनका विस्तार अरावली श्रेणी के दोनों ओर उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पश्चिम तथा दक्षिणी–पूर्वी पठारी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊँचाई 300 से 600 मीटर के मध्य है। यह राजस्थान के लगभग 31 प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका उत्तरी–पूर्वी भाग प्रायः समतल है जिसकी औसत ऊँचाई 400 मीटर है। जबकि दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्र उच्च भूमि है, जहाँ ऊबड़–खाबड़ धरातल है तथा औसत ऊँचाई 500 मीटर है। राज्य के दक्षिण–पूर्व में हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ जिले में भी पठारी क्षेत्र है।

4. **मैदानी क्षेत्र–** इसका विस्तार राज्य के लगभग 51 प्रतिशत भू–भाग पर है जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई 150 से 300 मीटर है। इसके दो वृहत क्षेत्र हैं : प्रथम–पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मरूस्थली क्षेत्र एवं द्वितीय– पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदान में बनास बेसिन, चम्बल बेसिन तथा छप्पन मैदान (मध्य माही बेसिन) हैं जो नदियों द्वारा निर्मित मैदान है तथा कृषि के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है।

धरातलीय प्रदेश

धरातलीय विशिष्टताओं के आधार पर राजस्थान को निम्नलिखित प्रमुख एवं उप–विभागों में विभक्त किया जाता है–

1. पश्चिमी मरूस्थली प्रदेश
2. अरावली पर्वतीय प्रदेश
3. पूर्वी मैदानी प्रदेश
4. दक्षिणी–पूर्वी पठार (हाडौती का पठार)



मानचित्र 2.4 राजस्थान धरातलीय प्रदेश

1. पश्चिमी मरूस्थली प्रदेश

राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क मरूस्थली प्रदेश है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे **'भारत का विशाल मरूस्थल'** अथवा **'थार मरूस्थल'** के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुन्झुनू, हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में है। यद्यपि गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्रीय स्वरूप में परिवर्तन आ गया है।

सम्पूर्ण पश्चिमी मरूस्थली क्षेत्र समान उच्चावच नहीं रखता अपितु इसमें भिन्नता है। इसी भिन्नता के इसको चार उप–प्रदेशों में विभिक्त किया जाता है, ये हैं–

(अ) शुष्क रेतीला अथवा मरूस्थली प्रदेश

(ब) लूनी–जवाई बेसिन

(स) शेखावाटी प्रदेश, एवं

(द) घग्घर का मैदान

(अ) शुष्क रेतीला अथवा मरूस्थली प्रदेश– यह क्षेत्र शुष्क मरूस्थली क्षेत्र है जहाँ वार्षिक वर्षा को औसत 25 से. मी. से कम है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिले एवं जोधपुर और चूरू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मलित है। इस प्रदेश में सर्वत्र बालुका–स्तूपों का विस्तार है। कुछ क्षेत्रों जैसे पोकर, जैसलमेर, रामगढ़ में चट्टानी संरचना दृष्टिगत होती है।

(ब) लूनी–जवाई बेसिन– यह एक अर्द्ध–शुष्क प्रदेश है जिसमें लूनी एवं इसकी प्रमुख जवाई तथा अन्य सहायक नदियाँ प्रवाहित है। इसका विस्तार पाली, जालौर, जोधपुर जिलों एवं नागौर जिले के दक्षिणी भागों में हैं। यह एक नदी निर्मित मैदान है जिसे **'लूनी बेसिन'** के नाम से जाना जाता है।

(स) शेखावटी प्रदेश– इसे **'बांगर प्रदेश'** के नाम से भी जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश का विस्तार झुन्झुनू, सीकर और चूरू जिले तथा नागौर जिले के उत्तरी भाग में है। यह प्रदेश भी रेतीला प्रदेश है जहाँ कम ऊँचाई के बालूका–स्तूपों का विस्तार हैं। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त (रन) हैं जिनमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तलछापर, परिहारा, कुचामन आदि प्रमुख हैं।

(द) घग्घर का मैदान– गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण घग्घर नदी के प्रवाह क्षेत्र की बाढ़ से हुआ है। वर्तमान में घग्घर नदी को 'मृत नदी' कहा जाता है क्योंकि इसका प्रवाह तल स्पष्ट नहीं है, किन्तु वर्षा काल में इसमें न केवल पानी प्रवाहित होता है, अपितु बाढ़ आ जाती है। घग्घर नदी प्राचीन वैदिक कालीन सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो चुकी है। यह सम्पूर्ण मैदानी क्षेत्र है जो वर्तमान में कृषि क्षेत्र बन गया है।

2. अरावली पर्वतीय प्रदेश

अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत

श्रेणी है जो राज्य में कर्णवत उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पश्चिम तक फैली है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर में देहली से प्रारम्भ होकर गुजरात में पालनपुर तक लगभग 692 किमी. की लम्बाई में विस्तृत है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के सात जिलों– सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में।

अरावली पर्वत प्रदेश को तीन प्रमुख उप–प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, ये हैं–

(अ) दक्षिणी अरावली प्रदेश

(ब) मध्य अरावली प्रदेश

(स) उत्तरी अरावली प्रदेश

(अ) दक्षिणी अरावली प्रदेश– इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मलित हैं। यह प्रदेश पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है, जहाँ अरावली की श्रेणियाँ अत्यधिक सघन एवं उच्चता लिये हुए हैं। इस प्रदेश में अरावली पर्वतमाला के अनेक उच्च शिखर स्थित हैं। इसमें **गुरुशिखर पर्वत** राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसकी ऊँचाई 1722 मीटर है जो सिरोही जिले में माउन्ट आबू क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की अन्य प्रमुख उच्च पर्वत चोटियाँ हैं– **सेर** (1597 मीटर), **अचलगढ़** (1380मीटर), **देलवाड़ा** (1442मीटर), **आबू** (1295 मीटर) और **ऋषिकेश** (1017मीटर)। उदयपुर–राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर **जरगा पर्वत** है जिसकी ऊँचाई 1431 मीटर है, इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियाँ **कुम्भलगढ़** (1224मीटर) **लीलागढ़** (874मीटर), **कमलनाथ की पहाड़ियाँ** (1001मीटर) तथा **सज्जनगढ़** (938 मीटर) है। उदयपुर के उत्तर–पश्चिम में कुम्भलगढ़ और गोगुन्दा के बीच एक पठारी क्षेत्र है जिसे **'भोराट का पठार'** के नाम से जाना जाता है।

(ब) मध्य अरावली प्रदेश– यह मुख्यतः अजमेर जिले में फैला है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकीर्ण घाटियाँ और समतल स्थल भी स्थित है। अजमेर के दक्षिण–पश्चिम भाग में **तारागढ़** (870 मीटर) और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ **नाग पहाड़** (795मीटर) कहलाती हैं। ब्यावर तहसील में अरावली श्रेणियों के चार दर्रे स्थित है, जिनके नाम हैं– **बर, परवेरिया और शिवपुर घाट, सूरा घाट दर्रा और देबारी।**

(स) उत्तरी अरावली प्रदेश– इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा तथा अलवर जिलों में है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियाँ अनवरत न होकर दूर–दूर होती जाती हैं। इनमें शेखावाटी की पहाडियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियों तथा जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ सम्मलित हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की सामान्य ऊँचाई 450 से 750 मीटर है। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखर सीकर जिले में **रघुनाथगढ़** (1055मीटर), अलवर में **बैराठ** (792 मीटर) तथा जयपुर में **खो** (920 मीटर) है। अन्य उच्च शिखर **जयगढ़, नाहरगढ़, अलवर किला और बिलाली** है।

3. **पूर्वी मैदानी प्रदेश–** राजस्थान का पूर्वी प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है जो अरावली के पूर्व में विस्तृत है। इसके अन्तर्गत भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक तथा भीलवाड़ा जिलों के मैदानी भाग सम्मलित है। यह प्रदेश **'नदी बेसिन'** प्रदेश है अर्थात् नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस मैदानी प्रदेश के तीन उप–प्रदेश हैं–

(अ) बनास–बाणगंगा बेसिन

(ब) चम्बल बेसिन और

(स) मध्य माही बेसिन अथवा छप्पन मैदान।

(अ) बनास–बाणगंगा बेसिन– बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह एक विस्तृत मैदान है। यह मैदान बनास और इसकी सहायक बाणगंगा, बेड़च, कोठारी, डेन, सोहाद्रा, मानसी, धुन्ध, बांडी, मोरेल, बेड़च, वागन, गम्भीर आदि नदियों द्वारा निर्मित है। यह एक विस्तृत मैदान है, जिसकी समुद्रतल से ऊँचाई 150 से 300 मीटर के मध्य है तथा ढाल पूर्व की ओर है।

(ब) चम्बल बेसिन– इसके अन्तर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों का क्षेत्र सम्मलित है। कोटा का क्षेत्र हाडौती में सम्मलित है किन्तु यहाँ चम्बल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली

एवं धौलपुर में चम्बल के बीहड़ स्थित है। यह अत्यधिक कटा–फटा क्षेत्र है, इनके मध्य समतल क्षेत्र स्थित है।

(स) मध्य माही बेसिन अथवा छप्पन मैदान– इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण–पूर्व से, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। यह माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से निकलकर इस प्रदेश से गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह क्षेत्र असमतल है तथा सर्वत्र छोटी–छोटी पहाडियाँ है। यह क्षेत्र पहाड़ियों से युक्त तथा कटा–फटा होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में **'वॉगड'** नाम से पुकारा जाता है। प्रतापगढ़ और बाँसवाड़ा के मध्य के भाग में छप्पन ग्राम समूह स्थित है अतः इसे **'छप्पन का मैदान'** भी कहते है।

4. दक्षिणी–पूर्वी पठारी प्रदेश अथवा हाडौती

राजस्थान का दक्षिणी–पूर्वी भाग एक पठारी भाग है, जिसे **'हाडौती के पठार'** के नाम से जाना जाता है। यह मालवा के पठार का विस्तार है तथा इसका विस्तार कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों में है। इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई 500 मीटर है तथा यहाँ अनेक छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनमें मुकन्दरा की पहाड़ियाँ और बूंदी की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। यहाँ चम्बल नदी और इसकी प्रमुख सहायक कालीसिंध, परवन और पार्वती नदियाँ प्रवाहित है, उनके द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश कृषि के लिये उपयुक्त है।

अपवाह तन्त्र अर्थात् नदियाँ

अपवाह तन्त्र से तात्पर्य नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों से है जो एक तन्त्र अथवा प्रारूप का निर्माण करती हैं। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी केवल चम्बल है। राजस्थान के अपवाह तन्त्र को अरावली पर्वत श्रेणियाँ निर्धारित करती है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान में एक जल विभाजक है और राज्य मे बहने वाली नदियों को दो भागों में विभक्त करती है। इसके अतरिक्त राज्य में अन्तः प्रवाहित नदियाँ भी हैं। इसी आधार पर राजस्थान की नदियों को निम्नलिखित तीन समूहों में विभक्त किया जाता हैः (मानचित्र–2.5)

1. बंगाल की खाडी में गिरने वाली नदियाँ
2. अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ
3. अन्तः प्रवाहित नदियाँ



मानचित्र 2.5 राजस्थान अपवाह तन्त्र

1. बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ

इसके अन्तर्गत **चम्बल, बनास, बाणगंगा** और इनकी सहायक नदियाँ सम्मलित हैं।

चम्बल नदी– इसको प्राचीन काल में **चर्मण्यवती** के नाम से जाना जाता था। चम्बल नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में महू के निकट मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ी से हुआ। यह राजस्थान में चौरासीगढ़ (चित्तौड़गढ़ जिला) के निकट प्रवेश कर कोटा–बूंदी जिलों की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों से होते हुए अन्त में यमुना नदी में मिल जाती है। चम्बल नदी पर गाँधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बाँध तथा कोटा बैराज बनाये गये हैं। चम्बल की प्रमुख सहायक नदियाँ **बनास, कालीसिंध और पार्वती** हैं।

बनास नदी– बनास नदी अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है जो कुम्भलगढ़ से 5 किमी. दूर है। यह **कुम्भलगढ़** से दक्षिण की ओर गोगुन्दा के पठार से प्रवाहित होती हुई नाथद्वारा, राजसंमद, रेल मगरा पार कर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिले से होती हुई सवाई माधोपुर में चम्बल से मिल

जाती है। बनास नदी को **'वन की आशा'** भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है : **बेडच, कोठारी, खारी, मैनाल, बाण्डी, धुन्ध और मोरेल।**

काली सिन्ध नदी– यह मध्य प्रदेश में देवास के निकट से निकल कर झालावाड़ और बारां जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चम्बल नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ **परवन, उजाड़, निवाज और आहू** हैं।

पार्वती नदी– मध्य प्रदेश के सिहोर क्षेत्र से निकलकर बारा जिले में बहती हुई सवाईमाधोपुर जिले में पालिया के निकट चम्बल में मिल जाती है।

वापनी (बाह्मणी) नदी – चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुर गाँव के निकट से निकलकर भैसरोड़गढ़ के निकट चम्बल में मिलती है।

मेज नदी – भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी में लाखेरी के निकट चम्बल में मिलती है।

बाणगंगा नदी – इसका उद्‌गम जयपुर जिले की बैराठ पहाड़ियों से है। यहाँ से यह पूर्व की ओर सवाई माधोपुर जिले और इसके पश्चात् भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है, जहाँ इसका जल फैल जाता है।

2. अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ

राजस्थान में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ है– **लूनी, माही और साबरमती** ।

लूनी नदी– लूनी नदी का उद्‌गम अजमेर का नाग पहाड़ है, तत्पश्चात यह जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर के क्षेत्रों में लगभग 320 कि.मी. प्रवाहित होती हुई अन्त में कच्छ के रन में चली जाती है। यह केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है। लूनी नदी की यह विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा तक मीठा है उसके पश्चात् खारा हो जाता है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ है– **जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी– प्रथम, द्वितीय** एवं **तृतीय, बाड़ी– प्रथम** एवं **द्वितीय** तथा **सागी।**

माही नदी– माही नदी मध्य प्रदेश के महू की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में बाँसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है तथा डूँगरपुर–बाँसवाड़ा जिले की सीमा बनाते हुए गुजरात में प्रवेश कर अन्त में खम्बात की खाडी में गिर जाती है। बाँसवाड़ा के निकट इस पर **'माही–बजाज सागर'** बाँध बनाया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ **सोम, जाखम, अनास, चाप** और **मोरेन** है।

साबरमती नदी– उदयपुर के दक्षिण–पश्चिम' से निकलकर उदयपुर और सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खम्भात की खाड़ी में गिरती है। प्रारम्भ में यह वाकल नदी के नाम से जानी जाती है।

3. अंतः प्रवाहित नदियाँ

राजस्थान में अनेक छोटी नदियाँ इस प्रकार की हैं, जो कुछ दूरी तक बहकर रेत अथवा भूमि में विलीन हो जाती हैं, इन्हीं को अंतः प्रवाहित नदियाँ कहते हैं। इस प्रकार की प्रमुख नदियाँ **कातली, साबी** तथा **काकानी** हैं।

कातली नदी– सीकर जिले की खण्डेला की पहाड़ियों से निकलती है। इसके पश्चात 100 किमी. दूरी तक सीकर, झुन्झुनू जिलों में बहती हुई रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है।

साबी नदी– जयपुर की सेवर की पहाडियों से निकलकर बानासूर, बहरोड, किशनगढ़, मण्डावर एवं तिजारा तहसीलों में बहती हुई हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है।

काकानी अथवा काकनेय नदी– जैसलमेर से लगभग 27 किमी. दक्षिण में कोटरी गाँव से निकलकर कुछ किलोमीटर बहने के पश्चात् विलुप्त हो जाती है।

घग्घर नदी– यह एक विशिष्ट नदी है जिसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। यह हरियाणा से निकलकर हनुमानगढ़, गंगानगर सूरतगढ़, अनूपगढ़ से होते हुए उसका जल पाकिस्तान में चला जाता है। इसमें वर्षाकाल में जल आता है जो सर्वत्र फैल जाता है। इस नदी को मृत नदी कहते हैं। वर्तमान में इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में **'नाली'** कहते हैं।

उक्त अंतः प्रवाहित नदियों के अतिरिक्त बाणगंगा और सांभर झील क्षेत्र की नदियाँ आन्तरिक प्रवाहित श्रेणी की हैं।

झीलें

राजस्थान में अनेक झीलें हैं, उन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, ये हैं –

(अ) खारे पानी की झीलें एवं

(ब) मीठे पानी की झीलें

इनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है।

(अ) खारे पानी की झीलें

राजस्थान के पश्चिमी मरूस्थली क्षेत्र तथा अंतः प्रवाह वाले क्षेत्रों में अनेक खारे पानी की झीलें हैं। इनमें **सांभर, डीडवाना, पचपद्रा** और **लूनकरनसर झील** प्रमुख हैं।

(1) **सांभर झील**– जयपुर जिले में जयपुर से लगभग 65कि.मी. पश्चिम में सांभर झील न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख खारे पानी की झील है। इस झील के पानी से नमक उत्पादित होता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किमी. में है।

(2) **डीडवाना झील**– नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट यह खारे पानी की झील है। इस झील के जल से सोडियम लवण तैयार किया जाता है।

(3) **पचपद्रा झील**– बाड़मेर जिले के पचपद्रा नामक स्थान पर यह खारे पानी की झील है।

(4) **लूनकरनसर झील**– बीकानेर से लगभग 80 किमी. दूर लूनकरसर में यह झील स्थित है।

उपर्युक्त प्रमुख खारे पानी की झीलों के अतरिक्त कुछ छोटी झीलें **फलोदी, कुचामण, कावोद, कछोर, रेवासा** आदि में हैं।

(ब) मीठे पानी की झीलें

राजस्थान प्रदेश के लिये मीठे पानी की झीलों का विशेष महत्व है क्योंकि राज्य में पानी की कमी है और मीठे पानी की झीलें पेय जल तथा सीमित रूप में सिंचाई हेतु जल प्रदान करती हैं। राज्य में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें भी है तथा अनेक झीलों का निर्माण बांध द्वारा पानी को रोक कर किया गया। राज्य में मीठे पानी की झीलें अनेक जिलों में स्थित है। यहॉं राज्य की प्रमुख एवं प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

(1) **जयसमंद झील**– इसका निर्माण वर्ष 1685–91 में महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनवाकर कराया गया था। यह झील उदयपुर से 51 किमी. दक्षिण–पूर्व में स्थित है। इसको **'ढेबर–झील'** के नाम से भी पुकारा जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

(2) **राजसमंद झील**– इसका निर्माण महाराणा राजसिंह ने सन् 1662 में कराया था। यह झील उदयपुर से 64किमी. दूर राजसमंद जिले में स्थित है। इस झील के किनारे सुन्दर घाट और नौ चौकी है, जहाँ संगमरमर के शिला लेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में अंकित है।

(3) **पिछोला झील**– उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पिछोला झील है। इस झील के दो टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास नाम के सुन्दर महल बने हुए है।

(4) **फतह सागर झील**– उदयपुर नगर से सटी हुई फतेह सागर झील, पिछोला झील के उत्तर–पश्चिम में है जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था।

(5) **आना सागर झील**– अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह आनाजी ने करवाया था। इसके किनारे एक उद्यान 'दौलत बाग' एवं इसके तट पर सुन्दर संगमरमर की छतरियॉं (बारादरी) हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है।

(6) **पुष्कर झील**– अजमेर से 11 किमी. दूर पर्वतों से आवृत पुष्कर झील है। यह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व की है तथा पर्यटकों के लिए दर्शनीय है।

(7) **सिलीसेढ़ झील**– अलवर नगर से लगभग 12 किमी दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य यह सुरम्य झील है।

उपुर्यक्त झीलों के अतिरिक्त **नवलखा झील** (बूंदी), **कोलायत झील** (कोलायत–बीकानेर), **शैव सागर** (डूँगरपुर), **गलता एवं रामगढ़** (जयपुर), **बालसमंद झील** (जोधपुर), **कैलाना झील** (जोधपुर), भरतपुर का **बैरठा बांध** तथा

धौलपुर का **तालाबशाही** भी प्रसिद्व है।

जलवायु

राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप–आर्द्र मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापान्तर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्द्धशुष्क एवं उप–आर्द्र जलवायु है। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्रतल से ऊँचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा, वनस्पति आवरण आदि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं।

राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेशताएँ हैं:

(1) शुष्क एवं अर्द्ध–शुष्क जलवायु की प्रधानता।

(2) अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा।

(3) वर्षा का असमान वितरण।

(4) अधिकांश वर्षा जून से सितम्बर तक।

(5) वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण सूखा एवं अकाल की स्थिति अधिक होना, आदि।

जलवायु का ऋतु प्रारूप

भारतीय जलवायु के समान, राजस्थान की जलवायु का अध्ययन भी ऋतुओं के अनुसार किया जाता है। राज्य की जलवायु का स्वरूप निम्नलिखित तीन ऋतुओं से स्पष्ट होता है–

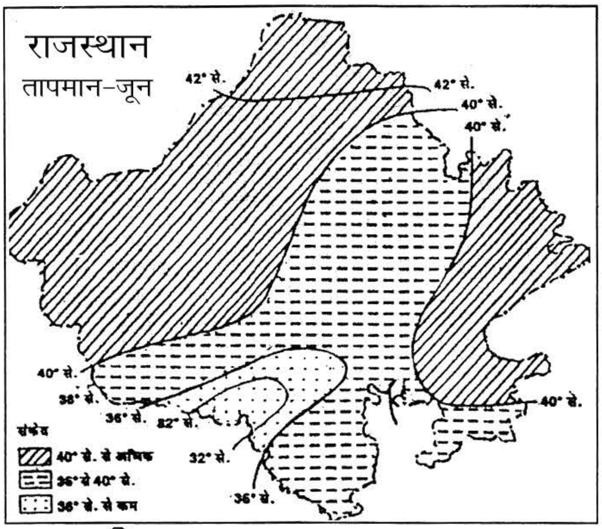
(अ) ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मध्य जून)

(ब) वर्षा ऋतु (मध्य जून से सितम्बर)

(स) शीत ऋतु (अक्टूबर से फरवरी)

(अ) ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मध्य जून)

ग्रीष्म ऋतु का प्रारम्भ मार्च से हो जाता है और इस समय सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगती है। मई–जून में सम्पूर्ण राजस्थान में उच्च तापमान हो जाता है जैसा कि मानचित्र 2.6 से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण राजस्थान विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू आदि में 40° से. से अधिक होता है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर तथा अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, में तापमान 36° से. से 40° से. होता। दक्षिणी अरावली के उच्च भागों में ऊँचाई के कारण तापमान कम होता हैं। हाड़ौती का पठार भी इस समय तपता रहता है और वहाँ तापमान 36° से. से 40° से. के मध्य होता है। इस समय गर्म और धूल भरी आँधियों का प्रकोप होता हैं। शुष्क प्रदेशों में रात्रि तापमान कम हो जाता है। इस समय हवा में नमी कम होती है और सम्पूर्ण राज्य गर्मी की चपेट में होता है।



मानचित्र 2.6 राजस्थान जून का तापमान

(ब) वर्षा ऋतु (मध्य जून से सितम्बर) :

मध्य जून तक सम्पूर्ण राज्य जब ग्रीष्म से तप्त हो जाता है तो वायुदाब एवं हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन के साथ ही हिन्द महासागर से मानसूनी हवाओं का प्रारम्भ हो जाता हैं राजस्थान में जून के अन्त में अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दक्षिणी और दक्षिणी–पूर्वी तथा पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से सक्रीय हो जाता है। मानसूनी वर्षा राजस्थान को अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि–

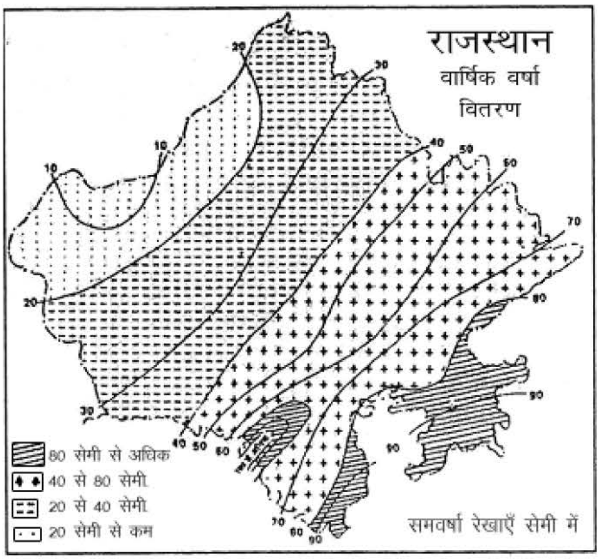
(1) अरावली पर्वत शृंखला का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा की दिशा के समानान्तर होने के कारण मानसून राज्य में बिना वर्षा के उत्तर की तरफ चला जाता है।

(2) बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाले मानसून

की राजस्थान में पहुँचते–पहुँचते आर्द्रता काफी कम हो जाती है।

(3) अरावली पर्वतमाला की ऊँचाई कम होने तथा उस पर वनस्पति कम होने का भी वर्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

किन्तु इससे यह तात्पर्य नहीं कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती। जून से सितम्बर तक राजस्थान में अधिकांशतः वर्षा होती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा का वितरण मानचित्र 2.7 में प्रदर्शित है।



मानचित्र 2.7 राजस्थान वार्षिक वर्षा का वितरण

राजस्थान में वर्षा के वितरण मानचित्र से स्पष्ट है कि 40 से.मी. की वर्षा मापक रेखा इसे दो भागों में विभक्त करती है। इसके पश्चिम का भाग जहाँ 40 से.मी. से कम वर्षा होती है। वह मरूस्थली है, दूसरी ओर पूर्वी एवं दक्षिणी–पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा आबू पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 150 से.मी. होती है। कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, सिरोही में वार्षिक वर्षा का औसत 90 सेमी रहता है। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर हैं जहाँ वर्षा 10 से 25 से.मी. तक होती है।

(स) शीत ऋतु (अक्टूबर से फरवरी तक)

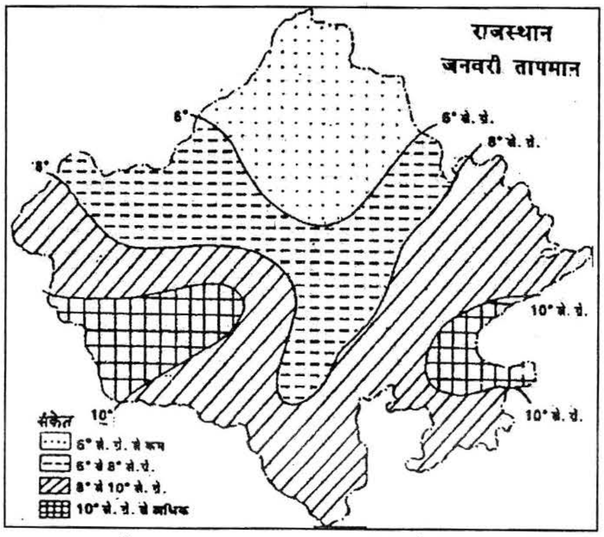
शीत ऋतु को दो भागों में विभक्त किया जाता है–

(1) मानसून के प्रत्यावर्तन का काल (अक्टूबर से मध्य सितम्बर)

(2) शीत ऋतु (मध्य दिसम्बर से फरवरी तक)

वर्षा ऋतु का समापन एकाएक न होकर क्रमिक रूप से होता है और मानसूनी हवाएँ अक्टूबर से वापस लौटने लगती है। इस समय अधिकतम तापमान 30^0 से 35^0 से. और न्यूनतम 20^0 से. तक होता है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन अर्थात् लौटने का समय होता है। लौटता मानसून भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा कर देता है।

वास्तविक शीत ऋतु का प्रारम्भ राज्य मे दिसम्बर माह में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणानय में होता है। उत्तरी–पश्चिमी ठण्डी हवाएँ पूरे राज्य में चलने लगती हैं। इस समय पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात भी प्रदेश में आते है जिनसे कुछ वर्षा हो जाती है, इस वर्षा को **'मावठ'** कहते है। यह वर्षा रबी की फसल के लिये वरदान होती है। जनवरी के माह में शीतकाल पूर्णता पर होता है। सम्पूर्ण प्रदेश में तापमान 5^0 से 15^0 से. होता है। चूरू, फलोदी, गंगानगर में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस समय बाडमेर, कोटा, बूंदी तथा दक्षिणी सवाई माधोपुर जिलों में तापमान 10^0 से अधिक होता है। राजस्थान में जनवरी के तापमान के वितरण का स्वरूप मानचित्र 2.8 में प्रदर्शित किया गया है।



मानचित्र 2.8 राजस्थान जनवरी तापमान

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजस्थान का भौतिक पर्यावरण विशिष्ट है। राज्य के भौतिक विभागों में

उच्चावच एवं जलवायु की अत्यधिक विविधता है। यहाँ के भौतिक पर्यावरण ने सदैव से आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप को प्रभावित किया है और वर्तमान में भी कर रहा है। राज्य की विकास योजनाओं पर भी इनका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान का क्षेत्रफल है–
   (अ) 3.5 लाख वर्ग किमी
   (ब) 3.4 लाख वर्ग किमी
   (स) 3.6 लाख वर्ग किमी
   (द) 3.2 लाख वर्ग किमी
2. क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौनसा स्थान है?–
   (अ) प्रथम (ब) द्वितीय
   (स) तृतीय (द) चतुर्थ
3. राजस्थान में कितने संभाग है?
   (अ) 5 (ब) 6
   (स) 7 (द) 8
4. क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है–
   (अ) जयपुर (ब) जैसलमेर
   (स) कोटा (द) जोधपुर
5. अरावली का सर्वोच्च शिखर है–
   (अ) तारागढ़ (ब) अचलगढ़
   (स) गुरु शिखर (द) जरगा
6. राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है?
   (अ) दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व
   (ब) दक्षिण–पूर्व से उत्तर–पश्चिम
   (स) उत्तर से दक्षिण
   (द) पश्चिम से पूर्व
7. हाडौती के पठार में कौन से जिले सम्मलित है?
   (अ) उदयपुर–डूंगरपुर–बाँसवाड़ा
   (ब) कोटा–बूंदी–बारां–झालावाड़
   (स) भीलवाड़ा–टोंक–चित्तौड़गढ–बून्दी
   (द) अजमेर–नागौर–पाली–जोधपुर
8. काली सिन्ध नदी किस की सहायक है?
   (अ) बनास (ब) माही
   (स) लूनी (द) चम्बल
9. निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है?
   (अ) सांभर (ब) पिछोला
   (स) डीडवाना (द) लूनकरनसर
10. राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है–
    (अ) कोटा (ब) बांसवाड़ा
    (स) सिरोही (द) अलवर

अतिलघूउत्तरात्मक प्रश्न

1. राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अधिकतम लम्बाई–चौड़ाई बताइये।
2. खारे पानी की तीन झीलों के नाम लिखिये।
3. राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है?
4. साबरमती नदी कहाँ से निकलती है?
5. राजस्थान की जलवायु कैसी है?
6. **'मावठ'** किसे कहते है?

लघूउत्तरात्मक प्रश्न

1. पश्चिमी मरूस्थली प्रदेश का विस्तार किन जिलों में है?
2. अरब सागरीय अपवाह तन्त्र की नदियों के बारे में बताइये।
3. राजस्थान में कम वर्षा होने के क्या कारण है?
4. राजस्थान के मुख्य भौतिक विभाग कौनसे है?
5. राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें कौनसी है?
6. राजस्थान की जलवायु की चार विशेषतायें बताइये?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. राजस्थान के धरातलीय प्रदेशों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
2. अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्णन कीजिये।
3. राजस्थान के मैदानी एवं पठारी क्षेत्र का वर्णन कीजिये।
4. राजस्थान की नदियों का सचित्र वर्णन कीजिये।
5. राजस्थान की जलवायु का ऋतुओं के अनुसार विवेचन कीजिये।

❑❑❑❑

अध्याय–3
राजस्थान की कला एवं संस्कृति

राजस्थान को सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के समृद्ध प्रदेशों में गिना जाता है। संस्कृति एक विशाल सागर है जिसे सम्पूर्ण रूप से लिखना संभव नहीं है। संस्कृति तो गाँव–गाँव, ढांणी–ढांणी, चौपाल, चबूतरे, महल–प्रासादों मे ही नहीं, वह तो घर–घर, जन–जन में समाई हुई है। राजस्थान की संस्कृति का स्वरूप रजवाडों और सामन्ती व्यवस्था में देखा जा सकता है, फिर भी इसके वास्तविक रूप को बचाए रखने का श्रेय ग्रामीण अंचल को ही जाता है, जहाँ आज भी यह संस्कृति जीवित है। संस्कृति में साहित्य और संगीत के अतिरिक्त कला–कौशल, शिल्प, महल–मंदिर, किले–झोंपडियों का भी अध्ययन किया जाता है, जो हमारी संस्कृति के दर्पण है। हमारी पोशाक, त्यौहार, रहन–सहन, खान–पान, तहजीब–तमीज सभी संस्कृति के अन्तर्गत आते है। थोड़े से शब्दों में कहा जाए तो जो ' मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वह संस्कृति है।

ऐतिहासिक काल में राजस्थान में कई राजपूत वंशों का शासन रहा है। यहाँ सभी शासकों ने अपने राज्य की राजनैतिक एकता के साथ–साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति में योगदान दिया है। ग्याहरवीं शताब्दी में उत्तर–पश्चिम से आने वाली आक्रमणकारी जातियों ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया, परन्तु निरन्तर संघर्ष के वातावरण मे भी यहाँ साहित्य, कला की प्रगति अनवरत रही। मध्य काल में राजपूत शासकों के मुगलों के साथ वैवाहिक और मैत्री संबन्धों से दोनों जातियों में सांस्कृतिक समन्वय और मेल–मिलाप रहा जिससे कला, साहित्य में विविधता एंव नवीनता का संचार हुआ और सांझी संस्कृति का निर्माण हुआ।

सांझी संस्कृति

राजस्थान के भू–भाग पर आक्रमणों एवं युद्धों का दौर लम्बे समय तक चलता रहा। राजस्थानी जनजीवन में समन्वय एवं उदारता के गुणों ने सांझी संस्कृति को पनपने का अवसर प्रदान किया। धार्मिक सहिष्णुता के परिणामस्वरूप अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हिन्दू–मुस्लिम एकता के दर्शन होते हैं, जहाँ सभी धर्म के अनुयायी एकत्र होकर इबादत (प्रार्थना) करते हैं और मन्नत मांगते है। लोक देवता गोगाजी, रामदेवजी के समाधि स्थल पर सभी धर्मानुयायी अपनी आस्था रखकर साम्प्रदायिक सद्‌भावना का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

राजस्थान के सामाजिक जीवन यथा खान–पान, रहन–सहन, आमोद–प्रमोद और रस्मों–रिवाजों में सर्वत्र हिन्दू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय हुआ है। भोजन में अकबरी जलेबी, खुरासानी खिचड़ी, बाबर बड़ी, पकौड़ी और मूंगोड़ी का प्रचलन मुगली प्रभाव से खूब पनपा है। पस्धिानों में मलमल, मखमल, नोरंगशाही, बहादुरशाही कपड़ों का प्रयोग हुआ है। आमोद–प्रमोद में पतंगबाजी, कबूतर बाजी मुगल काल से प्रचलित हुई है।

स्थापत्य कला में हिन्दू–मुस्लिम शैलियों का सम्मिश्रण सांझी संस्कृति का उदाहरण हैं। यहाँ के राजा–महाराजाओं ने मुगली प्रभाव से स्थापत्य निर्माण में संगमरमर का प्रयोग किया। गेलेरियों, फव्वारों, छोटे बागों को महत्व दिया। दिवारों पर बेल बूंटे के काम को बढ़ावा दिया। चित्रकला की विभिन्न शैलियों में मुगल शैली का प्रभाव सर्वत्र देखा जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि राजस्थानी कला एवं संस्कृति में सांझी संस्कृति के वे सभी तत्त्व मौजूद है जो अपने मूलभूत स्वरूप को बनाए रखते हुए भी नवीनता, ग्रहणशीलता, सहिष्णुता और समन्वय को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं।

मध्यकालीन साहित्यिक उपलब्धियाँ

राजस्थान में साहित्य प्रारम्भ में संस्कृत व प्राकृतभाषा में रचा गया। मध्ययुग के प्रारम्भकाल से अपभ्रंश और उससे जनित मरूभाषा और स्थानीय बोलियां जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूँढाड़ी और बागड़ी में साहित्य की रचना होती रही, परन्तु इस काल में संस्कृत साहित्य अपनी प्रगति करता रहा।

संस्कृत साहित्य

राजपूताना के विद्यानुरागी शासकों, राज्याश्रय प्राप्त विद्वानों ने संस्कृति का सृजन किया है। शिला लेखों, प्रशस्तियों और वंशावलियों के लेखन में इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। महाराणा कुम्भा स्वयं विद्वान संगीत प्रेमी एवं विद्वानों के आश्रयदाता शासक थे। इन्होंने संगीतराज, सूढ़ प्रबन्ध, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, (गीत गोविन्द की टीका) संगीत रत्नाकर आदि ग्रन्थों की रचना की थी। इनके आश्रित विद्वान मण्डन ने शिल्पशास्त्र से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों की रचना की। जिनमें देवमूर्तिप्रकरण, राजवल्लभ, रूपमण्डन, प्रसाद मण्डन महत्त्वपूर्ण कुंभाकालीन (चित्तौड़गढ़) और कुंभलगढ़ प्रशस्ति (कुंभलगढ़) की रचना की। राणा जगतसिंह एवं राजसिंह के दरबार में बाबू भट्ट तथा रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान थे, जिन्होंने क्रमशः जगन्नाथराम प्रशस्ति और राजसिंह प्रशस्ति की रचनाएँ की। ये दोनों प्रशस्तियाँ मेवाड़ के इतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण है।

आमेर–जयपुर के महाराजा मानसिंह, सवाईजयसिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवन्तसिंह, अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ तथा पृथ्वीराज तृतीय बीकानेर के रायसिंह और अनूपसिंह संस्कृत के विद्वान एवं विद्वानों के आश्रयदाता शासक थे। अनूपसिंह ने बीकानेर में 'अनूप संस्कृत पुस्तकालय' का निर्माण करवाकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। विग्रहराज चतुर्थ ने 'हरिकेलि' नाटक लिखा, पृथ्वीराज के कवि जयानक 'पृथ्वीराजविजय' नामक काव्य के रचयिता थे। प्रतापगढ़ के दरबारी पंडित जयदेव का 'हरिविजय' नाटक तथा गंगारामभट्ट का 'हरिभूषण' इस काल की प्रसिद्ध रचनाएँ है। मारवाड़ के जसवन्तसिंह ने संस्कृत में भाषा–भूषण और आनन्द विलास नामक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखें। जोधपुर के मानसिंह ने नाथ–चरित्र, नामक ग्रंथ लिखा। मानसिंह को पुस्तकों से इतना प्रेम था कि उन्होंने काशी, नेपाल आदि से संस्कृत के अनेक ग्रंथ मंगवाकर अपने पुस्तकालय में सुरक्षित रखें। आज यह पुस्तकालय मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र के रूप में विख्यात है।

राजस्थानी साहित्य

राजस्थानी समस्त राजस्थान की भाषा रही है जिसके अन्तर्गत मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूढाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी, मालवी और मेवाती आदि बोलियाँ आती है। इस भाषा में जैनशैली, चारणशैली, संतशैली और लोकशैली में साहित्य का सृजन हुआ है।

(1) जैनशैली का साहित्य – जैनशैली का साहित्य जैन धर्म से सम्बन्धित है। इस साहित्य में शान्तरस की प्रधानता है। हेमचन्द्र सूरी (ग्यारहवीं सदी) का 'देशीनाममाला', 'शब्दानुशासन', ऋषिवर्धन सूरी का 'नल दमयन्ती रास', धर्म समुद्रगणि का 'रात्रि भोजनरास', हेमरत्न सूरी का गौरा बादल री चौपाई प्रमुख साहित्य हैं।

(2) चारणशैली का साहित्य – राजपूत युग के शौर्य तथा जनजीवन की झांकी इसी साहित्य की देन है। इसमें वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। चारणशैली में रास, ख्यात, दूहा आदि में गद्य, पद्य रचनाएँ हुई है। बादर ढाढी कृत 'वीर भायण' चारण शैली की प्रारम्भिक रचना है। चन्दवरदाई का 'पृथ्वीराजरासों', नेणसी की 'नेणसीरीख्यात', बाँकीदास की 'बाँकीदासरीख्यात,' दयालदास की 'दयालदासरी ख्यात' गाडण शिवदास की 'अचलदास खींची री वचनिका' प्रमुख ग्रन्थ हैं जिनमें राजस्थान के इतिहास की झलक मिलती है। दोहा छन्द में ढोलामारू रा दूहा, सज्जन रा दूहा प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त दुरसा आढा का नाम भी विशिष्ठ उल्लेखनीय है। वह हिन्दू

संस्कृति और शौर्य का प्रशंसक तथा भारतीय एकता का भक्त था। बीकानेर नरेश कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ ने 'वेलि क्रिसन रूकमणी री' नामक ग्रंथ की रचना की, जो राजस्थानी साहित्य का ग्रन्थ माना जाता है। इन गुणों की ध्वनि इसके गीतों, छन्दों, झुलका तथा दोहा में स्पष्ट सुनाई देती है। सूर्यमल्ल मीसण आधुनिक काल का महाकवि था और बून्दी राज्य का कवि था। इसने 'वंश भास्कर' और 'वीर सतसई' जैसी उल्लेखनीय कृतियों की रचना की।

(3) सन्त साहित्य – राजस्थान के जनमानस को प्रभावित करने वाला सन्त साहित्य बड़ा मार्मिक है। सन्तों ने अपने अनुभवों को भजनों द्वारा नैतिकता, व्यावहारिकता को सरलता से जनमानस में प्रसारित किया है, ऐसे सन्तों में मल्लीनाथजी, जांभो जी, जसनाथ जी, दादू की वाणी, मीरा की 'पदावली' तथा 'नरसीजी रो माहेरो', रामचरण जी की 'वाणी' आदि संत साहित्य की अमूल्य धरोहर है।

(4) लोक साहित्य – लोक साहित्य में लोकगीत, लोकगाथाएँ, प्रेमगाथाएँ, लोकनाट्य, पहेलियाँ, फड़ें तथा कहावतें सम्मिलित है। राजस्थान में फड़ बहुत प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण वस्त्र पर किया जाता है। जिसके माध्यय से किसी ऐतिहासिक घटना अथवा पौराणिक कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फड़ में अधिकतर लोक देवताओं यथा पाबूजी, देवनारायण रामदेवजी इत्यादि के जीवन की घटनाओं और चमत्कारों का चित्रण होता है। फड़ का उपयोग चारण, भोपे करते हैं। राजस्थान में शाहपुरा (भीलवाड़ा) का फड़ चित्रण राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाये हुए है। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रण को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहयोग किया। इस कार्य हेतु भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। इनमें पाबूजी री फड़, 'देवजी री फड़' तीज, गणगौर, शादी, संस्कारों, मेलों पर गाये जाने वाले लोकगीत आते है।

स्थापत्य कला

मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना स्वतन्त्र स्थान है। मध्ययुगीन राजस्थान के स्थापत्य में राजप्रासाद, मन्दिरों और दुर्गों का निर्माण महत्वपूर्ण है। इस युग में स्थापत्य कला की एक विशेष शैली का विकास हुआ, जिसे हिन्दू स्थापत्य शैली कहा जाता है। इस शैली की प्रमुख विशेषताएँ थी–शिल्प सौष्ठव, सुदृढ़ता, अलंकृत पद्धति, सुरक्षा, उपयोगिता, विशालता और विषयों की विविधता आदि। मुगलसत्ता के साथ समागम के पश्चात् राजस्थानी स्थापत्य में तुर्की और मुगल प्रभाव से नई शैली का विकास हुआ जिसे हिन्दू–मुस्लिम स्थापत्य शैली कहा गया है।

दुर्गस्थापत्य – राजस्थान राजाओं का स्थान रहा है जहाँ राजा हो या सामंत दुर्ग निर्माण को आवश्यक मानते थे। दुर्गों का निर्माण निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण के लिए और आक्रमण के समय जनता, पशु तथा सम्पत्ति के संरक्षण हेतु किया जाता था। अधिकांश दुर्गों का निर्माण सामरिक महत्व के स्थानों पर किया गया ताकि आक्रमणकारियों से प्रदेश की सुरक्षा हो, तथा व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रह सकें।

दुर्ग निर्माण ऊँची एवं चौड़ी पहाड़ियों पर किया जाता था, जहाँ कृषि एवं सिंचाई के साधन उपलब्ध रहते थे। दुर्गों की प्रमुख विशेषताएँ थी। 1. सुदृढ़ प्राचीरें 2. विशाल परकोटा 3. अभेद्य बुर्जे 4. दुर्ग के चारों ओर गहरी नहर या खाई 5. दुर्ग के भीतर शास्त्रागार की व्यवस्था 6. जलाशय 7. मन्दिर निर्माण 8. पानी की टंकी की व्यवस्था 9. अन्नभण्डार की स्थापना 10. गुप्तप्रवेश द्वार रखा जाना 11. सुरंग निर्माण 12. राजप्रासाद एवं सैनिक विश्राम गृहों की व्यवस्था आदि।

चित्तौड का दुर्ग सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग है, जिसे महाराणा कुम्भा ने द्वारों की श्रृंखला और बुर्जों के निर्माण से सुदृढ़ बनाया । इसके बारे में प्रसिद्ध है गढ़ तो चित्तौढ़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। कुम्भा द्वारा ही कुम्भलगढ़ दुर्ग का

निर्माण कराया गया जो विशाल और ऊँची पहाड़ी पर सुदृढ़ द्वारों तथा प्राचीरों से सुरक्षित है। परमारों का जालोर दुर्ग, चौहानों का अजमेर में तारागढ़ दुर्ग तथा रणथम्भौर दुर्ग, हाड़ाओं द्वारा निर्मित बून्दी का तारागढ़, राव जौधा का जोध पुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, कछवाहों का जयपुर के पास आमेर दुर्ग नाहरगढ़ दुर्ग तथा जयगढ़ दुर्ग उत्कृष्ठ गिरी दुर्ग हैं। परमारों का झालावाड़ के निकट गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। महारावल जैसलदेव का जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित मरूस्थलीय दुर्ग है। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, भरतपुर का दुर्ग समतल मैदान पर निर्मित चौड़ी खाई से घिरा हुआ है। राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध दुर्गों में माण्डलगढ़ — भीलवाड़ा, अचलगढ़ — आबू, रणथम्बोर — सवाई माधोपुर, बयाना–भरतपुर, सिवाना–बाड़मेर, भटनेर–हनुमानगढ़ आदि है।

राजप्रासाद (महल)– राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ ही राजप्रसादों का निर्माण होने लगा था। राजप्रासाद या महल दो भागों पुरूष कक्ष तथा अन्तपुर, (जनानाकक्ष), में विभाजित होते थे। महलों में आवास कक्ष, शस्त्रागार, धान्यभण्डार, रसोई घर और पूजागृह होते थे। सादगी, नीची छतें, पतली गेलेरियाँ, छोटे–छोटे कक्ष और ढालान महलों की प्रमुख विशेषताएँ होती थी।

मुगल–राजपूत सम्बन्धों के प्रभाव से महलों में फव्वारे, छोटे बाग, गुम्बद, पतले खम्बे, मेहराब आदि नई विधाओं का प्रयोग होने लगा। कुम्भलगढ़ और चित्तौड़ के महल सादगी के नमूने है। उदयपुर के अमरसिंह के महल, जगनिवास, जगमन्दिर, जोधपुर के फूल महल, आमेर के दिवाने–आम, दिवाने–खास, बीकानेर के रंगमहल, कर्णमहल, शीशमहल, अनूपमहल तथा कोटा और जैसलमेर के महलों में मुगलस्थापत्य का प्रभाव दिखाई देता है।

मन्दिर स्थापत्य — राजस्थान में मन्दिर स्थापत्य का प्रारम्भ प्राचीनकाल से माना जाता है। तेहरवीं शताब्दी तक मन्दिर स्थापत्य में शक्ति एवं शौर्य का रणकपुर के जैन मन्दिर में दुर्ग स्थापत्य का प्रभाव है।

इसी काल के जैन धर्म के मन्दिर देलवाड़ा माउन्ट आबू में है। यहाँ पहला मन्दिर विमलशाह द्वारा बनवाया गया है, इस मन्दिर में आदिनाथ की मूर्ति है, जिनकी ऑखों में हीरे लगे हुए है। दूसरा मन्दिर वस्तुपाल और तेजपाल द्वारा बनवाया गया है। जिसमें 'नेमिनाथ' की मूर्ति है, यह मन्दिर तक्षणकला की दृष्टि से अपूर्व है। चितौड़ का सूर्य मन्दिर एवं बाडौली(चित्तौड़गढ़) के शिव मंदिर भी बड़े महत्त्व के है। डुंगरपुर के श्री नाथजी के मन्दिर, उदयपुर के जगदीश मन्दिर में हिन्दू स्थापत्य की प्रधानता है, जबकि जोधपुर के घनश्याम मन्दिर तथा आमेर के जगत शिरोमणि मन्दिर में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। 17वीं तथा 18वीं सदी में मुगल आक्रमणों के बचाव में श्री नाथजी(नाथद्वारा), द्वाराकाधीश (कांकरोली), मथुरेशजी (कोटा), गोविन्ददेव जी(जयपुर) के मन्दिरों का निर्माण राजपूत शासकों द्वारा करवाया गया था।

भवनस्थापत्य – (अ) हवेलियाँ – राजस्थान में भवन स्थापत्य का विकास हवेलियों के निर्माण से हुआ है। राजस्थान के अनेक नगरों में सेठ और सामन्तों ने भव्य हवेलियों का निर्माण करवाया था। इनमें प्रमुख द्वार के अगल–बगल कलात्मक गवाक्ष, लम्बी पोल, चौड़ा चौक और चौक के अगल–बगल भव्य कमरे होते थे। जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र में रामगढ़, नवलगढ़, फतहपुर, मुकुन्दगढ़, मण्डावा, पिलानी, सरदारशहर, रतनगढ़, सुजानगढ़ में बनी हवेलियाँ भवन स्थापत्य का उत्कृष्ठतम उदाहरण है।

जैसलमेर में सालिमसिंह, नथमल तथा पटवों की हवेलियाँ पत्थर की जाली एवं नक्काशी के कारण विश्व पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। इसी प्रकार वंशी पत्थर से निर्मित करौली, कोटा, भरतपुर की हवेलियां अपनी कलात्मक संगतराशि की दृष्टि से उत्कृष्ठ है।

(ब) विजय स्तम्भ (चित्तौड़गढ़) – महाराणा कुम्भा द्वारा मालवा के सुल्तान पर विजय की स्मृति में बनवाया गया विजय स्तम्भ जिसे कीर्तिस्तम्भ भी कहा जाता है भवन स्थापत्य का अद्‌भुत नमूना है। 122 फिट उँचे स्तम्भ में नो मंजिले है, तथा इसके अन्दर उपर जाने के लिए सीढ़ियाँ

बनी हुई है। हर मंजिल पर चारों ओर झरोखे बने है तथा हिन्दू देवताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया गया है।

(स) समाधियाँ (छतरियां) – देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शासकों, सामन्तों और सेनानायकों की स्मृति मे समाधियों पर छतरियां बनायी गई जिन्हे देवलिया या देवल कहा जाता था। गेटोर (जयपुर), आहड़ (उदयपुर), जसवन्तथड़ा (जोधपुर), छत्रविलासबाग (कोटा), और बड़ाबाग (जैसलमेर) में बनी छतरियाँ भवन स्थापत्य और मन्दिर स्थापत्य का अद्भुत समन्वय है।

चित्रकला

राजस्थानी चित्रकला का उद्भवकाल पन्द्रहवीं शताब्दी माना जाता है। राजपूतकाल में भित्तिचित्र, पोथीचित्र, काष्ठपट्टिका चित्र और लघुचित्र बनाने की परम्परा रही है। अधिकांश रियासतों के चित्र बनाने के तोर–तरीकों, स्थान के अनुसार मौलिकता और सामाजिक–राजनैतिक परिवेश के कारण अनेक चित्रशैलियों का विकास हुआ यथा–मेवाड़, मारवाड़, बून्दी, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़ और कोटा चित्रशैली। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारम्भिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में दिखाई देता है, इसलिए इसे राजस्थानी चित्रशैलियों की जनक शैली कहा जाता है। 1260 में चित्रित श्रावक प्रतिक्रमणसूत्रचूर्णि नामक चित्रित ग्रंथ इसी शैली का प्रथम उदाहरण है।

मेवाड़ शैली – मेवाड़ राज्य राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केन्द्र माना जा सकता है। महाराणा अमरसिंह के शासनकाल में इस चित्रशैली का अधिक विकास हुआ। लाल:पीले रंग का अधिक प्रयोग, गरूड़नासिका, परवल की खड़ी फांक से नेत्र, घुमावदारवलम्बी अंगुलिया, अंलकारों की अधिकता और चेहरों की जकड़न आदि इस शैली की प्रमुख विशेषताएँ हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों का विषय श्रीमद्‌भागवत्, सूरसागर, गीतगोविन्द, कृष्णलीला, दरबार के दृश्य, शिकार के दृश्य आदि थे। इस चित्रशैली के चित्रकारों में मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, साहिबदीन और जगन्नाथ प्रमुख हैं। राजा अमरसिंह के काल से इस शैली पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है।

मारवाड़ शैली – मारवाड़ में रावमालदेव के समय इस शैली का स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ। इस शैली में पुरुष लम्बे चौड़े गठीले बदन के, स्त्रियाँ गठीले बदन की, बादामी आँखें, वेशभूषा ठेठ राजस्थानी और पीले रंग की प्रधानता होती थी। चित्रों के विषय नाथचरित्र, भागवत, पंचतन्त्र, ढोला–मारू, मूमलदे, निहालदे, लोकगाथाएँ होती थी। चित्रकारों में वीर जी, नारायणदास भाटी, अमरदास, छज्जूभाटी, किशनदास और कालूराम आदि प्रमुख हैं।

बीकानेर शैली – महाराजा अनूपसिंह के समय इस शैली का वास्तविक रूप में विकास हुआ। लाल, बेंगनी, सलेटी और बादामी रंगो का प्रयोग, बालू के टीलों का अंकन, लम्बी इकहरी नायिकाएं, मेघमंडल, पहाड़ों और फूलपत्तियों का आलेखन इस शैली की प्रमुख विशेषताएँ रही है। शिकार, रसिक प्रिया, रागमाला, श्रृंगारिक आख्यान विशेष रहे हैं। इस शैली पर पंजाब कलम, मुगल शैली और मारवाड़ शैली का प्रभाव पाया जाता है।

किशनगढ़ शैली – यह राजपूतकालीन चित्रकला की अत्यन्त आकर्षक शैली है। इस शैली का सर्वाधिक विकास राजानागरीदास के समय में हुआ। उभरी हुई ठोड़ी, नेत्रों की खंजनाकृति बनावट, धनुषाकार भौंए, गुलाबीअदा, सुरम्यसरोवरों का अंकन इस चित्रशैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं है 'बनी ठनी' इस चित्रशैली की सर्वोत्तमकृति है, जिसे भारतीय चित्रकला का 'मोनालिसा' भी कहा जाता है। इसका चित्रण निहालचन्द ने किया था। इस शैली के चित्रों में कला, प्रेम और भक्ति का सर्वांगीण सामन्जस्य पाया जाता है।

जयपुर शैली – इस चित्रशैली का काल 1600 ई. से 1700 ई. तक माना जाता है। इस शैली पर राजस्थान में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। सफेद, लाल, पीले, नीले तथा हरे रंग का अधिक प्रयोग, सोने–चाँदी का उपयोग, पुरुष की बलिष्ठता और महिला की कोमलता इस

शैली की प्रमुख विशेषता रही है। शाही सवारी, महफिलें, राग–रंग, शिकार, बारहमासा, गीत गोविन्द, रामायण आदि विषय प्रमुख रहें है।

बून्दी शैली – मेवाड़ से प्रभावित, राव सुरजन से प्रारम्भ बून्दी शैली उम्मेदसिंह के समय तक उन्नति के शिखर पर पहुँची थी। लाल, पीले रंगो की प्रचुरता, छोटा कद, प्रकृति का सतरंगी चित्रण इस चित्र शैली की विशेषता रही है। रसिकप्रिया, कविप्रिया, बिहारी सतसई, नायक–नायिका भेद, ऋतुवर्णन बून्दी चित्रशैली के प्रमुख विषय थे। इस शैली में पशु–पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है, इसलिए इसे 'पशु पक्षियों की चित्रशैली' भी कहा जाता है। यहाँ के चित्रकारों में सुरजन, अहमदअली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम मुख्य थे।

कोटा शैली – कोटा चित्रशैली में बून्दी तथा मुगल शैली का समन्वय पाया जाता है। स्त्रियों के चित्र पुतलियों के रूप में, आँखे बड़ी, नाक छोटी, ललाटबड़ा, लंहगे उँचे, वेणी अकड़ी हुई इस शैली की प्रमुख विशेषताएँ रही है। चित्रों के विषय शिकार, उत्सव, श्री नाथ कथा चित्रण, पशु–पक्षी चित्रण रहें हैं।

नाथद्वारा शैली – यह शैली अपनी चित्रण विलक्षणता के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ श्रीनाथजी की छवियों के रूप में 'पिछवाई चित्रण' किया जाता है।

इस प्रकार राजस्थान चित्रण की दृष्टि से सम्पन्न रहा है। यहाँ पोथीखाना (जयपुर), मानसिंह पुस्तक प्रकाश (जोधपुर), सरस्वती भण्डार (उदयपुर) और स्थानीय महाराजाओं तथा सामन्तों के संग्रहालयों में चित्रकला का ऐसा समृद्ध भण्डार उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को धनी बनाये हुये है, वरन–भारत की कलानिधि का एक भव्य संग्रह भी है।

त्योहार एवं उत्सव

यद्यपि राजस्थान की मरूभूमि शुष्क है फिर भी उत्सवों त्योहारों एंव पारस्परिक मेल–मिलाप से रंग–रसमय है। राजस्थान में हिन्दू–मुस्लिम और इसाइयों के सभी त्यौहार उत्साह, उल्लासपूर्वक प्रेम भाई चारे के साथ सोहार्दपूर्ण वातावरण में मनाकर मानवीय एकता, सहिष्णुता का प्रदर्शन करते हैं।

यहाँ के प्रमुख लोकोत्सव में गणगौर और तीज का महत्वपूर्ण स्थान है। गणगौर का उत्सव होलिकात्सव से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। सधवास्त्रियाँ और कुमारियां सुहाग की अमरता एवं अच्छे वर की अभिलाषा में ईसर–ईसरी जी की पूजा करती है। यह उत्सव जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में गणगौर की सवारी निकालकर बड़ी धूम–धाम से मनाया जाता है। तीज का त्यौहार भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बालिकाएँ एवं नवविवाहिताएँ प्रकृति के प्रांगण में गीतों का गायनकर, झूलों में झूलकर, नवीन पोशाक पहन कर, और मेहन्दी रचाकर मनाती हैं। जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध हैं।

धार्मिक त्योहारों के अन्तर्गत हिन्दू दीपावली, होली, दशहरा, अक्षयतृतीया, रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, शरदपूर्णिमा, बसन्तपंचमी, नागपंचमी, रामनवमी, हनुमान जयन्ती, शिवरात्री, अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा आदि परम्परागत तरीके से हर्षोल्लासपूर्वक मनाते हैं।

जैन समाज में महावीर जयन्ती तथा भाद्रपद मास में पर्युषण पर्व व्रत, तप और अर्चना के साथ मनाते है। मुस्लिम समाज के प्रमुख त्यौहार इदुलजुहा, इदुलफितर, शबेरात, मोहर्रम और बारावफात उत्साह एवं भाईचारापूर्वक मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में सभी समाज के लोगों में प्रेम, उल्लास और आनन्द का संचार होता है सामाजिक समरसता का विकास होता है तथा धार्मिक श्रृद्धा का संचार होता है। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार एवं उनकी तिथियाँ निम्न है:

प्रमुख त्योहार एवं उनकी तिथियाँ

क्र.स.	त्योहार	तिथि
1.	गणगौर	फाल्गुन शुक्ल 15 से चैत्र शुक्ला 3 तक
2.	महाशिवरात्री	फाल्गुन कृष्ण पक्ष–13 (त्रयोदशी)
3.	दीपावली	कार्तिक कृष्ण पक्ष–अमावस्या

4.	रक्षाबन्धन	श्रावणमास पूर्णिमा
5.	होली	फाल्गुनमास पूर्णिमा
6.	जन्माष्टमी	भाद्रपद कृष्णपक्ष अष्टमी
7.	गणेश चतुर्थी	भाद्रपद शुक्लपक्ष चौथ
8.	रामनवमी	चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी
9.	क्रिसमस डे	25 दिसम्बर
10.	मुहर्रम	मुहर्रम माह की दस तारीख
11.	ईद–उलफितर	शव्वाल की पहली तारीख
12.	तीज	भाद्रपद कृष्णपक्ष तृतीया
13.	पर्युषण	भाद्रपद मास
14.	दशहरा	आश्विन शुक्लपक्ष दशमी
15.	ईदउलजुहा	जिल्कार की दसवीं तारीख

मेले

राजस्थान के मेलें यहाँ की संस्कृति के परिचायक है। राजस्थान में मेलों का आयोजन धर्म, लोकदेवता, लोकसंत और लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मेलों में नृत्य, गायन, तमाशा, बाजार आदि से लोगों में प्रेम व्यवहार, मेल–मिलाप बढ़ता है। राजस्थान के प्रत्येक अंचल में मेले लगते है। इन मेलों का प्रचलन प्रमुखतः मध्य काल से हुआ जब यहाँ के शासकों ने मेलों को प्रारम्भ कराया। मेले धार्मिक स्थलों पर एवं उत्सवों पर लगने की यहाँ परम्परा रही है जो आज भी प्रचलित है। राजस्थान में जिन उत्सवों पर मेले लगते है उनमें विशेष हैं– गणेश चतुर्थी, नवरात्र, अष्टमी, तीज, गणगौर, शिवरात्री, जन्माष्टमी, दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा आदि। इसी प्रकार धार्मिक स्थलों (मंदिरों) पर लगने वाले मेलों में तेजाजी, शीतलामाता, रामदेवजी, गोगाजी, जाम्बेश्वर जी, हनुमान जी, महादेव, आवरीमाता, केलादेवी, करणीमाता, अम्बामाता, जगदीश जी, महावीर जी आदि प्रमुख है।

राजस्थान के धर्मप्रधान मेलों में जयपुर में बालाजी का, हिण्डोन के पास महावीर जी का, अन्नकूट पर नाथद्वारा का, गोठमांगलोद में दधिमती माता का, एकलिंग जी में शिवरात्री का, केसरिया में धुलेव का, अलवर के पास भर्तहरि जी का और अजमेर के पास पुष्कर जी का मेला जयपुर का गलता मेला प्रमुख है। इन मेलों में लोग भक्तिभावना से स्नान एवं आराधना करते हैं।

लोकसंतो और लोकदेवों की स्मृति एवं श्रद्धा में भी यहाँ अनेक मेलों का आयोजन होता है। रूणेचा में रामदेवजी का, परबतसर में तेजाजी का, कोलगढ में पाबूजी का, ददेरवा में गोगाजी का, देशनोक में करणीमाता का, नरेणा(जयपुर)– शाहपुरा (भीलवाड़ा) में फूलडोल का, मुकाम में जम्भेश्वरजी का, गुलाबपुरा में गुलाब बाबा का और अजमेर में ख्वाजा साहब का मेला लगता है। यह मेले जीवन धारा को गतिशीलता एवं आनंद प्रदान करते है शान्ति, सहयोग और साम्प्रदायिक एकता को बढाते है। मेलों का सांस्कृतिक पक्ष कला प्रदर्शन तथा सद्भावनाओं की अभिवृद्धि है। मेलों का महत्त्व देवों और देवियों की आराधनाओं की सिद्धि के लिए मनुष्य देवालयों में जाते हैं। मेलों से एक पीढी से दूसरी पीढी तक सांस्कृतिक परिपाटी प्रवाहित होती है जो संस्कृति की निरन्तरता के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मेले व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, विशेषकर पशु मेले तथा इसका मनोरंजन के लिये भी महत्व है।

लोक कलाएँ

राजस्थान लोक कला के विविध आयामों का जनक रहा है। लोक कला के अन्तर्गत लोकगीत, लोकनाट्य, लोकनृत्य, लोकवाद्य और लोक चित्रकला आती है, इसका विकास मौखिक स्मरण और रूढ़ियों के आधार पर दीर्घ काल से चला आ रहा है। ये लोक कलाएँ हमारी संस्कृति के प्राण है। मनोरंजन का साधन है। लोक जीवन का सच्चा स्वरूप है।

लोक नाट्य

मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली और जयपुर में लोक कलाकारों द्वारा लोक भाषा में रामलीला तथा रासलीला बड़ी लोकप्रिय

है। बीकानेर ओर जैसलमेर में लोक नाट्यों में 'रम्मत' प्रसिद्ध है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोकनायकों एवं महापुरूषों की ऐतिहासिक एवं धार्मिक काव्य रचनाओं का मंचन किया जाता है। इन रम्मतों के रचियता मनीराम व्यास, फागु महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि आदि है।

मारवाड़ में धर्म और वीर रस प्रधान कथानकों का मंचन 'ख्याल'(खेलनाटक) परम्परागत चला आ रहा है, इनमें अमरसिंह का ख्याल, रूठिराणी रो ख्याल, राजा हरिश्चन्द्र का ख्याल प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है। राजस्थान में 'भवाईनाट्य' अनूठा है जिसमें पात्र व्यंग वक्ता होते है। संवाद, गायन, हास्य और नृत्य इसकी प्रमुख विशेषताएँ है। मेवाड़ में प्रचलित 'गवरी' एक नृत्य नाटिका है जो रक्षाबन्धन से सवा माह तक खेली जाती है।

गवरी – वादन संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक–संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ की 'गवरी' निराली है। गवरी का उद्भव शिव–भस्मासुर की कथा से माना जाता है। इसका आयोजन रक्षाबन्धन के दूसरे दिन से शुरू होता है। गवरी सवा महिने तक खेली जाती है। इसमें भील संस्कृति की प्रमुखता रहती है। यह पर्व आदिवासी जाति पर पौराणिक तथा सामाजिक प्रभाव की अभिव्यक्ति है। गवरी में पुरूष पात्र होते हैं। इसके खेलों में गणपति कान–गुजरी, जोगी, लाखा, बणजारा इत्यादि के खेल होते है।

लोकनृत्य

राजस्थान में लोकनृत्य की परम्परा सदा से उन्नत रही है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लोकनृत्यों का विकास हुआ जिससे जनजीवन में आनन्द, जीवट और शौर्य के भावों की अभिवृद्धि हुई है।

(अ) गैरनृत्य – आदिवासी क्षेत्रों में होली के अवसर पर ढोल, बांकिया तथा थाली की संगत में पुरूष अंगरखी, धोती, पगड़ी पहनें हाथ में छड़िया लेकर गोल घेरे में नृत्य में भीली संस्कृति के दर्शन होते हैं।

(ब) गीदड़नृत्य – शेखावाटी क्षेत्र में लोग होली का डण्डा रोपने से सप्ताह भर तक नंगाडे की ताल पर पुरूष दो छोटे डंडे लेकर गीतों के साथ सुन्दर परिधान पहन कर नृत्य करतें है जिसे 'गीदड़नृत्य' कहा जाता है।

(स) ढोलनृत्य – मरूस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के लोग 'थाकना' शैली में ढोलनृत्य करते हैं।

(द) बमनृत्य – अलवर और भरतपुर में फागुन की मस्ती में बड़े नगाड़े को दो बड़े डण्डों से बजाया जाता है, जिसे 'बम' कहते है। इसी कारण इसे 'बमनृत्य' कहते हैं।

(य) घूमरनृत्य – यह राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकनृत्य है, इसे मांगलिक पर्वों पर महिलाओं द्वारा हाथों के लचकदार संचालन से ढोलनगाड़ा, शहनाई आदि संगत में किया जाता है।

(र) गरबा नृत्य – महिला नृत्य में गरबा भक्तिपूर्ण नृत्य कला का अच्छा उदाहरण है। यह नृत्य भाक्ति की आराधना का दिव्य रूप है जिसे मुख्य रूप से गुजरात में देखा जाता है। राजस्थान में डूंगरपुर और बाँसवाड़ा में इसका व्यापक प्रचलन है। इस तरह गुजरात और राजस्थान की संस्कृति के समन्वय का सुन्दर रूप हमें 'गरबा' नृत्य में देखने को मिलता है।

अन्य लोकनृत्य – जसनाथी सिद्धों का अंगारा नृत्य, भीलों का 'राईनृत्य' गरासिया जाति का 'वालरनृत्य' कालबेलियाजाति का 'कालबेलियानृत्य' प्रमुख है। पेशेवर लोकनृत्यों में 'भवाई नृत्य' तेरहताली नृत्य चमत्कारी कलाओं के लिए विख्यात है।

लोकगीत – राजस्थानी लोकगीत मौखिक परम्परा पर आधारित मानस पटल की उपज है, जो सोलह संस्कारों, रीतिरिवाजों, संयोगवियोग के अवसरों पर लोक भाषा में सुन्दर अभिव्यक्ति करते है। उदाहरणार्थ – 'खेलण दो गणगौर', म्हारी घूमर छे नखराली एमाय, चिरमी आदि है।

लोकवाद्य – लोककला में राजस्थान के लोक वाद्यों का बड़ा महत्व है, इनके बिना नृत्य, संगीत भी

अधूरा लगता है। यहाँ के प्रमुख लोक वाद्यों में 'रावण हत्था', तंदूरा, नंगाड़े, तीनतारा, जोगिया सारंगी, पूंगी और भपंग उल्लेखनीय हैं।

लोक चित्रकला

1. पथवारी – गांवो में पथरक्षक रूप में पूजा जाने वाला स्थल जिस पर विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं।

2. पाना – राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं, उन्हें पाना कहा जाता है।

3. मांडणा – राजस्थान में लोक चित्रकला की यह एक अनुठी परम्परा है। त्योहारों एवं मांगलिक अवसरों पर पूजास्थल चौक पर ज्यामितीयवृत, वर्ग या आड़ी तिरछी रेखाओं के रूप में 'मांडणा' बनाये जाते हैं।

4. फड़ – कपड़ों पर किये जाने वाले चित्रांकन को 'फड़' कहा जाता है।

5. सांझी – यह गोबर के घर के आंगन, पूजास्थल अथवा चबुतरें पर बनाया जाता है।

लोकगीत, लोकनाट्य, लोकवाद्य, लोक चित्रकला राजस्थानी संस्कृति एवं सभ्यता के प्रमुख अंग है। आदिकाल से लेकर आज तक इन कलाओं का विविध रूपों में विकास हुआ है। इन विधाओं के विकास में भक्ति, प्रेम, उल्लास और मनोंरजन का प्रमुख स्थान रहा है। इनके पल्लवन में लोक आस्था की प्रमुख भूमिका रही है। बिना आस्था और विश्वास के इन लोक कलाओं के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज भी लोककला के मूल तत्त्व जन जीवन में विद्यमान हैं। त्योहार, नृत्य, संगीत, लोकवाद्य, लोक कलाओं, विभिन्न बोलियों एवं परिणाम के कारण ही राजस्थान को 'रंगीला राजस्थान' की संज्ञा दी जाती है। राजस्थान की सांझी संस्कृति के दर्शन यहाँ के जन–जीवन के साथ साहित्य में भी देखे जा सकते हैं। धर्म समभाव एवं सुलह–कुल की नीति यहाँ के धार्मिक जीवन का इतिहास के काल से ही मूल मंत्र रहा है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुविकल्पात्मक प्रश्न

सही उत्तर का क्रमाक्षर सामने के कोष्ठक में लिखिए–

1. 'हरिकेलि' नाटक के रचयिता थे–
   (अ) पृथ्वी राज तृतीय
   (ब) विग्रहराजचतुर्थ
   (स) चन्दरवरदाई
   (द) महाराणा कुम्भा
2. गागरोन दुर्ग जिस कोटी में आता है वह है–
   (अ) गिरीदुर्ग (ब) मरूस्थलदुर्ग
   (स) जलदुर्ग (द) वनदुर्ग

3– वह स्थान जहाँ पटवों की हवेलियाँ स्थित है–
   (अ) जैसलमेर (ब) बाड़मेर
   (स) आमेर (द) बीकानेर

4– 'बणी–ठणी' का चित्र जिस चित्रशैली में चित्रित हुआ, वह है–
   (अ) किशनगढ़ शैली (ब) मारवाड़ शैली
   (स) मेवाड़ शैली (द) कोटा शैली

5– देलवाड़ा के आदिनाथ मन्दिर का निर्माता था–
   (अ) विमलशाह (ब) तेजपाल
   (स) वस्तुपाल (द) कमलशाह

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1– चन्दरवरदायी कृत काव्य ग्रन्थ का नामोल्लेख कीजिए।

2– राजस्थान में मरूस्थलीय दुर्ग कहाँ स्थित है?

3– राजस्थानी चित्रकला की किन्हीं दो शैलीयों के नाम बताइये।

4– विजयस्तम्भ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया?

5– 'अंगारा नृत्य' किनके द्वारा किया जाता है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1– मन्दिर स्थापत्य में देलवाड़ा के मन्दिरों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

2– मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

3– 'संतसाहित्य राजस्थान की अमूल्य धरोहर है' स्पष्ट कीजिए।

4– राजस्थान के प्रमुख धर्मप्रधान मेलों का उल्लेख कीजिए।

5– राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्यों का परिचय दीजिए।

6– गणगौर और तीज राजस्थान के विशिष्ट लोकोत्सव है, स्पष्ट कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न–

1– राजस्थान में साझी संस्कृति दिखाई देती है, कथन की विवेचना कीजिए।

2– राजस्थान में साहित्यिक विकास पर निबन्ध लिखिए।

3– स्थापत्य कला राजस्थानी इतिहास की धरोहर है। व्याख्या कीजिए?

4– चित्रकला कला की विविध शैलीयों का वर्णन कीजिए।

5– राजस्थान के मेलों एवं उत्सवों की विवेचना कीजिए।

6– राजस्थान की लोककलाओं का विवरण दीजिए।

❑❑❑❑

अध्याय 4
राजस्थान की अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय

भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इस दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की जनसंख्या 2011 की ताजी जनगणना के अनुसार 6.86 करोड़ (प्रोविजनल) हो गई है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राजस्थान राज्य में पूरे देश की जनसंख्या 121.02 करोड़ का 5.67 प्रतिशत भाग निवास करता है। इस विवरण से क्षेत्रफल और जनसंख्या में राजस्थान की महत्ता सहज रूप से स्पष्ट होती है। अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक और मानव संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। राजस्थान इन दोनों ही दृष्टि से समृद्ध प्रान्त है। प्राकृतिक संसाधनों में खनिजों की भरपूर उपलब्धता के कारण भारत में राजस्थान 'खनिजों के अजायबघर' के नाम से जाना जाता है। खनिज संपदा के बल पर आज राजस्थान देश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है। उद्योगों के साथ–साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का भी बड़ा योगदान है। राजस्थान की मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, जौ, चना, गेहूँ, तिलहन, दालें, कपास और तम्बाकू है। राजस्थान तिलहन विशेष रूप से सरसों के उत्पादन में उभरा है। इनके अलावा लाल मिर्च, मैथी, जीरा, हींग भी अन्य फसलें है। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षो में सब्जियों तथा संतरा, माल्टा, नींबू, आंवला, अमरूद आदि फलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन की भूमिका बढ़ गई है। उल्लेखनीय है राजस्थान की साक्षरता दर 1991 में 38.55 प्रतिशत थी जो देश भर में बिहार की साक्षरता दर 37.19 प्रतिशत के बाद नीचे से दूसरे स्थान पर थी। वर्ष 2001 की जनगणना में राजस्थान की साक्षरता दर बढ़कर 60.41 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2001 में राजस्थान साक्षरता दर में उत्तरप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, दादर और नगरहवेली से आगे बढ़ गया। साक्षरता दर 2011 में और बढ़कर 67.06 प्रतिशत हो गई है। राजस्थान ने हाल ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस श्रृंखला में अजमेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुलना महत्वपूर्ण है। जोधपुर में आई.आई.टी. का खुलना बड़ी उपलब्धि है। इन बड़े निर्णयों से राजस्थान के ज्ञान क्रांति के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने की संभावनाएं है। आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ राजस्थान का सामरिक महत्व भी है।

अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना

आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। आधारभूत संरचना में जो क्षेत्र समृद्ध होते हैं उनका विकास तेज गति से होता है। आधारभूत संरचना को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग आधारभूत ढांचागत संरचना है इसमें परिवहन, विद्युत, संचार को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा सिंचाई भी आधारभूत ढांचागत संरचना का भाग है क्योंकि कृषि विकास सिंचाई पर निर्भर है। आधारभूत संरचना का दूसरा भाग आधारभूत सामाजिक संरचना है। इसमें प्रमुख रूप से मानव संसाधन विकास को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान का विकास के मामले में अग्रणी राज्य नहीं होने का कारण आधारभूत संरचना का अभाव है। बिना आधारभूत संरचना के विकास का पहिया घूम नहीं सकता है। राजस्थान सरकार आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसके विकास पर ध्यान केन्द्रित किये हुए है। राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं में और वार्षिक योजनाओं में वित्तीय संसाधनों का बड़ा भाग आधारभूत संरचना पर खर्च किया जा रहा है। जैसे–जैसे

राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति सुधर रही है वैसे–वैसे राजस्थान आर्थिक विकास में आगे बढ़ रहा है।

राजस्थान में आधारभूत संरचना विशेष रूप से परिवहन, ऊर्जा, सिंचाई, संचार और मानव संसाधन की स्थिति निम्नलिखित है :

(1) **परिवहन**

आर्थिक विकास में परिवहन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक विकास के लिए परिवहन आवश्यकता है। परिवहन के साधनों से सभी क्षेत्रों के विकास को गति मिलती है। परिवहन की प्राकृतिक आपदाओं के समय में अत्यधिक उपयोगिता होती है। युद्ध के समय परिवहन के साधनों की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। परिवहन का सांस्कृतिक महत्त्व भी होता है। राजस्थान के योजनाबद्ध विकास में परिवहन विकास पर ध्यान दिया गया है। राजस्थान ने विगत कुछ वर्षो में परिवहन के क्षेत्र में प्रगति की है।

परिवहन में मुख्यतः सड़क, रेल और वायु यातायात को सम्मिलित किया जाता है।

सड़क परिवहन

महानगर और बड़े शहर सामान्यतया रेल और वायु यातायात से जुड़े होते हैं, किन्तु गांवों के परिवहन का साधन मुख्यतः सड़के ही है। गांवों में सड़कों का महत्त्व मानव शरीर में शिराओं और धमनियों की भांति है। राजस्थान में जनसंख्या का बड़ा भाग गांवों में जीवन बसर करता है। राज्य के गांवों में जहाँ–जहाँ सड़कें पहुंची है, समृद्धि स्वतः ही नजर आने लगी है। सड़कों के विकास के बिना गांव अधूरे दिखते हैं। सड़कों के अभाव में गांवों का सामाजिक विकास गति नहीं पकड़ पाता है। वर्तमान में राजस्थान के गांवों में सड़कों का जाल बिछा हुआ नजर आने लगा है। राजस्थान में सड़क परिवहन की प्रगति को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है :

1. **यातायात विकास पर योजना खर्च** – राजस्थान के योजनाबद्ध विकास में यातायात विकास पर खर्च में वृद्धि हुई। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में यातायात विकास पर खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्तमान में सड़क परिवहन राज्य सरकार का महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता वाला विकास शीर्ष है।

2. **सड़कों का विकास** – योजनाबद्ध विकास में यातायात खर्च में वृद्धि से सड़क परिवहन का विकास हुआ है। राजस्थान में डामर की सड़कों की लम्बाई 1950–51 में 17339 किलोमीटर थी जो 2010–11 में बढ़कर 189034 किलोमीटर (प्रावधानिक) हो गई। इन सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें व ग्रामीण सड़कें सम्मिलित है।

राजस्थान में डामर की सड़कों की लम्बाई, 2010–11 (प्रावधानिक)

(किलोमीटर में)

क.सं.	सड़कों के प्रकार	लम्बाई
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	5724
2.	राज्य राजमार्ग	11866
3	मुख्य जिला सड़कें	7829
4	अन्य जिला सड़कें	24480
5	ग्रामीण सड़के	139135
	योग	189034

स्त्रोत – आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार 2010–11

राजस्थान में डामर की सड़कों के अलावा ग्रेवल की सड़कें, पक्की सड़कें, साधारण मौसमी सड़कें भी है। वर्ष 2008–09 में राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की लम्बाई 186806 किलोमीटर थी। इनमें डामर की सड़कें 140437 किलोमीटर, पक्की सड़कें 1399 किलोमीटर, ग्रेवल की सड़कें 41104 किलोमीटर तथा साधारण सड़कें 3866 किलोमीटर थी।

3. **राष्ट्रीय राजमार्ग** – राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई राजस्थान के विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए कम है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास का काम नेशनल हाइवे अथोरिटी देखता है। राजस्थान से कुल सात राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, इनमें पांच मार्ग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सबसे महत्त्वपूर्ण और व्यस्त राजमार्ग है। राजस्थान में इसकी लम्बाई 685 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होता हुआ मुम्बई जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 11 सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण मार्ग है यह मार्ग आगरा से भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ बीकानेर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर से टोंक, बून्दी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 ब्यावर, पाली, सिरोही, आबूरोड़ होता हुआ कांदला तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पठानकोट से राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होता हुआ कांदला तक जाता है। इसकी राजस्थान में लम्बाई 875 कि.मी. है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 भी है। राजस्थान में इस मार्ग की लम्बाई केवल 28 किलोमीटर ही है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग धोलपुर जिले से गुजरता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर– किशनगढ़ 6 लेन है इस मार्ग का निर्माण स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अन्तर्गत मार्च 2005 में हुआ।

4. **राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम** – यह राजस्थान सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख प्रतिष्ठान है। एक वैधानिक निगम के रूप में इसकी स्थापना 1964 में हुई। यह निगम स्थापना के समय से ही यात्री यातायात के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है।

5. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी. एस.वाई.)** – देश के सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसम्बर 2000 को ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' घोषित की गई। इसके अन्तर्गत 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 तथा इससे अधिक आबादी वाले गांवों को वर्ष 2003 तक तथा 500 से 1000 तक आबादी वाले सभी गांवों को 2007 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जनजाति क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना है।

राजस्थान रोड विजन –2025

राजस्थान में सड़क तंत्र के कायापलट के लिए 'राजस्थान रोड़ विजन–2025' तैयार किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इक्कीसवीं सदी के पहले 25 साल में राज्य में सड़कों के विकास के लिए यह दीर्घावधि ''विजन'' तैयार किया गया। इसमें सड़कों के विकास के साथ–साथ सड़कों के रख–रखाव और सड़कों की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। 'रोड विजन 2025' में पहले 15 साल में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के बाद अगले 10 साल में एक्सप्रेस वे, फ्लाई ओवर, चार लेन के राजकीय मार्ग पर जोर दिया गया है। इस विजन में धार्मिक महत्व के स्थानों, पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नये सड़क सम्पर्क विकसित करना जरूरी माना गया है।

सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को ''मॉडल स्टेट'' माना जा सकता है। राजस्थान में परिवहन व्यवस्था और कार्यविधि अनुकरणीय है।

रेल परिवहन

स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रेल मार्गों का विकास बहुत कम था। थोड़ा बहुत रेल मार्गों का विकास जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत तथा उदयपुर रियासत में हुआ था। डूँगरपुर, बांसवाडा, जैसलमेर रियासतें रेल मार्गों से जुड़ी हुई नहीं थी। स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार ने रेल विकास का काम हाथ में लिया। वर्तमान में रेल परिवहन भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। प्रत्येक वर्ष संसद में रेलमंत्री के द्वारा रेल बजट पेश किया जाता है। राजस्थान में रेल विकास का दायित्व भारत सरकार पर है।

भारत के कुल रेल मार्गों का लगभग 11 प्रतिशत भाग ही राजस्थान में है। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लम्बाई मार्च 2002 में 5894 किलोमीटर थी जो देश के रेल मार्गों की कुल लम्बाई 63140 किलोमीटर का 9.4 प्रतिशत था। राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लम्बाई में ब्रोडगेज का भाग 51.4 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 71.4 प्रतिशत है। राजस्थान में 31 मार्च 2002 को प्रति हजार वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गो की औसतन लम्बाई 17.2 किलोमीटर थी जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर 19.2 किलोमीटर थी।

राज्य में मार्च 2008 में रेल मार्गों की कुल लम्बाई 5683.01 किलोमीटर थी। जिसमें ब्रोडगेज का भाग 68.37

प्रतिशत, मीटर गेज का भाग 30.10 प्रतिशत तथा नैरोगेज का भाग 1.53 प्रतिशत था। राज्य में 31 मार्च 2008 को प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रेल मार्गों की औसतन लम्बाई 16.61 किलोमीटर थी।

प्रमुख रेल मार्ग – राजस्थान के प्रमुख रेल मार्गों में जयपुर–मुम्बई रेल मार्ग, जोधपुर–हावड़ा रेल मार्ग, दिल्ली–अहमदाबाद रेल मार्ग, उदयपुर–दिल्ली रेलमार्ग, बीकानेर– दिल्ली रेलमार्ग, जयपुर–दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर–गंगानगर रेलमार्ग, फुलेरा–दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर–सवाई माधोपुर रेल मार्ग, जयपुर–आगरा रेलमार्ग, जयपुर–जम्मूवती रेल मार्ग, जोधपुर–गौहाटी रेलमार्ग, जयपुर–लुहारू रेलमार्ग, जयपुर–चेन्नई रेलमार्ग, जोधपुर–हरिद्वार रेलमार्ग आदि महत्वपूर्ण है।

वायु परिवहन

स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में वायु परिवहन का विकास नहीं के बराबर था। राज्य में केवल जोधपुर में ही हवाई अड्डा था जो दिल्ली व कराची से जुड़ा था। वर्ष 1947 में बीकानेर जोधपुर वायु सेवा प्रारम्भ हुई। स्वतंत्रता के बाद 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। देश में वायु परिवहन का संचालन नागर विमानन विभाग करता है। देश में एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स की प्रमुख वायु सेवाएं है। आर्थिक उदारीकरण के बाद वायु परिवहन में निजी सेवाओं की भूमिका भी बढ़ गई है। राजस्थान पिछले दशकों में वायु परिवहन में पिछड़ा हुआ था, किन्तु वर्तमान में वायु परिवहन के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति में सुधार आ रहा है।

राजस्थान के मुख्य वायुमार्ग है – दिल्ली – आगरा–जयपुर, दिल्ली–जयपुर, जोधपुर–उदयपुर–अहमदाबाद–मुम्बई, दिल्ली – जयपुर – उदयपुर – औरंगाबाद–मुम्बई, जयपुर–बनारस–कोलकत्ता, जयपुर–हैदराबाद, जयपुर–बैंगलोर, जयपुर–गोहाटी, जयपुर – मुम्बई–सिंगापुर, जयपुर–मस्कट।

वर्तमान में राज्य में नियमित हवाई सेवा हेतु सांगानेर (जयपुर), रातानाड़ा (जौधपुर) एवं डबोक (उदयपुर) हवाई अड्डे हैं। इसमें जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का है।

(2) ऊर्जा

ऊर्जा महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, सामाजिक विकास क्षेत्र आदि विकास के लिए ऊर्जा पर निर्भर है। क्षेत्र विशेष का विकास ऊर्जा बिना संभव नहीं है। ऊर्जा के लिए परम्परागत और गैर परम्परागत स्त्रोत होते हैं। परम्परागत स्त्रोतों में जल विद्युत, थर्मल विद्युत एवं अणु ऊर्जा सम्मिलित की जाती है। ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतों में बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि प्रमुख है।

राजस्थान सरकार अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की महत्ता और उदारीकरण के कारण औद्योगिक विकास वृद्धि की संभावना को दृष्टि में रखकर ऊर्जा विकास के लिए प्रयत्नशील है। राजस्थान की गिनती ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सुधारों को लागू करने के मामलें में देश के अग्रणी राज्यों में होती है। राजस्थान में विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम, 1999 लागू किया गया। घाटे से ग्रसित 'राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल' को 1999 में समाप्त किया गया। राजस्थान में जून 2000 में पांच स्वतन्त्र कम्पनियां गठित की गई। नई कम्पनियों में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राज्य में विद्युत उत्पादन योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन एवं रख–रखाव का कार्य करती है।

एक अन्य कम्पनी 'राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड' राज्य में प्रसारण तंत्र का निर्माण, संचालन एवं संधारण करती है। बिजली वितरण के लिए तीन कम्पनियां यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। ये तीनों कम्पनियां अपने–अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विद्युत वितरण का कार्य संचालित करती है।

विद्युत विकास पर योजना परिव्यय – राजस्थान में ऊर्जा की कमी और आर्थिक विकास में विद्युत की महत्ता को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा पर

भारी वित्तीय संसाधन आवंटित किये गये। पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च स्थान दिया गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा पर सार्वजनिक व्यय इस प्रकार रहा – पहली योजना 1.24 करोड रूपये, दूसरी योजना 15.2 करोड रूपए, तीसरी योजना 39.4 करोड़ रूपए, चौथी योजना 94 करोड़ रूपये, पांचवी योजना 249 करोड़ रूपये, छठी योजना 566 करोड़ रूपए, सातवीं योजना 922 करोड रूपए, आठवीं योजना 3255 करोड़ रूपये, नौवीं योजना 5261 करोड़ रूपये, दसवी योजना 10461 करोड़ रूपये। ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा विकास पर 25607 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना के कुल योजना व्यय का 2.3 प्रतिशत भाग ऊर्जा विकास पर खर्च किया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कुल योजना व्यय का ऊर्जा विकास पर व्यय बढ़कर 36 प्रतिशत पहुंच गया।

स्थापित विद्युत क्षमता – राजस्थान में स्थापित विद्युत क्षमता 1950–51 में 13 मेगावट थी जो 2003–04 में बढ़कर 5167.43 मेगावाट हो गई। विद्युत स्थापित क्षमता बढ़कर 2006–07 में 6089 मेगावाट तथा 2011–12 में दिसम्बर 2011 तक 9831 मेगावाट (अग्रिम अनुमान) हो गई।

प्रमुख विद्युत परियोजनाएं – योजनाबद्ध विकास में राजस्थान में कई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई। राजस्थान में दो प्रकार की विद्युत परियोजनाएं है। एक राज्य के स्वयं की स्वामित्व वाली परियोजनाएं हैं इनमें सुपर थर्मल तापीय विद्युत परियोजना कोटा, सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना, छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना, माही जल विद्युत परियोजना है तथा अन्य आंशिक स्वामित्व वाली परियोजनाएं जिनसे राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। इनमें चम्बल परियोजना, व्यास परियोजना, भाखड़ा परियोजना, सतपुड़ा परियोजना प्रमुख है। **'राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना' एक महत्त्वपूर्ण योजना है** जिसके अन्तर्गत रावतभाटा में परमाणु संयन्त्र स्थापित किया गया है। अन्य ऊर्जा परियोजना में अन्ता विद्युत परियोजना (गैस आधारित), सिंगरोली, रिहन्द आदि है। ऊर्जा उत्पादन के प्रति सरकार अत्यधिक प्रयत्नशील है।

विद्युतीकृत कस्बें और गांव – योजनाबद्ध विकास में विद्युतीकृत कस्बों और गांवों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 1950–51 में राज्य में विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या केवल 42 थी। राजस्थान में 2002–03 तक 97.40 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत हो चुके थे। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च 2009 तक 37288 गाँवों को विद्युतीकृत एवं 8.96 लाख कुओं को ऊर्जीकृत किया गया।

ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोत – राजस्थान में गैर परम्परागत ऊर्जा के स्त्रोतों का विकास करने के लिए 21 जनवरी 1985 को राजस्थान ऊर्जा विकास एजेन्सी (रेडा) की स्थापना की गई। रेडा का उद्देश्य सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, गोबर गैस से विद्युत उत्पादन करना है। रेडा का अगस्त 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम में विलय हो गया।

सौर ऊर्जा से गैस और ईंधन की बचत होती है। इनका उपयोग सोलर कूलर चलाना, सोलर पम्प चलाना, वाटर हीटर्स, स्ट्रीट टयूब लाईटे, टी.वी. सेट्स आदि में किया जाता सकता है। जोधपुर जिले के उच्चीकृत प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र बालेसर में सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 27 अगस्त 1999 को जोधपुर जिले के मथानिया गांव में स्थापित होने वाली 140 मेगावाट के एकीकृत सौर मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। मथानिया परियोजना में 35 मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर तापीय तकनीक तथा शेष 105 मेगावट बिजली पारम्परिक नेफ्ता या गैस मिश्रित चक्रीय तकनीक से बनेगी। यह परियोजना विश्व में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसमें सौर तापीय तकनीक परम्परागत मिश्रित चक्रीय तकनीक के साथ जोड़ा जायेगा।

पवन ऊर्जा और बायो–गैस भी ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोत है। राजस्थान में वायु का वेग 20 से 40 कि.मी. प्रति घन्टा है । इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में चारे और चरागाह विकास के लिए पवन ऊर्जा उपयोगी है। भारत में 1980–81 में प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय बायोगैस योजना के माध्यम से राजस्थान में बायोगैस का विस्तार

किया जा रहा है।

राजस्थान में इन सब प्रयत्नों के बावजूद विद्युत की मांग और आपूर्ति में अन्तर बना हुआ है। राजस्थान में योजनाबद्ध विकास में विद्युत का उत्पादन बढ़ा है किन्तु बढ़ते औद्योगिक विकास और लोगों के सुधरते जीवन स्तर के कारण विद्युत की मांग अधिक बढ़ गई है। आर्थिक उदारीकरण लागू करने के बाद भविष्य में आर्थिक विकास अधिक गति पकड़ेगा। उत्तरोत्तर बढ़ते विकास के साथ ऊर्जा की मांग बढ़ना निश्चित है। राजस्थान सरकार को ऊर्जा विकास के और अधिक प्रयत्न करने होंगे। राजस्थान में ऊर्जा विकास की विपुल संभावनाएं हैं।

3. सिंचाई

राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिकांश लोग जीवन– स्तर के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कृषि विकास सिंचाई पर निर्भर करता है। राजस्थान के पश्चिम भाग में मरूस्थल है। मानसून की अनिश्चितता के कारण "कृषि मानसून का जुआ" जैसी बात कई बार चरितार्थ होती है। हरित क्रान्ति और कृषि क्षेत्र की आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ सिंचाई द्वारा ही संभव है। इसलिए राजस्थान में सिंचाई साधनों के विकास की महत्ती आवश्यकता है।

सिंचाई के स्त्रोत – राजस्थान के सिंचाई के प्रमुख साधनों में नहरें, तालाब, कुएँ, नलकूप है। सबसे अधिक सिंचाई नहरें और कुंओ से होती है। कुएँ और नलकूप सिंचाई के सर्वोत्तम साधन है। इनके द्वारा फसलों में आवश्यकतानुसार पानी दिया जा सकता है। कुएँ और नलकूप द्वारा सिंचाई के लिए पानी का मीठा होना, जल स्तर का गहरा नहीं होना तथा उपजाऊ भूमि का होना आवश्यक है।

नहरों द्वारा सतही जल का सबसे अधिक उपयोग होता हैं। राज्य में सतत् प्रवाही नदियों के अभाव में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र कम है। राज्य के दक्षिण–पूर्वी, पठारी एवं पथरीले भागों में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है।

राजस्थान में स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हजार हैक्टेयर)

स्त्रोत	1998–99	2007–08
नहरें	1557	1688
तालाब	93	102
कुएँ एवं नलकूप	3801	4572
अन्य	48	82
कुल सिंचित क्षेत्र	5499	6444

स्त्रोत – बेसिक स्टेटिस्टिक्स– 2009, राजस्थान, पृ.– 99

राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और सिंचाई की वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल, मछली पालन, वृक्षारोपण, अकाल और सूखे के समय जल की सुविधा, क्षेत्रीय आर्थिक विकास आदि निर्धारित किये गये हैं। वृहद सिंचाई परियोजनाओं से दस हजार हैक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई होती है। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से दो हजार से दस हजार हैक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की जाती है। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय, वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है :–

1. **भाँखरा नाँगल बहुउद्देशीय परियोजना** – यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सम्मिलित है। भाँखरा नाँगल में राजस्थान का हिस्सा 15.2 प्रतिशत है। भाँखरा मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हैक्टेयर है जिसमें राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हैक्टेयर है। भाँखरा नाँगल से राजस्थान के गंगानगर जिले में सिंचाई सुविधा और बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली की आपूर्ति है।

2. **चम्बल परियोजना** – चम्बल नदी मध्य प्रदेश के मऊ छावनी के पास से निकलकर उत्तर में बहती है।

राजस्थान में यह नदी चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। चम्बल राजस्थान की सतत् प्रवाही नदी है। चम्बल की विनाशकारी लीला को समाप्त करने के लिए राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्यों ने संयुक्त रूप से चम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया। यह देश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में से है। चम्बल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 50 प्रतिशत है।

चम्बल परियोजना के पहले चरण में चौरासीगढ़ और मानपुरी (मध्यप्रदेश) के पास गाँधी सागर बाँध तथा कोटा में दुर्ग के पास कोटा सिंचाई बाँध बनाया गया। दूसरे चरण में चूलिया झरने के पास राणा प्रताप सागर बांध तथा तीसरे चरण में जवाहर सागर बाँध का निर्माण किया गया । इसे कोटा बाँध भी कहते हैं। चम्बल परियोजना से राजस्थान के कोटा और बून्दी जिलों में सिंचाई होती है।

3. **माही बजाज सागर परियोजना** – माही नदी विन्ध्याचल पर्वत की उत्तरी पहाड़ियों से निकल कर मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों में बहती है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात राज्यों की संयुक्त परियोजना है। माही नदी पर बोरखेड़ा गांव के समीप माही बजाज सागर बाँध का निर्माण किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत बाँध, विद्युत गृह और नहरों के निर्माण से बांसवाड़ा और डूँगरपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन आया है।

4. **जाखम सिंचाई परियोजना** – जाखम माही की सहायक नदी है। प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम बाँध बनाया गया है। इस सिंचाई परियोजना से उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में सिंचाई सुविधा मुहैया है।

5. **बीसलपुर सिंचाई परियोजना** – टोंक जिले के बीसलपुर गांव में बनास नदी पर बाँध का निर्माण किया गया है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, टोंक आदि की पेयजल और सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बीसलपुर परियोजना महत्वपूर्ण है।

6. **सोम, कमला–अम्बा सिंचाई परियोजना** – दक्षिणी राजस्थान के जनजाति बहुल बांगड क्षेत्र की समृद्धि के लिए सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना भाग्य रेखा है। सोम नदी पर कमला अम्बा गांव के समीप बाँध का निर्माण किया गया है। इससे डूंगरपुर और उदयपुर के अनेक गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।

7. **मेजा बाँध परियोजना** – भीलवाड़ा जिले में माण्डलगढ़ तहसील के मेजा गांव के निकट कोठारी नदी पर मेजा बँाध का निर्माण किया। मेजा बाँध भीलवाड़ा का प्रमुख पेयजल स्त्रोत है। इससे भीलवाड़ा के आसपास के गांवों में सिंचाई सुविधा भी मुहैया होती है। मेजा बाँध क्षेत्र में गर्मियों में जल सूख जाने के कारण खीरा, कंकड़ी, तरबूज, खरबूज की खेती होती है।

8. **सिद्ध मुख परियोजना** – इस परियोजना से हनुमानगढ़ जिले की नोहर व भादरा तहसीलें तथा चूरू जिले की तारानगर व सादुलपुर तहसीलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इस परियोजना में राजस्थान रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी का उपयोग करेगा जो उसके हिस्से में दिसम्बर 1981 में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच हुए एक समझौता के अन्तर्गत मिला है।

9. **नर्मदा परियोजना** – सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना गुजरात राज्य की वृहद परियोजना है। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा भी है। इस परियोजना से राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों के गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

10. **व्यास परियोजना** – यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य रावी, व्यास, सतजल नदियों के जल का उपयोग करना है। राजस्थान में इस परियोजना से इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को स्थायी रूप से पानी की आपूर्ति की जाती है।

11. **इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना** – थार मरूस्थल की बेकार पड़ी उर्वरा शक्ति को सक्रिय करने के लिए बीकानेर रियासत के मुख्य अभियन्ता कंवर सेन ने हिमाचल

के पानी को थार मरूस्थल तक लाने की अनूठी योजना का प्रारूप वर्ष 1948 में भारत सरकार के विचारार्थ रखा। यही योजना इन्दिरा गाँधी नहर के लिए आधार बनी। यह परियोजना 2 नवम्बर 1984 तक राजस्थान नहर परियोजना का नाम से विख्यात थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के निधन के बाद परियोजना का नाम बदलकर उनकी स्मृति में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना किया गया। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। इसकी गिनती विश्व की सबसे लम्बी एवं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं में होती है।

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम स्थल पर स्थित 'हरिके बैराज' से है। यह परियोजना हरिके बैराज के बायीं और से निकाली गई है। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना की कुल लम्बाई 649 किलोमीटर रखी गई। इसे राजस्थान की मरूगंगा और थार मरूस्थल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य मरूस्थल में सिंचाई, मानव व पशुओं के लिए पीने का पानी, पशुपालन, वृक्षारोपण, विद्युत उत्पादन, पर्यटन विकास, मण्डी विकास, पशु चारा विकास, राष्ट्रीय शुष्क उद्यान आदि रखे गये हैं। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से लाभान्वित जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर सम्मिलित हैं।

12. **जवाई बाँध** – पश्चिमी राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी पर एरिनपुरा के निकट जवाई बाँध बनाया गया है। इस बाँध से जोधपुर, सुमेरपुर और पाली शहर को पेयजल आपूर्ति तथा पाली, जालोर जिलों में सिंचाई होती है।

13. **पाँचना परियोजना** – करौली जिले के गुडला गांव के समीप पाँच नदियों यथा बरखेडा, भद्रावती, माची, भैसावट, अटा के संगम पर बाँध बनाया गया है। पांचना परियोजना से करौली जिले की टोडाभीम, नादौती, हिण्डौन तथा सवाई माधोपुर में गंगापुर तहसील में सिंचाई सुविधा मुहैया है।

14. **मोरेल बाँध** – यह बाँध दौसा जिले के लालसोट कस्बे से 16 किलोमीटर दूर मोरेल नदी पर मिट्टी से बनाया गया है।

(4) संचार

संचार आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण भाग है। वर्तमान में आर्थिक विकास में संचार की भूमिका बढ़ गई है। देश में डाक एवं दूर संचार सेवाओं का तीव्र गति से विकास हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए तीव्र विकास ने संचार क्षेत्र में क्रान्ति ला दी है। संचार सुविधाओं के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। राजस्थान में भी डाक सेवा का पर्याप्त विकास हुआ है। राज्य में औसतन 33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक डाकघर स्थापित है। इसके अलावा प्रति डाकघर औसतन 5404 व्यक्तियों को सेवाएं प्राप्त हो रही है। राजस्थान में डाक एवं दूर संचार सेवाओं में डाकघर, तार कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज, लोकल पीसीओ, एसटीडी/पीसीओ, ग्रामीण पीटी, इन्टरनेट सेवाएँ आदि सम्मिलित है। संचार के अन्य साधनों में टेलीविजन, रेडियों, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, टेलेक्स, कम्प्यूटर, लेपटॉप, फैक्स आदि भी है।

(5) मानव संसाधन

आर्थिक विकास में सामाजिक आधारभूत संरचना की भूमिका बढ़ गई है। इसमें मानव संसाधन संरचना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलापूर्ति, आवास, समाज कल्याण, जनजाति क्षेत्रीय विकास, महिला एवं बाल विकास और कल्याणकारी गतिविधियाँ भी सामाजिक आधारभूत संरचना के अंग है।

राजस्थान में मानव संसाधन विकास की स्थिति सुधारवादी चरण में है। राजस्थान में साक्षरता दर 1991 में 38.6 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2001 में 60.4 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार 1991–2001 के दशक में राजस्थान की साक्षरता दर में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में साक्षरता में राजस्थान का स्थान भारत के राज्यों और

संघ क्षेत्रों में द्वितीय निम्न स्तर से ऊपर उठकर सातवां हो गया था। राज्य की साक्षरता दर 2011 में बढ़कर 67.06 प्रतिशत हो गई है। राजस्थान के मानव संसाधन विकास में प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान में 2005–06 में 56573 प्राथमिक स्कूल, 28955 उच्च प्राथमिक स्कूल, 11199 उच्च माध्यमिक विद्यालय थे। राज्य में 2006–07 में 1090 उच्च शैक्षणिक संस्थाएँ तथा 21 राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय तथा डीम्ड विश्वविद्यालय थे।

औद्योगिक विकास

राजस्थान अनेक औद्योगिक घरानों की जन्मभूमि है। यहाँ की धरा ने स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल, बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया, बॉगड़, पौद्दार आदि उद्योगपतियों को जन्म दिया है। इन्होंने देश और विदेश में औद्योगिक और व्यापारिक जगत में ख्याति अर्जित की है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त था। राज्य में बिजली, पानी व यातायात के साधनों के अभाव के कारण बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का विकास संभव नहीं था। इसके अलावा राजस्थान के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में केन्द्र सरकार के कुल निवेश का लगभग 2 प्रतिशत भाग ही पाया जाता है। आज राजस्थान योजनाबद्ध विकास के 62 वर्ष पूरे कर चुका है। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचागत संरचना और आधारभूत सामाजिक सरचंना के विकास पर काफी बल दिया है। राज्य में केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम भी है। विगत में केन्द्र सरकार ने यहाँ के कई जिलों को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया था। केन्द्रीय सब्सिडी की व्यवस्था के अनुसार पिछड़े जिलों को सब्सिडी का लाभ मिला। राज्य सरकार यहाँ से पलायन कर गये उद्योगपतियों तथा देश–विदेश के अन्य उद्यमियों को राज्य में विनियोग बढ़ाने हेतु आकर्षित करके के लिए प्रयत्नशील है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर 23 व 24 सितम्बर, 2000 को जयपुर में 'अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मलेन–2000' का आयोजन किया गया। अब राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति सन्तोषजनक होने के कारण बड़े उद्यमियों की मनोवृत्ति बदल रही है। उद्यमियों के कदम राज्य में निवेश के लिए बढ़ने लगे हैं। फिर राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन बहुतायत में उपलब्ध है। यहाँ विभिन्न उद्योगों के विकास की खूब संभावनाएं हैं। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों का विकास किया जाए तो यह देश के औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न राज्यों की श्रेणी में आ सकता है।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का भाग – राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग का भाग 2000–01 में 27.8 प्रतिशत था जो 2005–06 में बढ़कर 29. 7 प्रतिशत हो गया । वित्त वर्ष 2011–12 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग का भाग स्थिर (2004–05) कीमतों पर 29.85 प्रतिशत रहा है।

उद्योग वृद्धि दर – राजस्थान में खनन व विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2005–06 में 12.09 प्रतिशत उल्लेखनीय रही। वित्त वर्ष 2008–09 में खनन व विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि दर घटकर 3.21 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) रह गई। वैश्विक मंदी 2008 का असर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा।

वैश्विक मंदी का राजस्थान पर प्रभाव – वैश्विक मंदी 2008 से विश्व अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। इससे अनेक विकसित देशों की विकास दर घटी। भारत की अर्थव्यवस्था पर हालांकि वैश्विक मंदी का असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, किन्तु भारत की विकास दर 2008–09 में घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई जबकि यह 2007–08 में 9.3 प्रतिशत थी। भारत की औद्योगिक विकास दर 2008–09 में 2.5 प्रतिशत तक गिर गई।

स्थिर कीमतों (1999–2000) पर राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2005–06 में 6.70 प्रतिशत थी जो घटकर 2008–09 में 5.48 प्रतिशत रह गई। वित्त वर्ष 2008–09 में खनन व विनिर्माण वृद्धि दर 3.21 प्रतिशत तक गिर गई। इससे स्पष्ट है राजस्थान की

अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी 2008 का अधिक प्रभाव पड़ा है।

पंजीकृत फैक्ट्रियां – राजस्थान में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 1987 में 9665 थी जो 2007 में बढ़कर 10001 हो गई।

लघु उद्योगों का विकास – अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार ने लघु उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया है। लघु उद्योगों में काफी व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। राज्य में लघु उद्योगों की पंजीकृत इकाइयां 1975–76 में 20102 थी जो 2008–09 में बढ़कर 3.20 लाख हो गई। लघु उद्योगों में 1975–76 में 1.37 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था। लघु उद्योगों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 2008–09 में बढ़कर 13.16 लाख हो गई। लघु उद्योगों में विनियोजित पूंजी 1975–76 में 72.37 करोड़ रूपए से बढ़कर 2008–09 में 8888.21 करोड़ रूपए हो गई।

खादी एवं ग्रामोद्योग – खादी एवं ग्रामोद्योग की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करना, कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाना, सहकारिता की भावना जागृत करना, कच्चा माल तथा आवश्यक औजारों की पूर्ति द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना है। राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'फैशन फोर डवलपमेंट योजना' संचालित की जा रही है। राज्य में गुणवत्ता पूर्ण एवं आकर्षक खादी वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2008–09 में खादी का 18.14 करोड़ रूपए का उत्पादन एवं ग्रामोद्योग में 301.79 करोड़ रूपए का उत्पादन हुआ।

औद्योगिक उत्पादन – वर्तमान में राजस्थान में सूती एवं सिंथेटिक रेशे की इकाइयां, ऊनी, चीनी, सीमेन्ट, टेलीविजन, टायर टयूब फैक्ट्री, वनस्पति तेल की मिलें, इंजीनियरी की औद्योगिक इकाइयां, खनिज आधारित बड़ी एवं मध्यम इकाइयां है। राजस्थान से मुख्य रूप से रत्न, आभूषण, टेक्सटाइल, अभियांत्रिक वस्तुएं, रेडीमेड वस्त्र, दस्तकारी वस्तुएं, रसायन, कृषि उत्पादन, खनिज आधारित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है।

राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन में 36 उत्पाद है। इनमें से कुछ प्रमुख उत्पादन इस प्रकार है:– वर्ष 2008 में वनस्पति घी का उत्पादन 57480 टन, खाद्य तेल 120866 टन, सूती कपड़ा 203.40 लाख मीटर, सिथेंटिक तागा 536.60 लाख कि.ग्रा., यूरिया 371883 टन, सल्फयूरिंक एसिड 594045 टन, सीमेन्ट 101.20 लाख टन, वाटर मीटर 89592 आदि।

प्रमुख वृहद उद्योग – राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों में सीमेन्ट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, नमक उद्योग, कांच उद्योग आदि है।

(1) राजस्थान सीमेन्ट उद्योग में भारत का अगुआं राज्य माना जाता है। प्रान्त में सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी (बून्दी) में सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित की गई। इसके बाद सवाईमाधोपुर में 'जयपुर उद्योग लि0' (प्रारंभिक उत्पादन 1953 से 1959) स्थापित किया गया, किन्तु इस उद्योग में 1986 से उत्पादन बन्द है। इनके अलावा राज्य के प्रमुख सीमेन्ट संयंत्रों में बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स (चित्तौड़गढ़), उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स (उदयपुर), जे.के. सीमेन्ट वर्क्स (निम्बाहेड़ा), मंगलम सीमेन्ट मोडक (कोटा), जे.के. व्हाईट सीमेन्ट (गोटन), श्रीसीमेन्ट लिमिटेड (ब्यावर) प्रमुख है।

(2) सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग है। यह उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर शहर में 1889 में कृष्णा मिल्स लिमिटेड निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। इसके पश्चात् ब्यावर शहर में ही 1906 में एडवर्ड मिल्स लि0 व 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लि0 स्थापित हुई। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग में निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में सूती वस्त्र की मिलें है।

(3) राजस्थान में चीनी की तीन मिलें है। राज्य में सर्वप्रथम 1932 में मेवाड़ चीनी मिल्स भोपाल सागर (चित्तौडगढ़) की स्थापना हुई। यह चीनी मिल निजी क्षेत्र में है। इसके बाद 1938 में गंगानगर चीनी मिल्स की स्थापना हुई। इसमें उत्पादन 1946 से प्रारम्भ हुआ। एक

जुलाई 1956 से यह सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही है। राज्य में 1965 में श्री केशोरायपाटन सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई जो विगत कुछ वर्षों से बन्द है। राजस्थान में चीनी की तीनों मिलें निजी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में होने के कारण तीनों प्रकार के संगठनों के उत्पादन की तुलना करने का अवसर प्रदान करती है।

(4) **नमक उद्योग** – नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्त्वपूर्ण स्थान है। नमक उत्पादन से संबंधित सभी अनुकूल दशाएं प्रान्त में उपलब्ध है। यहाँ खारे पानी की झीलें बहुतायत में है। वर्तमान में राज्य में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में नमक का उत्पादन किया जा रहा है।

सांभर में नमक का उत्पादन भारत सरकार का उपक्रम हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कम्पनी सांभर सांल्ट्स लिमिटेड की देख रेख में होता है। सांभर झील नमक उत्पादन में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में नमक पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम डीडवाना में तीन तथा एक पंचमदरा में है। इसके अलावा राज्य में निजी क्षेत्र में लघु पैमाने के नमक उद्योग है जिनमें पोकरण, फलौदी, कुचामन व जाब्दीनगर (नागौर) प्रमुख है।

(5) **कांच उद्योग** – कांच बनाने में बालू मिट्टी, सिलिका मिट्टी, सोडा सल्फेट, शीरा, चूने का पत्थर आदि प्रमुख होते हैं। ये सभी राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कांच बनाने वाले कुशल मजदूर भी राज्य में हैं। राजस्थान में कांच बनाने में धौलपुर के दो कारखाने विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक धोलपुर ग्लास वर्क्स निजी क्षेत्र में कार्यरत है तथा दूसरा कारखाना हाईटैक प्रेसीजन ग्लास वर्क्स, धौलपुर है जो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अन्तर्गत है एवं मदिरा विभाग के लिए बोतलों का उत्पादन करता है। उदयपुर में भी कांच का कारखाना है।

(6) **वनस्पति घी उद्योग** – मूंगफली व बिनौले का तेल वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में भीलवाड़ा में वनस्पति घी का कारखाना खोला गया। इसके बाद जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौडगढ़ व गंगानगर आदि शहरों में स्थापित हुए। राज्य में वनस्पति घी की मांग में हो रही वृद्धि के साथ वनस्पति घी का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं रोजगार वृद्धि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना प्रस्तावित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) औद्योगिक सेवाओं एवं व्यापार हेतु एक विशेष सीमांकित क्षेत्र है जिन्हें 'डीम्ड फोरेन टेरिटरी' का दर्जा देते हुए सीमा उत्पाद शुल्क एवं अन्य शुल्कों से मुक्त रखा गया है।

राजस्थान में सीतापुरा (जयपुर) में जैम्स एवं ज्वैलरी हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा जोधपुर में हैण्डीक्राफ्ट एवं ग्वार गम की इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना प्रगति पर है। जयपुर में रीको और महिन्द्रा लाईफ स्पेस डवलपर लिमिटेड द्वारा जयपुर–अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पब्लिक प्राइवेट पॉर्टनरशिप (पीपीपी) के अन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है।

राजस्थान के औद्योगिक विकास ने अब गति पकड़ ली है। राज्य में आधारभूत संरचना के सुधर जाने से अब आई.टी. क्षेत्र की दिग्गज कम्पनियां जैसे इनफोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, टेक महिन्द्रा, नगारो आदि राज्य में निवेश में रूचि दिखा रही है।

कृषि विकास

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का भाग 75.07 प्रतिशत है। यह ग्रामीण जनसंख्या जीवन यापन के लिए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र पर निर्भर है।

राजस्थान का भूमि उपयोग उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 2008 में 34270 हजार हैक्टेयर था। इसमें सकल कृषिगत क्षेत्र 22208 हजार हैक्टैयर था जो

रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 64.80 प्रतिशत था। राज्य में 2007–08 में विभिन्न स्त्रोतों से सकल सिंचित क्षेत्र 8088 हजार हैक्टैयर था जो सकल कृषिगत क्षेत्र का 36.42 प्रतिशत था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान – किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि ा में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि, उद्योग और सेवाएं के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। वित्त वर्ष 2008–09 में स्थिर (2004–05) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 21.42 प्रतिशत, उद्योग का योगदान 31.40 प्रतिशत तथा सेवाओं का योगदान 47.19 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2011–12 के अग्रिम अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 22.09 प्रतिशत, उद्योग का योगदान 29.85 प्रतिशत तथा सेवाओं का योगदान 48.06 प्रतिशत था। पिछले कुछ वर्षों में (2008–09 से 2011–12) सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान को देखे तो पाते हैं कि स्थिर कीमतों (2004–05) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 22 प्रतिशत स्थिर सा हो गया है।

कृषि वृद्धि दर – कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं की वृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। इसके पीछे कारण कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का मानसून पर निर्भर होना है। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र वृद्धि दर 2005–06 में ऋणात्मक 0.88 प्रतिशत थी। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र वृद्धि दर 2008–09 में बढ़कर 6.12 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) हो गई। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2009–10 में कृषि उत्पादन में 2009–10 में पिछले वर्ष की तुलना में 35.84 प्रतिशत कम रहने की संभावना है।

राजस्थान की प्रमुख फसलें

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। राज्य में रबी की फसलों में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी, गन्ना, तारामीरा, जीरा, धनिया, आलू, मटर, अफीम तथा खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, चावल, मूँग, मोठ, अरहर, सूरजमुखी आदि मुख्य है।

खाद्यान्न उत्पादन

योजनाबद्ध विकास में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। यहाँ खाद्यान्न उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृति देखने को मिलती है। इसका कारण कृषि का मानसून पर निर्भर होना है। खाद्यान्न उत्पादन 1960–61 में 45.41 लाख टन था जो बढ़कर 1990–91 में 109.35 लाख मैं. टन हो गया । खाद्यान्न का उत्पादन 2011–12 में और बढ़कर 209.45 लाख मैं. टन (प्रावधानिक) हो गया।

खाद्यान्न उत्पादन में अनाज और दालों के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। अनाज में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ प्रमुख फसलें है। बाजरा पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसल है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। देश के कुल बाजरा उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान में होता है। देश के कुल मक्का उत्पादन का 1/8 भाग राजस्थान में होता है। देश में उत्तरप्रदेश के बाद सबसे अधिक जौ का उत्पादन राजस्थान में होता है।

राजस्थान में 2008–09 में अनाज उत्पादन 140.55 लाख टन, दलहन उत्पादन 18.98 लाख टन, इन दोनों को मिलाकर खाद्यान्न उत्पादन 159.53 लाख टन (संभावित) था।

तिलहन – देश में खाद्य तेलों का अभाव है। खाद्य तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा भण्डार खर्च होते है। राजस्थान में तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है। हाल ही के वर्षों में राजस्थान "तिलहन क्रान्ति" की ओर अग्रसर हुआ है। राज्य में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, राई व सरसों, अलसी, तारामीरा का उत्पादन होता है।

राजस्थान में तिलहन का उत्पादन 1960–61 में 1.72 लाख टन था जो 1990–91 में बढ़कर 23.56 लाख टन हो गया। तिलहन का उत्पादन 2007–08 के 42.29 लाख टन की तुलना में 2008–09 में 55.36 लाख टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में 30.91 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। तिलहन के अन्तर्गत खरीफ फसल में

मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरण्डी तथा रबी फसल में राई व सरसों, तारामीरा व अलसी सम्मिलित हैं।

गन्ना – गन्ना चीनी उद्योग का कच्चा माल है। राजस्थान में गन्ने का उत्पादन बूंदी, उदयपुर, गंगानगर, चित्तौडगढ़ आदि जिलों में होता है। राज्य में गन्ने का उत्पादन अधिक नहीं होता है। गन्ने का उत्पादन 2007–08 में 5.94 लाख टन की तुलना में 2008–09 में 3.02 लाख टन होने की संभावना है जो 49.16 प्रतिशत कमी दर्शाता है।

कपास – कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। राज्य में कपास विशेषतः गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बोई जाती है। कपास का उत्पादन 2007–08 में 8.62 लाख गाँठें था जबकि 2008–09 में 7.26 लाख गाँठें उत्पादित होने की संभावना है जो 15.78 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

फल, सब्जियाँ और मसाले – राज्य के प्रमुख फल पपीता, अमरूद, सन्तरे हैं। सब्जियों में आलू व प्याज का उत्पादन होता है। इनके अलावा यहाँ जायकेदार मसालों का भी उत्पादन होता हैं। मसालों में सूखी मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाईन, मैथीं, हल्दी, अदरक, सौंठ, लहसुन का उत्पादन होता है।

हरित राजस्थान

विश्व में आर्थिक विकास की दौड़ के कारण पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ चुका है। आज प्राकृतिक आपदाएँ, खाद्यान्न संकट, ऊर्जा संकट आदि घटनाएँ बढ़ रही हैं। इन सब संकटों का संबंध सामान्यतया जलवायु परिवर्तन से है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण प्रकृतिजन्य संकट उत्पन्न हो गये हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समुद्री जल स्तर के बढ़ने सें भू–भाग तेजी से घट रहा है। पवित्र गंगा नदी भी प्रदूषण से ग्रसित हो गई है। आकाश की ओजोन परत के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता घट चुकी है। पृथ्वी का तापमान निरन्तर बढ़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देश और अन्य परमाणु शक्ति सम्पन्न देश जिम्मेदार हैं। इन देशों के विकास से बढ़ता कार्बन उत्सर्जन लोगों की सहन करने की क्षमता से बहुत अधिक बढ़ चुका है। प्राकृतिक संसाधनों के निर्मम संहार के चलते जलवायु परिवर्तन ज्वलंत समस्या और बड़ी चुनौती है।

जलवायु परिवर्तन पर चिंतन करने और इससे निपटने के लिए विश्व के देश 7–8 दिसम्बर 2009 को डेनमार्ग की राजधानी कोपेनहेगन में इकट्ठा हुए। भारत ने 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में 15 से 20 प्रतिशत कटौती की स्वेच्छा से घोषणा की है। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में कम है।

भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान विकासशील राज्य है। हालांकि राजस्थान औद्योगिक विकास की दृष्टि से कम विकसित है, किन्तु इस राज्य को जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान का पश्चिम भाग मरूस्थल है। यहाँ का तापमान अधिक है। मानसून में अनिश्चितता बढ़ चुकी है। अकाल और सूखे की समस्या है। भू–जल स्तर काफी नीचे जा चुका है।

राजस्थान में वन क्षेत्र – राजस्थान में 2005–06 में कुल वन क्षेत्र 32,627 वर्ग किलोमीटर था जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.54 प्रतिशत है। यह वन प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33 प्रतिशत होने से बहुत कम है। किन्तु वर्ष 2000–01 में राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.60 था। इस प्रकार पाँच वर्षों में 1.94 प्रतिशत वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है जो सकारात्मक है।

वन पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। वनों का महत्व अतीत से है। एक वृक्ष लगाने के महत्व को गुणवान पुत्रों के बराबर माना गया है। भारतीय संस्कृति में लोग वृक्षों को पूजते आ रहे हैं। वृक्षों से प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती है। जीवन में वृक्षों का अधिक महत्व है। इसके बावजूद भी लोग वृक्षों को काटने से नहीं चूकते हैं। ऐसे लोग निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए भविष्य को भूलकर स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं।

हरित राजस्थान का शुभारंभ – दुनिया जलवायु में परिवर्तन से चिन्तित है। राजस्थान में जल स्तर के गिरने से

पानी की समस्या गंभीर हो चुकी है। पर्यावरण की चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए ''हरित राजस्थान'' अभियान शुरू किया गया है। जिसका शुभारम्भ 18 जून 2009 को शिक्षा संकुल प्रांगण जयपुर में वृक्षारोपण कर किया। हरित राजस्थान केवल एक वर्ष के लिए नहीं बल्कि पूरे पांच वर्ष और इससे आगे भी निरन्तर क्रियान्वित करने का कार्यक्रम है। स्पष्ट है यह किसी समय विशेष के लिए नहीं अपितु सतत् चलने वाली गतिविधि है। हरित राजस्थान राज्य सरकार का एक ऐसा महाभियान है जिससे आने वाले वर्षों में राज्य में वन क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री की पहल पर हरित राजस्थान को मनरेगा से जोड़ा गया है। इससे गांवों के नागरिकों की वृक्षारोपण में भागीदारी निर्धारित हो गई है। गांव के गरीबों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

जन चेतना – डूँगरपुर के खेमारू गांव में 12 अगस्त 2009 को एक ही दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक छह लाख पौधे लगाने का विश्व का अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया गया है। एक साथ इतनी संख्या में पौधे लगाने से जन चेतना जागृति को बल मिलेगा।

वन विकास के कदम– राज्य में वन क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीण युवाओं में पर्यावरण, वन्य जीव और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढाने के लिए युवकों को 'वन मित्र' के रूप में रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की गई है। वन रक्षकों के रिक्त पदों को भरने तथा नये वन रक्षकों की भर्ती की पहल की गई है।

वन्य जीवों की सुरक्षा – राजस्थान में बाघों की सुरक्षा के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत् ''बाघ संरक्षण बल'' के गठन की दिशा में प्रयास प्रारम्भ किये गये है। रणथम्भौर और सरिस्का में बाघों की वंशवृद्धि में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए बाघों का डीएनए टेस्ट कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इससे शिकार के मामले की जांच आसान हो जायेगी साथ ही वन्य जीवों में पारिवारिक रिश्तों के प्रभाव का आकलन भी आसानी से हो सकेगा। रणथम्भौर के बाघों से सरिस्का अभयारण्य को फिर से आबाद किया जा रहा है। रणथम्भौर नेशनल पार्क (सवाई माधोपुर) की गिनती देश के श्रेष्ठ बाघ परियोजना क्षेत्रों में होती है।

वन सम्पदा संरक्षण – राज्य के सघन वन क्षेत्रों में औषधीय पौधे लुप्त होने जा रहे हैं। राज्य सरकार औषधीय पौध संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। औषधीय पौधे विशेष रूप से गूगल, सालर, सफेद मूसली, बीजासाल आदि के सरंक्षण के लिए वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में वन कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्राकृतिक वनों में जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न कार्यों के साथ ही साथ वन क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण के भी उपाय किये गये हैं।

हरित राजस्थान की प्रगति – राजस्थान सरकार ने सम्पूर्ण राजस्थान में वर्ष 2009 में अगस्त माह के अन्त में 30 हजार हैक्टेयर में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान में ''हरित राजस्थान'' अभियान के अन्तर्गत सितम्बर–अक्टूबर 2009 तक लगभग 50 हजार हैक्टैयर भूमि में 2.50 करोड़ पौधे लगाये गये है। सड़कों के किनारे भी 394 किलोमीटर, रोड सहारे 44,772 पौधे लगाये गये हैं। हरित राजस्थान अभियान में राज्य सरकार के साथ–साथ निजी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्टों और शिक्षण संस्थाओं ने भी भूमिका निभाई है। राज्य में हरित राजस्थान की प्रभावी शुरूआत हुई है। 'हरित राजस्थान' की सफलता राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं के साथ मानसून पर भी निर्भर करती है। 'हरित राजस्थान' वृक्षारोपण का महा अभियान है । इस कारण कम बरसात का असर पौधों के संरक्षण पर पड़ सकता है। मगर यह निश्चित है हरित राजस्थान से राज्य का वनक्षेत्र बढ़ेगा।

प्रेरणा स्त्रोत – आज दुनिया जलवायु परिवर्तन की चपेट में है। राजस्थान ने प्रकृति की मार सदैव सही है। इसका पश्चिम भाग रेत के धोरों से पटा है। राजस्थान ने इन्दिरा गॉधी नहर परियोजना से मरूस्थल का कायाकल्प किया है । अब पूरा देश प्रदेश के 'हरित राजस्थान' को आश्चर्य से देख रहा है। जब मरूस्थलीय प्रदेश में 'हरित राजस्थान'

की प्रभावी शुरूआत संभव है। ऐसी स्थिति में भारत में वनक्षेत्र को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को भीषण होने से रोका जा सकता है। हरित राजस्थान अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनता जा रहा है।

हरित भारत की नींव – भारत में मध्य साठ के दशक में कृषि विकास के लिए हरित क्रान्ति लागू की गई थी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ भी कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए हरित क्रान्ति की शुरूआत की गई। हरित क्रान्ति के कारण आज भारत एक अरब से अधिक लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराने की स्थिति में आ सका है। आज जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक खाद्यान्न संकट के समाधान में भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन विश्व की विकट समस्या है। राजस्थान का 'हरित राजस्थान' सम्पूर्ण देश में 'हरित भारत' की नींव का काम करेगा।

हरित क्रान्ति से राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ा, किन्तु भारत के खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान की भूमिका अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ सकी। इसका कारण मानसून की अनिश्चितता के कारण खाद्यान्न में उच्चावचन की प्रवृत्ति है। अब हरित राजस्थान के गति पकड़ने से राजस्थान का पारिस्थितिकी संतुलन सुधरेगा। वनों के बढ़ने से मानसून की अनिश्चितता घटेगी । हरित राजस्थान से हरित क्रान्ति भी फलीभूत होगी। हरित राजस्थान की सफलता राज्य सरकार के प्रयत्नों से ज्यादा जन सहयोग पर निर्भर करेगी।

'हरित राजस्थान' एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे केवल राजस्थान सरकार का अभियान नहीं माना जाना चाहिये। प्रकृति को बचाने वाला यह कार्यक्रम जन–जन का है। राजस्थान सरकार अधिक से अधिक पौधे लगाये और उनकी देखभाल आम लोग करे, साथ में वे स्वयं भी पौधे लगाये तो हरित राजस्थान की सफलता निश्चित है।

राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में 75.07 प्रतिशत भाग ग्रामीण जनसंख्या का है। गांवों में गरीबी की समस्या मुखर है। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया है। योजनाबद्ध विकास और आर्थिक उदारीकरण में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर भारी राशि खर्च की गई है। मनरेगा इसका ज्वलंत उदाहरण है। केन्द्र सरकार ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील है। केन्द्र सरकार की कई योजनाएं इस दिशा में राजस्थान में क्रियान्वयन में है। राजस्थान सरकार ने भी ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के अनेक कार्यक्रम चालू कर रखे हैं।

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के उद्देश्य – ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता की गरीबी को दूर करना, ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ढांचागत विकास करना, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन, ग्रामीण विषमता को दूर करना तथा गरीब व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को बेहतर बनाना है।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजस्थान में ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं क्रियान्वयन में है जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख है :

(अ) केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं :–

1. **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना** – भारत सरकार ने एक अप्रेल 1999 से स्वर्ण जयन्ती ग्रामस्वरोजगार योजना प्रारम्भ की। इसका उद्देश्य गरीबों को समुचित आजीविका उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योगों की स्थापना करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है।

2. **इन्दिरा आवास योजना** – ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इन्दिरा आवास योजना शुरू की। एक जनवरी 1996 से यह योजना पूर्णरूप से एक स्वतंत्र योजना है। योजना का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अथवा जिला परिषदों द्वारा किया जाता है।

3. **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना** – इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकारों का वित्तीय अनुपात 75:25 है। यह योजना पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना का वृहद रूप है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में परिसम्पत्ति निर्माण तथा बेरोजगारों को पूरक रोजगार उपलब्ध कराना है।

4. **मरू विकास कार्यक्रम** – 1.4.1995 से जलग्रहण (वाटर शैड) के तहत राजस्थान में मरू विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रारम्भ में शत–प्रतिशत सहायता भारत सरकार की थी। एक अप्रैल 1999 से भारत सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए 75 प्रतिशत राशि केन्द्र प्रवर्तित योजना के हिस्से में उपलब्ध कराना तय किया है तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य द्वारा वहन की जायेगी।

5. **सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम** – यह कार्यक्रम जल संग्रहण के आधार पर 1.4.95 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें 1999–2000 से 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार का तथा 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का है।

6. **एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना** – एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना एक केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम है जो 1992–93 से प्रारम्भ किया गया। बंजर भूमि की दृष्टि से राजस्थान बड़ा राज्य है।

7. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** – यह कार्यक्रम राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के चार जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर में क्रियान्वित किया जा रहा है। इन सीमावर्ती जिलों में आधारभूत विकास के लिए भारत सरकार राशि उपलब्ध कराती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सुरक्षा उपायों को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा इन जिलों में सड़क निर्माण, विद्युतीकरण, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा, भेड़ एवं ऊन, शिक्षा, पशुपालन तथा मानव संसाधन विकास आदि विकास कार्यों को महत्व दिया गया है।

8 **सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम** – यह पूर्णतः केन्द्रीय प्रवर्तित योजना वर्ष 1992–93 से प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है। इस योजना में सांसदों को संसदीय क्षेत्रों के विकास के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है।

9. **बायोगैस कार्यक्रम** – ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1981 से बायोगैस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पारम्परिक ऊर्जा न तो उपलब्ध है और न ही आर्थिक रूप से उपयोगी है, ऐसे क्षेत्रों के लिए बायोगैस शुद्ध प्रदूषण रहित एवं नवीन ऊर्जा स्त्रोत है।

10. **बन्धुआ मजदूर** – बन्धुआ मजदूर की खोज, मुक्ति एवं उनके पुनर्वास बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा है। मानव बन्धन की इस बुराई के उन्मूलन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। बन्धुआ मजदूर को मुक्त कराते ही तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इसके अलावा मुक्त बन्धुआ मजदूर को कृषि भूमि उपलब्ध कराई जाती है। (यदि कृषि भूमि उपलब्ध हो) तथा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना और इन्दिरा आवास योजना आदि में प्राथमिकता दी जाती है।

11. **जीवन धारा** – जीवन धारा योजना वर्ष 1995–96 तक जवाहर रोजगार योजना का भाग थी। वर्तमान में यह योजना अलग से क्रियान्वयन में है। इस योजना में लघु एवं सीमान्त कृषकों को कुओं के निर्माण एवं अन्य लघु सिंचाई कार्यों हेतु शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

12. **बीस सूत्री कार्यक्रम** – भारत में योजनाबद्ध विकास का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रहा है। देश में गरीबी उन्मूलन हेतु बीस सूत्री कार्यक्रम का शुभारम्भ भूतपूर्व

प्रधानमंत्री स्व.श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने एक जुलाई 1975 को किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी, बीमारियां एवं कुपोषण दूर करना है। समाज के गरीब तबकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। बीससूत्री कार्यक्रम में 1982 तथा 1986 में संशोधन किया गया।

राजस्थान में बीस सूत्री कार्यक्रम का शुभारम्भ वर्ष 1975 में किया गया। वर्तमान में इसका क्रियान्वयन समाज के गरीब वर्गो के उत्थान एवं उनके आर्थिक विकास के लिए किया जा रहा है। बीस सूत्री कार्यक्रम का गरीबी निराकरण से सीधा संबंध है। राजस्थान सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम को पूरी लगन से लागू किया है। राजस्थान ने 20 बीस सूत्री कार्यक्रम को अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया है।

बीस सूत्री कार्यक्रम की 20 प्रमुख मदें इस प्रकार है :–

1. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
2. अधिशेष भूमि का वितरण
3. पेयजल की सुविधा
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
6. टीकाकरण
7. आई.सी.डी.एस.
8. आंगनबाडी
9. अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता
10. अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता
11. इन्दिरा आवास योजना
12. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आवास
13. निम्न आय वर्ग के आवास
14. गंदी बस्ती सुधार
15. निजी भूमि पर वृक्षारोपण
16. सार्वजनिक एवं वन भूमि के अन्तर्गत संग्रहित क्षेत्र
17. विद्युतीकृत गांव
18. उर्जाकृत पम्पसेट
19. उन्नत चूल्हें
20. बायोगैस संयंत्र।

13. **जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना** – राजस्थान में जुलाई 2000 में विश्व बैंक की सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना का शुभारम्भ हुआ। यह परियोजना गरीबों के उत्थान के लिए राज्य के सात जिलों बारां, चूरू, दौसा, धोलपुर, झालावाड़, राजसमंद, टोंक में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चयनित राज्य के सात जिलों में गरीबी कम करना है।

(ब) राज्य योजनाएँ

1. **अपना गांव–अपना काम योजना** – यह योजना जनवरी 1991 से राज्य में विकास की प्रक्रिया एवं स्थानीय आयोजना में लोगों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस योजना के अनुसार किसी भी सामुदायिक विकास कार्य के लिए ग्रामीण/दानदाताओं/ गैरसरकारी संथाओं/सामुदायिक समूह को न्यूनतम 30 प्रतिशत राशि जन सहयोग के रूप में देनी होती है तथा 50 प्रतिशत राशि इस योजना के कोष से उपलब्ध करवाई जाती है। यदि प्रस्तावित कार्य इस योजना में स्वीकृत योग्य होते है तो शेष राशि इस योजना से ही उपलब्ध करवाई जाती है।

2. **जिला काम योजना** – जिलों में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के सर्वोतम उपयोग एवं स्थानीय नियोजन एवं विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को अधिकतम सीमा तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1991–92 से राज्य के सभी जिलों में यह योजना चलाई जा रही है। जिले की स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए प्रतिवर्ष जिले में एक विशेष प्रकृति के कार्य का चयन कर क्रियान्वयन किया जाता है।

3. **विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम** – यह, शत प्रतिशत राज्य योजना वर्ष 1999–2000 में लागू की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विधायक प्रतिवर्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए अपने

सुझाव जिला प्रमुख को देता है।

4. **डांग क्षेत्र विकास योजना** – चम्बल की लम्बी गहरी घाटियों वाला क्षेत्र एवं इसकी सहायक घाटियों वाले क्षेत्र 'डॅाग क्षेत्र' कहलाता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने वर्ष 1995–96 में "डॅाग क्षेत्र विकास कार्यक्रम" नाम से योजना लागू की।

5. **मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम** – अलवर, भरतपुर में मेव आबादी वाला क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने 1987–88 में 'मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम" चालू किया।

6. **वानप्रस्थ योजना** – सेवा निवृत लोगों की स्वैच्छिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए वानप्रस्थ योजना के नाम से एक योजना तैयार की गई है। जिसके अन्तर्गत सेवा निवृत व्यक्ति अपनी रूचि अनुसार स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान कर सकता है।

7. **मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** – राज्य के राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली जिलों के पहाड़ी एवं पिछड़ी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में मूल आधारभूत सुविधाओं का विकास और रोजगार अवसरों का सृजन करना है।

8. **राजीव गॉंधी पारम्परिक जल स्त्रोत संधारण कार्यक्रम** – राज्य में भूमिगत जल में वृद्धि एवं वर्षा के पानी को संरक्षित करने हेतु यह इनोवेटिव योजना अक्टूबर 1999 से प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण हेतु परम्परागत जल स्टोरेज के साधनों जैसे कुआं, बावड़ी, टाका, तालाब, जोहड़ा, नाड़ी आदि की मरम्मत की जाती है। प्रस्तावित कार्य में राज्य सरकार एवं जनता का व्यय अनुपात 70:30 का होगा।

महात्मा गॉंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)

वर्तमान में भारत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान बना चुका है। भारत ने आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक अप्रैल 1951 से योजनाबद्ध विकास का मार्ग प्रारम्भ किया था। छह दशक के योजनाबद्ध विकास में ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएं और छह वार्षिक योजनाऐं पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में बारहवीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में है जिसकी समयावधि एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक है। इस योजनाबद्ध विकास के दौर में वर्ष 1991 से भारत की अर्थव्यवथा को विश्व के बदलते आर्थिक परिवेश के साथ समायोजित करने के लिए आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत की गई। आज आर्थिक उदारीकरण को लागू हुए दो दशक हो चुके हैं। आर्थिक उदारीकरण के कारण आज भारत की गिनती विश्व में चीन के बाद सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में होने लगी है। वैश्विक मंदी 2008 के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था विकास की पटरी पर बनी रही।

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किन्तु योजनाबद्ध विकास की तुलना में आर्थिक उदारीकरण के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भूमिका तेजी से घट गई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 1950–51 में 56.7 प्रतिशत तथा 1990–91 में 34 प्रतिशत था। आर्थिक उदारीकरण के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 2007–08 में घटकर 19.8 प्रतिशत रह गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका तो घट गई, किन्तु कृषि पर निर्भर जनसंख्या में कमी नहीं हुई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 68.84 प्रतिशत थी। अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका के घटने का अर्थ विकास की दौड़ में कृषि के पिछड़ने से है। स्पष्ट है कि कृषि के पिछड़ने से देश की 69 प्रतिशत ग्रामीण आबादी की माली हालत कमजोर होना है। ग्रामीण भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है। कृषि क्षेत्र में 'छिपी हुई बेरोजगारी' अधिक है इसमें जरूरत नहीं होने पर भी आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे हुए होते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में गांवों के विकास के लिए सरकार ने समय–समय पर कई ग्रामीण विकास और रोजगार परक योजनाएं चलाई। यह भी सत्य

है इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को अपेक्षित रूप से नहीं मिल सका है।

भले ही आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका घट गई, किन्तु गांवों के विकास बिना भारत का विकास अधूरा है। आर्थिक उदारीकरण में योजनाबद्ध विकास की भांति ग्रामीण विकास पर विशेष रुप से बल दिया गया है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए आर्थिक उदारीकरण के दौर में ''मनरेगा'' की शुरूआत की गई। मनरेगा आर्थिक उदारीकरण का सामाजिक दर्शन है। विशेषज्ञों की माने तो मनरेगा हरित क्रान्ति और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे उपायों के समान सामाजिक परिवर्तनकारी कार्यक्रम सिद्ध होने जा रहा है।

मनरेगा

ग्रामीण भारत के अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 (नरेगा) पारित किया गया। नरेगा केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण (फ्लैगशिप) योजनाओं में से एक है। इस योजना की शुरूआत 2 फरवरी 2006 को आन्ध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई थी। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 2 अक्टूबर 2009 को 140वीं जयन्ती पर नरेगा का नया नामकरण किया। अब नरेगा को महात्मा गाँधी के नाम पर ''महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम'' (मनरेगा) से पुकारा जाता है।

मनरेगा को शुरूआत में देश के 200 जिलों में लागू किया। वर्ष 2007–08 में इसका 130 और जिलों में विस्तार किया गया। मनरेगा को एक अप्रेल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया।

मननरेगा की प्रमुख विशेषताएँ

1. मनरेगा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देता है।

2. रोजगार उपलब्ध कराने की लागत का 90 प्रतिशत भार केन्द्र वहन करता है और 10 प्रतिशत खर्च राज्य सरकारें वहन करती है।

3. कार्य के लिए आवेदन करने के बाद 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध कराएगी। अन्यथा आवेदक को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

4. मनरेगा कार्य स्थल पर शिशु सदन, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता और शेड उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कार्यस्थल पर कार्य के विवरण के साथ नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाएगा।

5. काम करने वाले मजदूरों के नाम रजिस्टर में दर्ज होंगे। कार्य स्थल निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। समय पर मापन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. मनरेगा के श्रमिकों को जननी बीमा योजना की सुरक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

मनरेगा के कार्य

मनरेगा के अन्तर्गत गांवों के विकास की परियोजनाएं चलायी जा रही है। इसमें भूमि सुधार पर जोर दिया गया है। सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। मनरेगा के कार्यो में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके प्रमुख कार्य सड़क संपर्कता, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण एवं जल संभरण, सूखा रोकने के उपाय, सूक्ष्म सिंचाई कार्य, किसानों के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई का प्रावधान, पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार, भू–विकास कार्य आदि है। मनरेगा में ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुमोदित कार्य भी सम्मिलित किये जाते हैं। पंचाचती राज संस्थाओं की योजना बनाने, निगरानी और कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका होगी।

जॉब कार्ड

मनरेगा में बिना दक्षता वाला हाथ का कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को रोजगार मांगने का अधिकार है। ऐसे परिवार जॉब कार्ड के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन करेंगे। ग्राम पंचायत आवेदक की उम्र और स्थानीय निवास स्थान का सत्यापन करेगी। इसके बाद ग्राम पंचायत परिवार को फोटो सहित

जॉब कार्ड निःशुल्क जारी करेगी। जॉब कार्ड परिवार के पास ही रहना चाहिए। जॉब कार्ड धारक महिला/पुरूष काम के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते है। मनरेगा में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी का भी प्रावधान है।

बजटीय आवंटन – मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2006–07 में मनरेगा पर वित्तीय आवंटन 8600 करोड़ रूपए था जो बढ़कर 2008–09 में 30000 करोड़ रूपए (संशोधित) तथा 2009–10 में 30100 करोड़ रूपए हो गया। वित्त वर्ष 2011–12 के केन्द्रीय बजट में मनरेगा के लिए 40000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मनरेगा ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं से अलग है। इसने ग्रामीण बेरोजगारों को सीधे लाभ पहुंचाया है। मनरेगा ने बड़ी संख्या में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार दिया है।

बढ़ता महत्व – मनरेगा सात वर्षो से भी कम समय में भारत के गांवों के कायाकल्प का पर्याय बन चुकी है। इसके माध्यम से गांवों के गरीबों को रोजगार मिलने से तथा ग्रामीण परिवेश में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन होने से चहुंओर खुशहाली नजर आने लगी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मनरेगा से भारत को वैश्विक मंदी 2008 से निपटने में मदद मिली। उल्लेखनीय है मनरेगा से देश के करोड़ों व्यक्तियों के हाथों में पैसा आने से गांवों के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता बाजार को विस्तार मिला है। वैश्विक मंदी से शहरी क्षेत्रों में घटे रोजगार के अवसरों की भरपाई गांवों में मनरेगा ने की है। मनरेगा की एक बड़ी उपलब्धि ग्रामीण व्यक्तियों का शहरों की ओर पलायन रूकना भी है।

सामाजिक अंकेक्षण – मनरेगा के क्रियान्वयन के दौरान भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की बात भी सामने आने लगी है। इसका कारण प्रशासनिक व्यवस्था में खामी होना है। मनरेगा से देश समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। इस बात से मनरेगा का महत्व स्पष्ट हो जाता है। अतः मनरेगा को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए प्रभावी नियंत्रक और पारदर्शी व्यवस्था लागू होनी चाहिये। केन्द्र सरकार के द्वारा राज्यों को मनरेगा के प्रत्येक कार्य का तीन महिने के भीतर सामाजिक अंकेक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'सामाजिक अंकेक्षण' को सार्वजनिक निगरानी की एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। ''सामाजिक अंकेक्षण '' एक प्रक्रिया है, जिसके तहत लोक संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों में उपयोग किये गये वित्तीय एवं गैर वित्तीय दोनों संसाधनों का विस्तृत विवरण प्रायः एक लोक मंच के माध्यम से जनता के साथ साझा किया जाता है तथा यह प्रक्रिया जनता को जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता लागू करने की छूट देकर अन्तिम लाभार्थी को उसके लिए बनी विकास योजनाओं की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करती है।

राजस्थान में मनरेगा

राजस्थान के सभी जिलों में एक अप्रेल 2008 से मनरेगा क्रियान्वयन में है। मनरेगा ने राज्य के गांवों में रोजगार के नये द्वार खोले है। राज्य सरकार मनरेगा के कारगर क्रियान्वयन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। राज्य में मनरेगा योजना के अन्तर्गत पूर्णतया प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आन्ध्रप्रदेश सरकार की तर्ज पर सामाजिक अंकेक्षण के लिए पृथक से सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय का गठन किया गया है। मनरेगा के अधिक वित्तीय आवंटन को देखते हुए राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लेखा शाखा को मजबूत किया गया है।

मनरेगा के मुख्य उद्देश्यों में पर्यावरण रक्षा सम्मिलित है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मनरेगा से 'हरित राजस्थान' को जोड़ते हुए पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण की मुहिम चलायी है। राजस्थान में मनरेगा द्वारा उपलब्ध वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण, वन संरक्षण और चारागाह विकास के कार्य प्रमुखता से कराये जाने लगे है। सड़कों के किनारे वृक्षों की सघन श्रृंखला विकसित की जा रही है। वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर तक 2493.16 करोड़ रुपये व्यय कर कुल 25.07 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये।

बजट

राजस्थान के बजट पर चर्चा करने से पूर्व बजट से संबंधित सामान्य बातों पर प्रकाश डालना आवश्यक होगा। बजट अर्थव्यवस्था का दर्पण होता है। बजट में लिये गये आर्थिक निर्णयों से अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित होती है। इसीलिए सभी व्यक्ति हर वर्ष बजट की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते है। आर्थिक विकास से संबंधित निर्णय बजट में लिये जाते है इसलिए बजट का अधिक महत्व होता है। चूंकि अर्थव्यवस्था गतिशील होती है। राज्यों की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक घटकों से प्रभावित होती है। वर्ष 1991 से आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था में गतिशील प्रवृत्ति ज्यादा हो गई है। वैश्विक मंदी 2008 से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, इसका प्रभाव सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। भारत अपनी आवश्यकता का खनिज तेल बहुत बड़ी मात्रा में विदेश से आयात करके पूरा करता है। यहाँ पेट्रोल, डीजल की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय घटकों से भी प्रभावित होती है। मंहगाई में कभी भी उफान आ जाता है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के अनेक घटक होते हैं। इनसे संबंधित आर्थिक समस्याओं के अचानक खड़ा हो जाने से इनके समाधान के लिए निर्णय भी शीघ्रता से लिये जाते हैं। इसलिए कई बार महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णय बजट से पहले भी लिये जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि बजट में लिये गये निर्णय वित्त वर्ष में पूरी तरह क्रियान्वित भी नहीं होते है। ऐसा होने से बजट की प्रासंगिकता प्रभावित होती है।

भारत का केन्द्रीय बजट प्रत्येक वर्ष सामान्यतया फरवरी माह में लोकसभा में पेश किया जाता है। कई बार देश में आम चुनाव होने, आर्थिक संकट आदि कारणों से केन्द्रीय बजट के स्थान पर अंतरिम बजट भी पेश किया जाता है। भारत में रेलवे बहुत बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसमें केन्द्र सरकार का भारी पूंजी निवेश है तथा बड़ी संख्या में देशवासियों को रोजगार मिला हुआ है। रेलवे का अत्यधिक महत्व होने के कारण लोकसभा में रेल बजट अलग से पेश किया जाता है। केन्द्र सरकार की भांति सभी राज्य सरकारें भी अलग से राज्य बजट पेश करती है। राज्य सरकारें सामान्यतया केन्द्रीय बजट के बाद राज्य बजट पेश करती है। ऐसा करने से केन्द्रीय आर्थिक निर्णय राज्यों के लिए उनके बजट से पहले स्पष्ट हो जाते है।

बजट के उद्देश्य – भारत में जो उद्देश्य और विकास क्षेत्र योजनाबद्ध विकास के मुख्य केन्द्र रहे है, वे ही विगत वर्षो से बजट की नीतियों के रहे हैं, जैसे आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता आदि। योजनाबद्ध विकास के उद्देश्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक है कि बजट की मूल रणनीति योजना की रणनीति के अनुरूप हो।

भारत में 1991 के बाद आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में उदारीकृत आर्थिक नीतियों की महत्ता बढ़ गई है। हालांकि आर्थिक उदारीकरण के दौर में पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण के अनुरूप निर्धारित किये गये है। इसलिए उदारीकृत अर्थव्यवस्था के दौर में भी पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। वर्तमान में बजट की नीतियों में योजनाबद्ध विकास और आर्थिक उदारीकरण के उद्देश्य और विकास क्षेत्र प्रमुख रूप से सम्मिलित किये जाते हैं।

बजट के संबंध में यह बात महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है कि बजट की नीति में चालू वित्त वर्ष में घटित आर्थिक समस्या के निराकरण के कदम प्रमुखता से उठाये जाए। जहां तक राज्यों के बजट का सवाल है, राज्यों के बजट के उद्देश्य, राज्यों के विकास को बढ़ावा देने वाले होने के साथ देश के विकास लक्ष्यों को भी पोषित करने वाले होने चाहिए।

बजट शब्दावली – बजट विश्लेषण से पहले बजट से जुड़ी कुछ शब्दावली को समझना आवश्यक है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) – एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के सम्मिलित बाजार मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें कृषि,

उद्योग और सेवा तीन क्षेत्र सम्मिलित होते हैं।

राजस्व प्राप्ति/व्यय – जब हुई आमदनी को खर्च करने से किसी तरह की अचल सम्पत्ति का निर्माण नहीं होता है। राजस्व प्राप्ति में सरकार को टैक्स से हुई आय सम्मिलित की जाती है जबकि राजस्व व्यय में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, सब्सिडी, ब्याज देने आदि खर्चों को सम्मिलित किया जाता है।

पूंजीगत प्राप्ति/ व्यय – सभी तरह की आमदनी जो किसी भी तरह की सम्पत्ति जैसे शेयर आदि को बेचने (विनिवेश), दिये ऋण पर आने वाले ब्याज आदि को पूंजीगत प्राप्ति कहते है जबकि किसी भी तरह की सम्पत्ति जैसे शेयर, सम्पत्ति आदि को खरीदने पर होने वाले खर्च या लिये ऋण पर देय ब्याज को पूंजीगत व्यय कहते हैं।

राजस्व घाटा – जब वित्त वर्ष में सरकार की राजस्व आय राजस्व व्यय से कम होती है तो उसे राजस्व घाटा कहते है। कायदे से राजस्व घाटा शून्य होना चाहिये।

राजकोषीय घाटा – जब सरकार की आमदनी उसके खर्चो से कम होती है तो सरकार को उस अन्तर को पूरा करने के लिए पब्लिक से उधार लेना पड़ता है जिसे राजकोषीय घाटा कहते हैं।

योजना खर्च – बजट के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले वित्त संसाधन को योजना खर्च कहा जाता है।

राजस्थान का बजट

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में केन्द्र का बजट प्रस्तुत करने के उपरान्त राजस्थान सरकार चालू वर्ष (आलोच्य वर्ष) का अपना बजट राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करती है। यह बजट नियमानुसार राज्य के वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जता है। यदि वित्त मंत्रालय का प्रभार किसी अन्य मंत्री अथवा मुख्यमंत्री के पास धारित हो तो संबंधित मंत्री अथवा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य विधान सभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है।

प्रस्तुत बजट पर राज्य विधान सभा में बहस होने के पश्चात आवश्यक संशोधनों के साथ बजट बहुमत से सदन में पारित किया जाता है।

पारित बजट का प्रकाशन आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया रहा है।

राजस्थान राज्य का बजट संघीय वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत तैयार किया जाता है। राज्य के बजट में राज्य सूची के प्रावधानुसार आने वाले कर और गैर कर तथा राजस्व प्राप्तियों के प्रस्ताव होते हैं। इसके अन्तर्गत, भू–राजस्व, स्टाम्प्स एवं पंजीयन शुल्क, मादक पदार्थ उत्पादन शुल्क, मोटर कर, वेट (बिक्रीकर) मनोरंजन कर आदि तथा विभिन्न सेवाओं पर भी कर लगाया जाते है।

राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण की विभिन्न योजनाऐं भी चलाई जाती है जिन पर व्यय का प्रावधान राज्य बजट में किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार गैर विकास मदों पर भी खर्च करती है, जिसका उल्लेख भी बजट में होता है।

सामान्यतः विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा घाटे का बजट बनाया जाता है। इस घाटे की पूर्ति केन्द्र सरकार एवं राज्य की जनता से ऋण लेकर की जाती है। इस ऋण पर ब्याज राशि चुकानी पड़ती है ब्याज की अदायगी समय पर नहीं होने से ऋण अदायगी प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है।

केन्द्र में गठित वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्र से राज्यों को धन हस्तांतरित किया जाता है। इस सहयोग राशि से ऋणों की अदायगी तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य किए जाते है।

राज्य सरकार द्वारा बजट के प्रावधान अनुसार सामाजिक कल्याण की विविध योजनाएं संचालित की जाती है वहीं राज्य में विकास की दर बढ़ाने के भी अनवरत प्रयास किए जाते है।

प्रतिवर्ष इसी प्रक्रिया के तहत बजट कार्यवाही एवं विकास कार्यो का निष्पादन होता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है –
   (अ) मध्यप्रदेश
   (ब) उत्तरप्रदेश
   (स) राजस्थान
   (द) बिहार
2. भारत के कुल रेल मार्गो का प्रतिशत भाग राजस्थान में है –
   (अ) 11 प्रतिशत
   (ब) 15 प्रतिशत
   (स) 8 प्रतिशत
   (द) 17 प्रतिशत
3. राजस्थान में सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है –
   (अ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8
   (ब) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12
   (स) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14
   (द) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11
4. राजस्थान में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है –
   (अ) डबोक
   (ब) रातानाड़ा
   (स) सांगानेर
   (द) कोटा
5. भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है –
   (अ) बीसलपुर
   (ब) माही बजाज
   (स) व्यास
   (द) भॉखरा नॉगल
6. देश में बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है–
   (अ) प्रथम
   (ब) द्वितीय
   (स) तृतीय
   (द) चतुर्थ
7. राजस्थान में बीस सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया –
   (अ) 1982
   (ब) 1975
   (स) 1986
   (द) 1991
8. भारत में मनरेगा की शुरूआत राज्य से हुई –
   (अ) उत्तरप्रदेश
   (ब) राजस्थान
   (स) आन्ध्रप्रदेश
   (द) गुजरात

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है?
2. राजस्थान में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कितने है?
3. आधारभूत संरचना कितने प्रकार की होती है?
4. उर्जा के परम्परागत स्त्रोतों के नाम बताइये।
5. बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है?
6. इन्दिरा गॉधी नहर परियोजना की कुल लम्बाई कितनी है?
7. राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के नाम बताइये।
8. राजस्थान में 'हरित राजस्थान' की शुरूआत कब हुई?
9. नरेगा का नामकरण मनरेगा कब किया गया?

10. सामाजिक अंकेक्षण क्या है?
11. राजकोषीय घाटा क्या है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. ढांचागत आधारभूत संरचना क्या है?
2. राजस्थान में सड़कों के प्रकार बताइये।
3. राजस्थान रोड विजन 2025 क्या है?
4. राजस्थान में सिंचाई के स्त्रोतों का वर्णन कीजिए।
5. 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' पर टिप्पणी लिखिए।
6. राजस्थान की प्रमुख फसलें कौनसी है?
7. मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं बताइये।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. राजस्थान में परिवहन क्षेत्र की प्रगति का वर्णन कीजिए।
2. राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए।
3. राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का वर्णन कीजिए।
4. जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में 'हरित राजस्थान' के महत्त्व को समझाइये।
5. राजस्थान के बजट पर टिप्पणी लिखिए।

❑❑❑❑

अध्याय–5
राजस्थान में लोकप्रशासन

राजस्थान भारतीय गणराज्य का एक राज्य है, जहाँ अन्य भारतीय राज्यों की तरह संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। सम्पूर्ण राज व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका द्वारा संचालित की जाती है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अथवा लोक प्रशासन का उद्देश्य राज्य के बहुमुखी विकास के साथ–साथ जनता के हितों की रक्षा करना तथा शांति एवं व्यवस्था हेतु कानून का शासन करना है। राजस्थान के लोक प्रशासन के अध्ययन से पूर्व राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है।

राजस्थान का एकीकरण

स्वतन्त्रता से पूर्व राजस्थान विभिन्न छोटी–छोटी रियासतों में बँटा हुआ था तथा इस राज्य का कोई संगठित स्वरूप नहीं था। यह 19 देशी रियासतों, 2 चीफशिप एवं एक ब्रिटिश शासित प्रदेश में विभक्त था। इसमें सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी, तथा सबसे छोटी लावा चीफशिप थी। प्रत्येक रियासत एक राजप्रमुख अर्थात् राजा, महाराजा अथवा महाराणा द्वारा शासित थी तथा प्रत्येक की अपनी राजव्यवस्था थी। अधिकांश रियासतों में आपसी समन्वय एवं सामजंस्य का अभाव था। स्वतन्त्रता के पश्चात् यह आवश्यक था कि समस्त देशी रियासतों का एकीकरण किया जाए। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया समस्त भारतीय एकीकरण का हिस्सा थी। इस कार्य को सम्पन्न करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम् भूमिका निभाई और राजस्थान का एकीकरण एक चरणबद्ध रूप से किया गया। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 17 मार्च, 1948 ई. को प्रारम्भ हुई और 1 नवम्बर, 1956 ई. को पूर्ण हुई। एकीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया सात चरणों में सम्पन्न हुई, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

प्रथम चरण– 'मत्स्य संघ' का निर्माण : 17 मार्च, 1948 को चार रियासतों अर्थात् अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया, जिसका नाम **'मत्स्य संघ'** रखा गया। इस संघ का नामकरण के.एम.मुन्शी के सुझाव पर रखा गया था। मत्स्य संघ का राजप्रमुख धौलपुर के महाराजा को बनाया गया। राज्य में एकीकरण की दिशा में यह पहला कदम था।

द्वितीय चरण – 'संयुक्त राजस्थान' का गठन : राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में 25 मार्च, 1948 को 9 रियासतों–बाँसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, और टोंक को मिलाकर **'संयुक्त राजस्थान'** का निर्माण किया गया। इसकी राजधानी कोटा बनायी गयी।

तृतीय चरण–संयुक्त राजस्थान' :

18 अप्रेल, 1948 को उदयपुर रियासत को पूर्व राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। इसे **'संयुक्त राजस्थान'** का नाम दिया गया। इस नये राज्य का नया विधान बनाया गया जिसमें उदयपुर को राजधानी तथा उदयपुर के महाराजा को राजप्रमुख बनाया गया।

चतुर्थ चरण – 'वृहत् राजस्थान' :

राज्य एकीकरण के चतुर्थ चरण में 30 मार्च, 1949 को राज्य की चार बड़ी रियासतें–जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का संयुक्त राजस्थान में विलय के पश्चात् 'वृहत् राजस्थान' का गठन किया गया। इस वृहत् राजस्थान का व्यापक चर्चा के पश्चात् एक विधान बनाया गया तथा इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई। राज्य के एकीकरण में यह महत्वपूर्ण कदम था, इसी कारण बाद में 30 मार्च को प्रतिवर्ष **'राजस्थान दिवस'** के रूप में स्वीकार किया गया। संयुक्त राजस्थान में राजप्रमुख, महाराज प्रमुख,

उपराज प्रमुख पर क्रमशः जयपुर, उदयपुर, कोटा के महाराजा के साथ ही हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री (मुख्य मंत्री) बनाया गया।

पंचम् चरण– 'संयुक्त वृहत् राजस्थान' :

15 मई, 1949 को **'वृहत् राजस्थान'** और 'मत्स्य संघ' का विलय सम्पन्न हुआ और उन्हें मिलाकर 'संयुक्त वृहत् राजस्थान' का निर्माण किया गया। मत्स्य संघ के विलय से पूर्व इस क्षेत्र की जनता का जनमत जानने के लिये शंकर देव समिति का गठन किया गया तथा इसकी सिफारिश पर ही विलय किया गया।

षष्ठम् चरण– राजस्थान का निर्माण :

26 जनवरी, 1950 को यहाँ की अकेली बची हुई सिरोही रियासत को संयुक्त वृहत् राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। इसी समय भारत एक संप्रभुत्वसम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित किया गया और राज्य को राजस्थान के नाम से उल्लेखित किया गया।

सप्तम् चरण– वर्तमान 'राजस्थान' का निर्माण :

राज्य एकीकरण के अन्तिम चरण में 1 नवम्बर, 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 लागू हुआ। इसके अन्तर्गत कोटा जिले का सिरोंज मध्य भारत (मध्य प्रदेश) को दिया गया तथा अजमेर–मेरवाड़ा, आबू तहसील एवं मध्य भारत (मध्य प्रदेश) राज्य के मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनेल टप्पा वाला भाग राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया।

राजस्थान निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है–

तालिका 5.1

राजस्थान राज्य का निर्माण क्रम

स्तर–क्रम	निर्मित संघ	बनाने की तिथि	सम्मिलित देशी राज्य/रियासतें
प्रथम	मत्स्य संघ	17.3.1948	अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली
द्वितीय	संयुक्त राजस्थान	25.3.1948	बाँसवाड़ा, बूँदी, डूँगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक
तृतीय	संयुक्त राजस्थान (I + II)	18.4.1948	उपर्युक्त + उदयपुर
चतुर्थ	संयुक्त राजस्थान (II+III+IV)	30.3.1949	उपर्युक्त + बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर
पंचम	वृहत संयुक्त राजस्थान (I+II+III+IV)	15.5.1949	उपर्युक्त + मत्स्य संघ
षष्ठम	वृहत संयुक्त राजस्थान (I+II+III+IV+V)	26.1.1950	उपर्युक्त सभी (सिरोही, आबूरोड़ को छोड़कर)
सप्तम	पुनर्गठित राजस्थान	1.11.1956	उपर्युक्त सभी+अजमेर, आबूरोड़, सुनेल टप्पा (सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया) अर्थात् वर्तमान राजस्थान

राज्य की विधायिका

हमारे देश में शासन व्यवस्था के लिये शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को अपनाया गया है जिसे प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानवेत्ता मोन्टेस्क्यू ने दिया था। यह सिद्धान्त बताता है कि कानून निर्माण की शक्ति (विधायिका), उसको लागू करने की शक्ति (कार्यपालिका) तथा कानून व्यवस्था एवं न्याय–निर्णय की शक्तियाँ (न्यायपालिका) अलग–अलग निहित होनी चाहिये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमण्डल अथवा विधायिका होगी। विधायिका से तात्पर्य है जो व्यवस्था को बनाये रखने हेतु विधि निर्माण करती हो। इसे व्यवस्थापिका अथवा विधान मण्डल भी कहते हैं।

राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है, जहाँ एक सदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान है, जिसे **'विधानसभा'** कहते हैं। राज्य विधानसभा राज्य के लिये संविधान के अनुसार विधि निर्माण करती है। इसके सदस्यों अर्थात् विधायकों का चुनाव राज्य के मतदाता करते हैं। वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 200 है।

योग्यता– राज्य विधानसभा का सदस्य बनने हेतु कुछ सामान्य योग्यतायें निर्धारित है जो कि निम्नलिखित हैं–

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो।
3. संसद द्वारा विधि से निर्धारित अन्य योग्यताएँ धारण करता हो।
4. वह राज्य अथवा भारत सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद को धारण नहीं करता हो।
5. वह सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत मानसिकता का तथा दिवालिया घोषित नहीं हो।

कार्यकाल– विधायिका तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल साधारणतया 5 वर्ष होता है, जो शपथ ग्रहण से माना जाता है। राज्य में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपात्काल लगा होने पर संसद द्वारा विधि पूर्वक विधान सभा का एक बार में एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर समय से पूर्व भी विधानसभा भंग कर सकता है तथा इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन प्रभावी हो जाता है।

गणपूर्ति व सत्र– राजस्थान की विधायिका या विधानसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग से होती है। गणपूर्ति के अभाव में किया गया कार्य असंवैधानिक होता है। संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप एक वर्ष में न्यूनतम दो सत्र अवश्य हों तथा दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार वर्तमान में बजट–सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून–सत्र आदि प्रत्येक वर्ष में आहूत करती है।

विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष– राज्य व्यवस्थापिका या विधान सभा अपना एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्य लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की भांति सदन का नियमपूर्वक संचालन करना, सदस्यों के विशेषाधिकारों की सुरक्षा, अनुशासन एवं शांति रखना, सदस्यों को प्रश्न पूछने, प्रस्ताव तथा विधेयक प्रस्तुती की अनुमति देना, मतदान कराने पर परिणाम की घोषणा आदि कार्य करते हैं। अध्यक्ष को सदस्यों द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना देकर विशिष्ट बहुमत से हटाया भी जा सकता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य देखता है।

विधानसभा की प्रमुख शक्तियाँ एवं कार्य– राज्य की विधानसभा की शक्तियाँ व कार्य भी लोकसभा की तरह है। वह संविधान की राज्य सूची व समवर्ती सूची में निर्धारित विषयों पर विधि निर्माण करती है। राज्य सूची में 66 तथा सम्वर्ती सूची में 47 विषय हैं। राज्य के लिए वित्तीय स्वीकृति का कार्य करती है अर्थात् विधानसभा बजट पारित करती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। आवश्यकता पड़ने पर संविधान संशोधन की स्वीकृति दे सकती है। विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग

लेते हैं।

राज्य की कार्यपालिका

हमारे देश में संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ सहयोगी संबंध रहते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार हमारे राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है तथा उनका प्रयोग वह भी सामान्यतः राष्ट्रपति की भाँति मंत्रिमण्डल के परामर्शानुसार करता है। राज्य में भी कार्यपालिका दो प्रकार की रखी गई है प्रथम नाममात्र की एवं संवैधानिक प्रमुख के रूप में तथा द्वितीय वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका अर्थात् जिसके नाम से शासन चलता है। अतः राज्यपाल ऐसी ही कार्यपालिका है। जिसके द्वारा शासन संचालित होता है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग होता है, उसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद् ही वास्तविक कार्यपालिका होती है।

कार्यपालिका सरकार का द्वितीय अंग है, जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियों के रूप में दिये गये कार्य को लागू करने तथा क्रियान्वित करने का कार्य करती है।

हमारे राज्य में भी संविधान के अनुच्छेद् 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल पद पर नियुक्ति की जाती है। यद्यपि नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष हेतु की जाती है, किन्तु राष्ट्रपति उससे पूर्व भी राज्यपाल को हटा सकता है। राज्यपाल पद हेतु कुछ योग्यतायें वांछनीय है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सामान्यतः यह ध्यान रखा जाता है कि वह सम्बन्धित राज्य का नागरिक न हो, आदि।

राज्यपाल द्वारा संविधान प्रदत्त कई शक्तियों को प्रयोग में लाया जाता है जो कि निम्न हैं–

1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना तथा उसके परामर्श पर मंत्रिपरिषद का गठन करना।
2. विधान सभा का सत्र आहूत करना, सत्रावसान की घोषणा, विधान सभा को भंग करना आदि।
3. वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, क्षमादान की शक्तियाँ आदि।

मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद अर्थात् वास्तविक कार्यपालिका– देश में जो कार्य प्रधानमंत्री के है लगभग उसी प्रकार की भूमिका तथा स्थान राज्य में मुख्यमंत्री का होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को परामर्श देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल उसके परामर्शानुसार ही कार्य करता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री पद हेतु पृथक् से योग्यताएं नहीं रखी है, लेकिन राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो, तथा वह विधान सभा का सदस्य हो, यदि वह विधान सभा का सदस्य नहीं है, तो 6 माह में उसे सदस्यता प्राप्त करनी होती है।

यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल न हो तो राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है।

सम्पूर्ण राज्य का शासन, प्रशासन सर्वोच्च रूप में मुख्यमंत्री द्वारा ही चलता है। मुख्यमंत्री अपने दल के कार्यक्रम, नीतियों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप लागू करने हेतु कई कार्य करते है। जो निम्न हैं–

1. सर्वप्रथम् अपनी मंत्रिपरिषद् का गठन करना।
2. मंत्रियों को विभाग बाँटना तथा मंत्रिमण्डल की बैठकें बुलाकर अध्यक्षता करना।
3. राज्य प्रशासन एवं व्यवस्था सम्बन्धी मंत्रिपरिषद् के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराना।
4. सभी मंत्रियों, विभागों की देख–रेख करना तथा समन्वय रखकर सरकार की सुदृढ़ एकता रखना।
5. विधान सभा में शासन सम्बन्धी नीतियों, कार्यों की घोषणा कर विधिवत् रूप दिलाना, सदन का तथा सरकार का नेतृत्वकर्ता होना।
6. राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन अथवा किसी विधेयक के विषय में कोई सूचना माँगे जाने पर

उसे उपलब्ध कराना।

मुख्यमंत्री की उक्त शक्तियों व कार्यों तथा अन्य कार्यों के क्रियान्वन हेतु मंत्रिमण्डल पूर्ण सहयोग करता है। प्रत्येक विभाग के मंत्रियों के अधीन स्थायी नौकरशाही के रूप में सचिव से लेकर अनेक कर्मचारी रहते है। मंत्रियों को हटाना, विभाग परिवर्तन करना भी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है।

वास्तविक कार्यपालिका होने से मुख्यमंत्री विधान सभा को, राज्यपाल को परामर्श देकर, समय पूर्व भंग करा सकता है। दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर विधानसभा मुख्यमंत्री को पद से, समय से पूर्व अर्थात् 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भी अपदस्थ कर सकती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद् के मध्य कड़ी का कार्य करता है। समय–समय पर राज्यपाल को शासन संबंधी निर्णयों से अवगत भी कराता है।

वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति उसके दल में उसके व्यक्तित्व, सदन में बहुमत की स्थिति, जनता में लोकप्रियता, विपक्षी दलों में स्वीकार्यता पर निर्भर करती है और इन्हीं पर कोई मुख्यमंत्री शक्तिशाली, तो कोई निर्बल मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है।

राज्य प्रशासन

राजस्थान में लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र सृजित किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान में राजस्थान को सात संभागों एवं 33 जिलों में विभक्त किया गया है, इसके निचले स्तरों पर उपखण्ड एवं तहसीलें है। इस सम्पूर्ण व्यवस्था में मुख्यमंत्री के अधीन सर्वोच्च स्तर पर **मुख्य सचिव** होता है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम् अधिकारी में से एक होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव राज्य के मंत्रिमण्डल के सचिव (कैबिनेट सचिव) के रूप में भी कार्य करता है। इनका प्रमुख कार्य मुख्यमंत्री तथा मंत्रीमण्डल को प्रशासनिक विषयों पर उचित परामर्श देना है।

राजस्थान में राज्य प्रशासन के कार्य संचालित करने हेतु विविध विभाग गठित हैं तथा प्रत्येक विभाग का प्रभारी मंत्री होता है और मंत्री की सहायतार्थ शासन सचिव रहता है। शासन सचिव मंत्रियों को नीति निर्माण में आवश्यक सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार सचिवों की सहायता से निर्धारित नीति को विभिन्न विभाग अपने निदेशालय द्वारा लागू करवाते हैं जिसका प्रमुख अधिकारी महानिदेशक/निदेशक होता है।

राजस्व एवं कानून व्यवस्था प्रशासन तंत्र

राज्य में राजस्व एवं कानून व्यवस्था के लिये एक ही प्रशासनिक तंत्र गठित किया गया है। राजस्व एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से राज्य **सात संभागों** अर्थात् **जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर** में विभक्त किया गया है। राजस्व सम्बन्धी मामलों में राज्य में सर्वोच्च निकाय **राजस्व मण्डल** है जिसका मुख्यालय अजमेर में है। प्रत्येक संभाग पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी संभागीय आयुक्त बैठता है। इनके अधीन सभी जिलों के जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक रहते हैं। इनको पुलिस एवं सामान्य विभागों में समन्वय रखते हुए सम्पूर्ण संभाग में विकास तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने के साथ, संभाग स्तर पर राजस्व सम्बन्धी मामलों का निस्तारण भी करना होता है। जिला स्तर पर कलेक्टर/मजिस्ट्रेट का पद सृजित है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। इसे पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करनी होती है। इनके अधीन प्रत्येक उपखण्ड पर उपखण्ड अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। प्रत्येक तहसील पर एक तहसीलदार होता है, जिसकी मदद के लिये नायब तहसीलदार, कानूनगों आदि होते हैं। तहसील को पटवार सर्किल में विभक्त किया जाता है, जिसका प्रमुख पटवारी होता है, एक पटवार सर्किल कई ग्रामों से मिलकर बनता है। सम्पूर्ण राजस्व एवं कानून व्यवस्था तंत्र निम्न चार्ट से स्पष्ट है–

राजस्व एवं कानून व्यवस्था प्रशासन तंत्र

राजस्व मण्डल	राज्य स्तर
संभागीय आयुक्त	संभाग स्तर
जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट	जिला स्तर
उपखण्ड अधिकारी	उपखण्ड स्तर
तहसीलदार	तहसील स्तर
नायब तहसीलदार	तहसील स्तर
पटवारी	पटवारी सर्किल

पुलिस प्रशासन

राज्य में कानून एवं शांति–व्यवस्था बनाये रखने हेतु गृह विभाग का गठन किया गया है। यह विभाग राज्य के गृह मंत्री के अधीन तथा निर्देशन में कार्य करता है। गृह मंत्री की सहायता हेतु उनके अधीन सचिवालय स्तर पर गृह सचिव होता है। पुलिस प्रशासन के मुखिया का पदनाम वर्तमान में **पुलिस महानिदेशक** (डी.जी.पी.) है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठतम् अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। पुलिस का मुख्यालय जयपुर में है।

सम्पूर्ण राज्य को पुलिस प्रशासन की दृष्टि से आठ रेंज में बांटा गया है। (**अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर रेंज–प्रथम, जयपुर रेंज–द्वितीय, जोधपुर, कोटा, उदयपुर**)। एक रेंज का आकार सामान्यतः एक संभाग के समान ही होता है। प्रत्येक रेंज का प्रमुख अधिकारी **पुलिस महानिरीक्षक** (आई.जी.) होता है, जो भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है।

प्रत्येक रेंज को जिलों में विभक्त किया गया है। पुलिस प्रशासन के जिलों की संख्या राजस्व एवं सामान्य प्रशासन की दृष्टि से निर्धारित किये गए जिलों से भिन्न होती है। जहाँ राजस्व एवं सामान्य प्रशासन की दृष्टि से राज्य में 33 जिले है, वहीं पुलिस के आन्तरिक प्रशासन की दृष्टि से कुल 38 जिले सृजित किये गए हैं। निम्न तीन जिलों में पुलिस प्रशासन की दृष्टि के अतिरिक्त जिले सृजित है : जयपुर में चार (पूर्व, उत्तर, दक्षिण, ग्रामीण), कोटा में दो (शहरी, ग्रामीण), जोधपुर में दो (शहर, ग्रामीण)।

जिला स्तर पर एक पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) होता है, जो सम्पूर्ण जिले की पुलिस का नियंत्रण करता है। जिले में पुलिस का प्रयोग जिलाधीश के निर्देशानुसार किया जाता है तथा पुलिस का आन्तरिक प्रशासन पुलिस अधीक्षक द्वारा देखा जाता है।

जिले को वृत्त (Circle) में विभक्त किया जाता है। जहाँ वृत्ताधिकारी (सी.ओ) प्रमुख अधिकारी होता है। जो सामान्यतः राज्य पुलिस सेवा (आर.पी.एस) का अधिकारी होता है। वृत्त को पुलिस थानों में बाँटा जाता है तथा पुलिस थाने के अधीन सबसे छोटी इकाई पुलिस चौकी होती है। थाने का भार सामान्यतः पुलिस निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक के पास होता है। इसके अतिरिक्त हैडकांस्टेबल, कांस्टेबल

इत्यादि होते हैं।

अन्य विभागों का भी इसी प्रकार उच्च से अधीनस्थ कड़ी जोड़ता हुआ प्रशासनिक ढाँचा रहता है। जैसे शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, वाणिज्य, उद्योग, पंचायती राज इत्यादि। समस्त प्रशासनिक विभाग मिल कर राज्य में विकास के कार्य सम्पन्न करते हैं। सभी विभागों के आपसी सामंजस्य एवं समन्वय से राज्य में जनहित के कार्य सम्पन्न किये जाते है तथा राज्य के विकास को नवीन दिशा प्रदान की जाती है।

स्थानीय स्वशासन निकाय एवं पंचायती राज

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों की राजनीतिक सहभागिता एवं स्थानीय विकास हेतु प्रायः सभी देशों में स्थानीय स्तर पर शासन के लिये स्थानीय लोगों का संगठन या निकाय बनाया जाता है और स्थानीय स्तर की विकास योजनायें तथा अन्य समस्याओं तथा जन मांगों को इसी स्थानीय शासन निकाय द्वारा पूरा किया जाता है। भारत में तीन स्तर का शासन अपनाया गया है– केन्द्रीय स्तर, राज्य स्तर तथा स्थानीय स्तर।

स्थानीय स्वशासन द्वारा स्थान विशेष के, चाहे वह नगर हो या ग्राम, जनप्रतिनिधियों द्वारा उसी स्थान के विकास कार्य किये जाते है। राज्य में नियामकीय कार्यों (राजस्व एवं कानून व्यवस्था सम्बन्धी) तथा विकास कार्यों को अलग–अलग करने का प्रयास किया गया है। जहाँ एक और जिले में नियामकीय कार्यों का दायित्व जिलाधीश तथा उससे सम्बन्धित तंत्र को सौंपा गया है। वहीं जिले में विकास कार्यों (पानी, सड़क, विद्युत, स्वच्छता इत्यादि) का दायित्व स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सौंपे जाने का प्रयास किया गया है। विकास कार्यों की दृष्टि से प्रत्येक जिले को ग्रामीण एवं नगरीय दो भागों में विभक्त किया जाता है।

स्थानीय स्वशासन निकाय भारत की तरह राजस्थान में भी दो प्रकार के हैं – नगरों के लिये नगरीय शासन तथा ग्रामों के लिये पंचायती राज शासन। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। राज्य में तीन तरह की शहरी संस्थायें हैं – नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका। वर्तमान में राजस्थान में 5 नगरनिगम, 13 नगरपरिषद तथा 170 नगरपालिका मिलाकर कुल 188 नगरीय निकाय हैं।

पंचायती राज– भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। राजस्थान में भी इसी के साथ ग्रामीण स्थानीय शासन प्रारंभ हुआ। हमारे राज्य में भी वर्तमान में तीन स्तरीय व्यवस्था प्रचलित है– ग्राम स्तर पर **ग्राम पंचायत**, खण्ड स्तर पर **पंचायत समिति** तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इन्हें संवैधानिक संस्थाओं का स्तर प्रदान किया गया तथा संविधान में ग्याहरवीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिये गये है। जिन पर ये संस्थायें कार्य करती है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषतायें –

1. **संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है**– इस अधिनियम से पूर्व तक पंचायतीराज अधिकतर राज्य सरकारों के भरोसे था, लेकिन अब संविधान में स्पष्ट स्थान व स्तर प्राप्त हो गया है। इससे सत्ता परिवर्तन का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। संविधान में (भाग 9 जोड़ा गया है तथा 16) नये अनुच्छेद जोड़े गए है।

2. **आरक्षण व्यवस्था** – वर्तमान में पंचायती राज की तीनों स्तर की संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था की गई है।

(क) अनु. जाति और अनु. जनजाति के आरक्षण – इन दोनों वर्गों हेतु प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में राज्य सरकार ने आरक्षण कर रखा है, जो बारी–बारी से आवर्तित (रोटेशन) होता रहता है।

(ख) महिलाओं के लिये आरक्षण – इस अधिनियम के तहत राज्य में महिलाओं हेतु प्रत्येक वर्ग में एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गये हैं। ये भी बारी–बारी चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षित होते हैं। राज्य सरकार ने 2009 में पंचायती राज एवं नगरीय शासन में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये थे।

(ग) पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण – पंचायती राज में पिछड़े वर्गों हेतु भी राज्य सरकार ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण रखा है, जो वर्तमान में 21 प्रतिशत है।

(घ) अध्यक्ष पदों पर आरक्षण – पंचायती राज में अब अध्यक्षों के लिये भी उक्त तीनों प्रकार का आरक्षण किया गया है।

3. **कार्यकाल** – पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल अब 5 वर्ष निश्चित किया गया है। इससे पूर्व किसी कारण से इन संस्थाओं को भंग करना पड़े, तो 6 माह के अंदर ही पुनः चुनाव करवाना अनिवार्य है। इन पंचायती राज संस्थाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।

4. **ग्राम सभा का गठन**– प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र पर एक ग्राम सभा का गठन होगा। उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क मतदाता उसके सदस्य होते है। वर्तमान में राजस्थान में वर्ष में चार बार इसकी बैठकें आहुत की जाती है जब कि दो बार, प्रत्येक वर्ष में, बैठकें अनिवार्य है।

5. **कार्य एवं शक्तियाँ** – पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर निर्णय लेकर कार्य करने की शक्तियाँ प्रदान की है।

6. **त्रिस्तरीय व्यवस्था**– प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है।

(क) ग्राम पंचायत– ग्राम पंचायत सभी वार्ड पंचों, उप सरपंच व सरपंच से मिलकर बनती है तथा एक सरकारी कर्मचारी ग्राम सचिव भी रहता है। माह में दो बार इसकी बैठक होती है।

(ख) पंचायत समिति– प्रत्येक विकास खण्ड से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य, उप प्रधान व प्रधान मिलकर खण्ड स्तर की संस्था बनाते है। इनके साथ सरकारी अधिकारी विकास अधिकारी होते है।

(ग) जिला परिषद् – पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था प्रत्येक जिला स्तर पर जिला परिषद नाम से गठित है। राज्य में इसमें जिला परिषद् सदस्य, उपजिला प्रमुख तथा जिला प्रमुख होते है तथा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहता है। सरपंच को छोड़कर शेष अध्यक्षों, उपाध्यक्षों प्रधान, उपप्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख का निर्वाचन सदस्यों द्वारा होता है।

वर्तमान में राजस्थान में 9177 ग्राम पंचायतें 248 पंचायत समितियाँ तथा 33 जिला परिषदें हैं। जिनके सदस्य व अध्यक्ष पद हेतु 21 वर्ष की आयु का सम्बन्धित क्षेत्र का मतदाता निर्वाचन लड़ सकता है।

राजस्थान में पंचायती राज का स्वरूप निम्न चार्ट से स्पष्ट हो जाता है –

पंचायती राज (ग्रामीण स्थानीय स्वशासन)

संस्था	राजनीतिक प्रतिनिधि	प्रशासनिक अधिकारी
जिला परिषद्	जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद् सदस्य	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पंचायत समिति	प्रधान, उप प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य	विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत	सरपंच, उपसरपंच एवं पंच	ग्राम सेवक

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान में एकीकरण से पूर्व रियासतें थी –
   (अ) 20 (ब) 35
   (स) 33 (द) 19

2. राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
   (अ) 5 मार्च (ब) 20 मार्च
   (स) 30 मार्च (द) 15 मार्च

3. राजस्थान एकीकरण कुल चरणों में पूर्ण हुआ–
   (अ) सात (ब) पाँच
   (स) तीन (द) चार
4. वर्तमान विधान सभा की सदस्य संख्या हैं –
   (अ) 160 (ब) 320
   (स) 200 (द) 180
5. राज्यपाल की नियुक्ति करता है–
   (अ) प्रधानमंत्री (ब) राष्ट्रपति
   (स) मुख्यमंत्री (द) मुख्य न्यायाधीश
6. मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है–
   (अ) राज्यपाल (ब) मुख्य न्यायधीश
   (स) प्रधानमंत्री (द) जनता
7. राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः होता है–
   (अ) 10 वर्ष (ब) 6 वर्ष
   (स) 3 वर्ष (द) 5 वर्ष
8. राजस्थान के कुल संभाग है–
   (अ) तीन (ब) सात
   (स) तैंतीस (द) दस
9. मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी होता है–
   (अ) मुख्य सचिव (ब) जिलाधीश
   (स) पुलिस अधीक्षक(द) संभागीय आयुक्त
10. जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है–
   (अ) संभागीय आयुक्त
   (ब) तहसीलदार
   (स) उपखण्ड अधिकारी
   (द) जिलाधीश (कलेक्टर)
11. स्थानीय स्वशासन के निकायों का कार्यकाल होता है–
   (अ) 5 वर्ष (ब) 6 वर्ष
   (स) 4 वर्ष (द) 10 वर्ष
12. पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए–
   (अ) 30 वर्ष (ब) 35 वर्ष
   (स) 21 वर्ष (द) 25 वर्ष

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण कब हुआ?
2. देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किस पर था?
3. राजस्थान को 'राजस्थान' नाम किस चरण में प्राप्त हुआ था?
4. विधायिका को और किन नामों से जाना जानते हैं?
5. विधायिका किसे कहते है?
6. सरकार के कितने अंग होते हैं?
7. राज्यपाल किस प्रकार की कार्यपालिका होता है?
8. कार्यपालिका किसे कहते है?
9. वास्तविक कार्यपालिका किसे कहा जाता है?
10. मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है?
11. पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता है?
12. पुलिस उप–अधीक्षक किस सेवा से बनते है?
13. भारत में लागू शासन के तीनों स्तरों के नाम लिखो?
14. राज्य में शहरी स्वशासन निकाय कितने तरह के होते हैं? नाम लिखो।
15. राजस्थान में पंचायती राज कौन–कौन से स्तर पर क्या कहलाता है?
16. राज्य में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. राजस्थान राज्य के एकीकरण के प्रथम चरण को समझाइये।
2. राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।
3. राज्यपाल की प्रमुख शक्तियाँ कौन–कौन सी हैं?
4. मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया बताइये?
5. मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिये?
6. राज्य के सामान्य प्रशासन का वर्णन कीजिये?
7. पुलिस प्रशासन को उच्च अधीनस्थ क्रम से समझाइये।
8. स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं?
9. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषतायें बताइये।
10. राजस्थान के स्थानीय पंचायती राज में आरक्षण व्यवस्था का वर्णन करो।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया का चरणबद्ध वर्णन कीजिये।
2. राजस्थान में व्यवस्थापिका के स्वरूप का विवेचन कीजिये।
3. राज्य में कार्यपालिका के स्वरूप एवं कार्यों को स्पष्ट कीजिये।
4. राजस्थान के राजस्व एवं कानून व्यवस्था तंत्र का वर्णन कीजिये।
5. राजस्थान में पंचायती राज के स्वरूप पर एक निबंध लिखिये।

❑❑❑❑

अध्याय–6
जल संरक्षण : आज की आवश्यकता

जल प्रकृति से विरासत में मिला वह संसाधन है जो सम्पूर्ण जीव जगत का आधार है। जल के बिना जीव जगत की कल्पना ही व्यर्थ है। वस्तुतः जल ही जीवन है।

जल संरक्षण की आवश्यकता :

भूमण्डल पर दृष्टि डालने पर पृथ्वी के 70% भाग पर पानी दृष्टिगोचर होता है किन्तु पृथ्वी पर उपलब्ध जल का .007% हिस्सा अर्थात एक लाख लीटर पानी में से 7 लीटर पानी ही मानव के लिए उपयोगी है, शेष पानी या तो समुद्री जल के रूप में या ग्लेशियर के रूप में जमा है। सारे विश्व मे जल का संकट है किन्तु भारत की स्थिति अधिक गंभीर है क्योंकि यहां दुनिया की 16% आबादी निवास करती है जबकि पानी केवल 4% ही उपलब्ध है।

राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है तथा भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग धारण करता है उसमें भारत का मात्र 1% जल उपलब्ध है। राजस्थान के अलग–अलग भागों में जल का वितरण भी असमान है।

राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ अत्यधिक विषम है यहाँ वार्षिक औसत वर्षा सबसे कम तो है ही बारह मास बहने वाली नदियों का अभाव है तथा राजस्थान का पश्चिमी भाग 'मरूभूमि' तो सदियों से अकाल और सूखे की चपेट में रहा है। यहाँ दूर–दूर तक पानी के दर्शन नहीं होते है तथा कई स्थानों पर बच्चों ने वर्षो तक वर्षा नहीं देखी होती है। भूमिगत जल स्त्रोतों में नाममात्र का उपलब्ध जल सीमित उपयोग द्वारा ही भविष्य के लिए बचाया जा सकता है।

राजस्थान की 90% आबादी पेयजल के लिये भूजल स्त्रोतों पर निर्भर है तथा कृषिकार्य हेतु 60–70% भू जल स्त्रोतों का उपयोग होता है। राजस्थान में विगत 60 वर्षो में भू जल स्त्रोतों के अंधाधुंध दोहन से ये भंडार जो हजारो वर्षों में एकत्र हुए थे खाली होते जा रहे है। सतही पानी के स्त्रोत नदी, झील, तालाब आदि संकटपूर्ण स्थिति में है। पर्यावरणीय कारण जैसे ग्लोबल वार्मिग एवं मनुष्य जनित कारण जैसे बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण के कारण सतह के जल स्त्रोत अपना अस्तित्व खोते जा रहे है पानी के अंधाधुंध दोहन के कारण जमीन के नीचे के भंडार तो खाली हो रहे है नदियाँ भी वर्षा के कुछ माह बाद ही सूख जाती है नदियों के जल प्रवाह में लगातार कमी आती जा रही है सिंचाई और घरेलू इस्तेमाल के लिये नदियों से पानी का दोहन कई गुणा बढ़ गया है। शहरी जनसंख्या हेतु दूर से किसी नदी का पानी लाकर शहरों की प्यास बुझाने का कार्य किया जा रहा है किन्तु इस हेतु बड़े बाध एवं बड़ी नहरें बनाना भावी जल संकट का स्थायी समाधान नहीं है क्योंकि जब तक जल की बर्बादी पर प्रभावी रोक नहीं होगी आसानी से नाममात्र के मूल्य पर सरकार द्वारा उपलब्ध करवायें जा रहे जल का आम जनता मूल्य नहीं समझ सकेगी। जल की बर्बादी रोकने से अभिप्राय यह नहीं कि हम लोगो को जल न पीने दे बल्कि संरक्षण है अर्थात् जल की अच्छी प्रकार से रक्षा है अतः जल का विवेकपूर्ण व समुचित उपयोग ही संरक्षण है।

मानव द्वारा जल संसाधनों के अत्यधिक एवं अविवेकपूर्ण दोहन एवं जल स्त्रोतों की दुर्दशा का सर्वाधिक नुकसानदायी दुष्प्रभाव जल प्रदूषण के कारण जीव जन्तुओं एवं वनस्पति पर पड़ा हैं किन्तु इसके दुष्प्रभाव से स्वयं मानव भी बच नहीं सका है, प्रदूषित पानी से प्रति वर्ष भारत में एक लाख लोगों की मृत्यु हो रही है।

मानव जिस जल को प्राचीन काल से देवता एवं जल स्त्रोतों को पवित्र मानता आ रहा है आधुनिक जीवन शैली, शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण द्वारा प्रदूषित कर अपने ही वर्तमान एवं भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

जल की कमी के दुष्प्रभाव :

जल का मानव जीवन के सभी पक्षों यथा सिंचाई, कृषि, खाद्यान्न उत्पादन, उद्योग, निर्माण, पर्यटन, सांस्कृतिक जीवन, जीवनयापन आदि सभी क्षेत्रों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है जल के अभाव में मानव पशु–पक्षी जीव जन्तु वनस्पति किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है जल की कमी मानव एवं समस्त जैव जगत के अस्तित्व को प्रभावित करती है।

जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में (60–70)% उसके पश्चात् उद्योगों एवं कारखानों में (15–20)% तथा तीसरे स्थान पर घरेलू क्षेत्र में उपयोग होता है

जल की कमी के कारण :

शुद्ध पेयजल की पूरे विश्व में कमी है जिसके सामान्य कारण निम्न है।

1. आबादी में वृद्धि : बढ़ती आबादी हेतु अधिक पानी, भोजन, कृषि कार्यों एवं औद्योगिक इकाईयों द्वारा पानी का अधिक उपयोग प्रमुख कारण है।

2. असमान वितरण : भौगोलिक रूप से सभी स्थानों पर वर्षा का वितरण समान नहीं होता है। भारत में मानसूनी वर्षा का अधिकांश भाग अन्ततः समुद्र मे जा गिरता है तथा कई स्थान उसी समय सूखा ग्रस्त होते हैं।

3. बांध एवं एनीकट : कृषि कार्य एवं औद्योगिक उपयोग हेतु जल भंडारण के उद्देश्य से बांध बनाये गये किन्तु बांधों में मिट्टी के भराव से उनकी क्षमता धीरे–धीरे कम हो जाती है तथा कई स्थानों पर बांधो के टूटने से विनाशलीला भी होती है।

4. पानी का अधिक उपयोग : पानी के अधिक उपयोग ने पानी का अभाव उत्पन्न किया आधुनिक जीवन शैली, टब बाथ व्यवस्था, फ्लश शौचालय, खुले नलों पर नहाना अथवा कपड़े धोना या दांत मॉंजना, वॉशिंग मशीन एवं डिटरजेन्ट पाउडर का उपयोग आदि में पानी अधिक व्यय होता है।

प्रति मनुष्य प्रतिदिन जल का खर्च :

1. दांत मॉंजना 2–8 लीटर
2. शौचालय फ्लश 15–40 लीटर
3. नलो का रिसना 10 लीटर
4. खुले नल के नीचे हाथ धोना 2–8 लीटर
5. बर्तन धोना 10–20 लीटर
6. कपड़े धोना 20–40 लीटर
7. शॉवर या बाथटब 20–200 लीटर
8. सफाई करना 15–20 लीटर
9. पीने के लिये पानी 3–6 लीटर
10. अन्य खर्च 10 लीटर

सामान्य व्यय 100 लीटर धनी वर्ग / बाथटब संस्कृति 360 लीटर से 400 लीटर

5. **जल प्रदूषण** : उद्योगों से अपशिष्ट जल, जिनमे अनेक प्रकार की अशुद्धियॉं होती है सीधे ही पीने के पानी के स्त्रोतों में छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार घरेलू अपशिष्ट भी नाली के रास्ते किसी पानी के स्त्रोत में जा मिलते है, इससे वे स्त्रोत जो लोगों के पीने के पानी की पूर्ति करते है वे उपयोग लायक नहीं रहते तथा उनका उपयोग बन्द हो जाता है जिससे पानी का अभाव हो जाता है।

6. **वर्षा के पानी का उपयोग नहीं होना** : वर्षा का जल बिना किसी उपयोग के समुद्र में चला जाता है, यदि इस जल का प्रभावी संचय किया जाता तो कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

राजस्थान की परिस्थितियों में सभी क्षेत्रों में विकास एवं वृद्धि के लिये जल संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था एवं जनता का बड़ा भाग कृषि एवं पशुपालन से जुडा है तथा औद्योगिक विकास वर्तमान की आवश्यकता है। इन सभी क्षेत्रो के लिये जल की लगातार उपलब्धता अत्यावश्यक है साथ ही जनसंख्या के अधिकांश भाग को आवश्यकतानुसार स्वच्छ पेयजल मिल सके, इस हेतु सरकार एवं समाज के सभी वर्गों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपयोगी कदम उठाने चाहिए।

जल संरक्षण के उपाय :

जल का जीवन के जिन क्षेत्रों मे उपयोग हो रहा है वहां उचित एवं मितव्ययततापूर्ण उपयोग कर बचाया जा सकता है। इस हेतु किये जाने वाले उपायो को सुविधा हेतु निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :–

1. सरकार के स्तर पर किये जाने वाले उपाय
2. सामाजिक स्तर पर
3. घरेलू स्तर पर
4. औद्योगिक इकाइयों द्वारा
5. स्थानीय शासन द्वारा
6. कृषि के क्षेत्र मे

1. सरकार के स्तर पर किये जाने वाले उपाय :– सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना प्राथमिक कार्य हैं। इस हेतु 1986 मे राष्ट्रीय पेयजल मिशन स्थापित किया गया, जिसमे देश में उपलब्ध जल को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल, कृषि, जल विद्युत, जल परिवहन, उद्योग आदि में प्रयुक्त किये जाने का निश्चय किया।

जल संरक्षण के लिये आवश्यक है कि सरकार जल निकायों जैसे बांध, नहरों आदि की समयानुसार मरम्मत, नवीनीकरण कराये, जल निकायों की भंडारण क्षमता मे वृद्धि करें, भूजल पुनर्भरण हेतु नयी प्रविधियों की उपलब्धि करावे। शहरी क्षेत्रों में जल की बर्बादी एवं अनियंत्रित प्रयोग को रोकने के लिये कानून बनाये जल प्रदूषण रोकने के लिये तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित करावें, कृषि/उद्यान कृषि उत्पादकता मे सुधार हेतु प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

राजस्थान सरकार ने "जल संरक्षण" कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त सरकारी भवनों में वर्षा जल संचय अनिवार्य किया है साथ ही भूजल भंडारों के पुनर्भरण हेतु वर्षा जल पुनर्भरण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इस में एक छत के बरसाती पानी को गड़ड़े या खाई के जरिये सीधे जमीन के भीतर उतारा जाता है या छत के पानी को किसी टैंक मे एकत्र कर सीधा उपयोग किया जाता है। छत के पानी को हेंड पम्प, बोरवेल या कुएं के माध्यम से भी भूगर्भ में ड़ाला जा सकता है।

2. सामाजिक स्तर पर किये जाने वाले उपाय : जल संरक्षण या कोई भी जन जाग्रति कार्यक्रम समाज के सभी वर्गो के योगदान के बिना अधूरा है। समाज के जागरूक वर्ग को जल की सीमितता एवं जल संकट के खतरों से सभी वर्गों को जागरूक करना चाहिए। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों को जिला एवं राज्यस्तर पर जल के बुद्धिमत्तपूर्ण उपयोग के लिए जल, जंगल, जमीन के परंपरागत रिश्ते को पुनर्जीवित करना चाहिए, ताकि सूखी नदियॉं पुनः जल से भरी बह सके एवं वर्षा जल से भूजल स्त्रोतों का पुनर्भरण हो सके।

3. घरेलू स्तर पर किये जाने वाले उपाय : आधुनिक जीवन शैली के कारण जल का भारी मात्रा में अपव्यय हो रहा है। मितव्ययतापूर्ण एवं विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा व्यक्ति आसानी से प्रतिदिन 200 लीटर तक जल बचा सकता है। जल के उपयोग में सावधानी द्वारा व्यक्ति जल बचा सकता है इस हेतु निम्न उपाय घरेलू सतर पर किये जा सकते है

1. दंत मंजन के समय नल खुला रखने के बजाय मग का उपयोग।
2. नहाने में शॉवर या बाथटब के बजाय बाल्टी मग का प्रयोग।
3. नल खुला रख कर हाथ न धोए।
4. फर्श को धोने की बजाय बाल्टी में पानी भरकर पौंछा लगाना।
5. शौचालय मे फ्लश चलाने के बजाय छोटी बाल्टी काम मे लें।
6. मग मे पानी लेकर शेव बनाना।
7. पाईप की बजाय बाल्टी में पानी लेकर वाहन को धोये या पोंछे।
8. बर्तन धोते समय लगातार नल न चलाये या पानी से भरे बड़े बरतन (बेसिन) में बर्तन धोए।
9. पानी पीते समय गिलास को झूठा न करें बल्कि ऊपर से पानी पिए जिससे बार–बार धोने में लगने वाला पानी बचेगा।
10. वाशिंग मशीन से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल वाहनों को साफ करने, छत, आंगन को धोने में करें।
11. किचन, बाथरूम से निकलने वाले पानी को पुनर्चक्रीकृत कर बगीचे मे काम में ले।
12. घर के बगीचे में कम पानी की जरूरत वाले पौधे लगायें।
13. घास को अधिक पानी की जरूरत होती है लॉन संस्कृति को कम अपनायें।

14. नल अच्छी तरह बंद करे लीकेज होने पर तुरन्त ठीक करायें।
15. सब्जियों को सीधे नल के नीचे धोने की बजाय किसी बर्तन मे धोया जाय।
16. छत के पानी वर्षा जल को टैंक में एकत्र किया जाये या भूमि में उतारा जायें।

4. औद्योगिक इकाइयों द्वारा किये जाने वाले उपाय : औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध जल का 15–20% जल प्रयुक्त किया जाता है, उद्योगों मे पानी का विविध उपयोग होता है। शुद्ध पानी को औद्योगिक संयंत्र दूषित अथवा प्रदूषित कर बाहर निकालते है यह प्रदूषित जल उपचारित कर पुनः संयंत्र को ठंडा करने या पेयजल के अतिरिक्त अन्य कार्यो में उपयोग जैसे बाग–बगीचे का रखरखाव साफ–सफाई आदि में या ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त किया जाय। उत्पादन में इस प्रकार की प्रौद्योगिकी काम में ली जाय जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो।

5. स्थानीय शासन द्वारा किये जाने वाले उपाय
शहरी इलाकों में रोजाना सप्लाई किए जाने वाले करोड़ों लीटर पानी का हिस्सा इस्तेमाल के बाद नालियों (सीवरेज) मे बहा दिया जाता है, अगर स्थानीय शासन इस हिस्से को पुनर्चक्रीकृत/उपचारित कर उपयोग मे ले तो पानी की बड़ी बचत हो सकती है। यह पानी नहाने, हाथमुँह, कपड़े धोने, साफ सफाई और बर्तन आदि धोने में तथा बाग बगीचों में प्रयुक्त किया जा सकता है।

स्थानीय स्वायतशासी निकाय बहुमंजिली इमारतों एवं घरों के निर्माण की स्वीकृति से पूर्व इमारत में टांका निर्माण या वर्षा जल द्वारा भूजल पुनर्भरण के लिये अनिवार्यता लागू कर सकता है।

शहरों एवं गांवों में गैर जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा अवैध जल कनेक्शन लेने, जलापूर्ति के समय घरों मे अवैध बूस्टर लगाकर अधिक पानी खीचने, मापदण्डों से बड़ी पाईप लाईन के जरिये अधिक जल भंडारण एवं दुरूपयोग करने वालो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। पानी की पाईप लाईन से होने वाले रिसाव को रोके, स्थानीय स्तर पर पुराने जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किये जाय। कुओं और तालाबों की नियमित सफाई हो तथा तालाबों की मिट्टी को नियमित रूप से निकाला जाय।

6. कृषि के क्षेत्र में किये जाने वाले उपाय :
राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ पर उपलब्ध जल का 60–70% कृषि क्षेत्र मे प्रयुक्त किया जाता है। कृषक अपने खेत में आये वर्षा जल को मेड़ बनाकर रोके तथा किसी उचित स्थान पर पक्का या कच्चा टांका निर्माण कर वर्षा के जल को भूजल स्त्रोत के पुनर्भरण हेतु प्रयुक्त करे इस हेतु 1 (i) सीधे जमीन में गड्ढे के जरिये या (ii) खाई बनाकर भूगर्भीय जल भंडार में उतार सकता है या (iii) कुओं के जरिये यह कार्य किया जा सकता है। (iv) ट्यूबवेल में एक विशेष फिल्टर लगाकर पाईप के जरिये पानी उतारा जा सकता है। (v) छत या खेत के पानी को सीधे किसी टैंक मे जमा कर सकता है।

2. राज्य की परिस्थिति के अनुरूप कम जल खपत वाली फसले बोयें।
3. गेहूँ, चावल, गन्ना जैसी नगदी फसलों के स्थान पर कम जल खपत वाली फसलो का उत्पादन लें।
4. फव्वारा सिंचाई एवं बूंद–बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग करें।
5. जल संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे नवीन अनुसंधान को कृषि के क्षेत्र में शीघ्रता से लागू करें।

7. जल संरक्षण में विद्यार्थियों का योगदान :
विद्यार्थी वर्ग समाज का बड़ा वर्ग है तथा अपने आस–पास की अच्छी जानकारी उसके पास होती है। जल के बुद्धिमतापूर्ण उपयोग की क्यों आवश्यकता है ? यह बात यदि वह समझ जाता है तो वह भविष्य में आने वाले भीषण जल संकट से बचाव हेतु अपना सक्रिय योगदान दे सकता है। परिवार, पास–पड़ौस, ग्राम, नगर में होने वाले जल के अपव्यय, जल प्रदूषण, जल के दुरूपयोग को रोकने हेतु, पीने के जल स्त्रोतों के आस–पास स्वच्छता बनाये रखने हेतु, वृक्षारोपण हेतु समाज के सभी स्तरो पर जागरूकता उत्पन्न कर सकता है। इस हेतु वह विद्यालय में अर्जित ज्ञान एवं संचार माध्यमों से प्राप्त जानकारी सरल एवं सहज रूप से जन–जन तक पहुँचा कर जल संरक्षण के कार्य को मूर्त रूप दे सकता है। विद्यार्थी स्वयं के उदाहरण द्वारा जल संरक्षण हेतु व्यक्ति को क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए का ज्ञान समाज के सभी वर्गों को करा सकता है।

जल जीवन की एक बुनियादी जरूरत है जल संरक्षण से व्यक्ति परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का हित जुड़ा है इस अभियान में भागीदारी द्वारा हम एक राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने में सहयोग दे सकते है सभी को पेयजल पहुँचाने और जल समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार तो लगातार प्रयत्नशील है किन्तु जल की एक भी बूंद व्यर्थ न बहाने का हम सभी का संकल्प भावी जल संकट का समाधान है। इसके बारे में बड़े बुजुर्गो, बच्चों, पास–पड़ौसियों, मित्रों, समूहों से चर्चा कर उन्हें जल की बचत एवं संरक्षण के लिये जागरूक बनाना समय की मांग है। आइये हम सब मिलकर ''जल संरक्षण अभियान'' की सफलता के लिए काम करें।

जल संरक्षण कुछ तथ्य :

1. राजस्थान के 236 ब्लाक में से 140 में भूमिगत पूर्णतया समाप्त (डार्कजोन), 50 जोन में स्थिति गम्भीर (ग्रे जोन) है।
2. राजस्थान के भूजल भंडार में से 27 जिलो में अत्यधिक खारापन, 30 जिलों में अत्यधिक फ्लोराइड, 28 जिलों में अत्यधिक लौहयुक्त तत्व है।
3. 2030 तक कृषि के लिए आज की तुलना में और 13% पानी की जरूरत होगी।
4. 2030 तक हिमालय से मिलने वाले जल में 20% कमी हो सकती है।
5. कुल पानी का लगभग 2.5% वाष्पीकरण की भेंट चढ़ जाता है।
6. संयुक्त राष्ट्र जल उपलब्धता मानकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम 50 लीटर पानी मिलना चाहिए।
7. भारतीय पैमाने के अनुसार 85 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी मिलना चाहिए।
8. एक हजार वर्गफीट की छत से एक बरसाती मौसम में लगभग एक लाख लीटर पानी जमीन के भीतर उतारा जा सकता है।
9. जमीन के नीचे पानी कम होने से उसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती हैं वर्षा जल पुनर्भरण द्वारा यह समस्या हल की जा सकती है।
10. दुनिया में 1.20 अरब लोगों को रोजाना पानी के लिये संघर्ष करना पड़ता है।
11. दुनियाँ के सबसे अधिक 22 लाख ट्यूबवेल भारत में है।
12. विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

1. राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है।

(अ) कृषि (ब) उद्योग
(स) घरेलू उपयोग (द) सभी में समान

2. पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल का कितने प्रतिशत है।

(अ) 1% (ब) .007%
(स) 3% (द) .7%

3. संसार में सबसे अधिक टयूबवेल किस देश में है।

(अ) चीन (ब) भारत
(स) अमेरिका (द) आस्ट्रेलिया

4. जल दिवस मनाया जाता है।

(अ) 5 जून (ब) 24 अक्टूबर
(स) 10 दिसम्बर (द) 22 मार्च

अति लघुत्तरात्मक प्रश्न :

1. भारतीय मानदण्डानुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी मिलना चाहिए।
2. भूजल स्त्रोतों का जल स्तर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौनसा है।

लघुत्तरात्मक प्रश्न :

1. वर्षा जल एकत्र करने की विधि बताइयें।
2. औद्योगिक इकाईयों द्वारा जल संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है।

निबन्धात्मक प्रश्न :

1. पानी का घरेलू दुरूपयोग किस प्रकार से होता है ? इसे रोकने के उपाय बताईयें।
2. जल संरक्षण में विद्यार्थी किस प्रकार अपना योगदान दे सकते है।
3. जल की कमी के कारणो का वर्णन करों।

❑❑❑❑